



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 6 जून, 2025

ज्येष्ठ 16, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

विद्युत नियामक भवन, विभूति खण्ड

गोमती नगर, लखनऊ-226010

संख्या यू0पी0ई0आर0सी0/डी(टी)/जेडी(पारेषण)/156-012

लखनऊ, दिनांक 06 जून, 2025

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 181 सह-पठित धाराओं 36, 39, 40, 41, 61, 62, 64, 65 तथा धारा 86 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त इसे सक्षम करने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग निम्नलिखित विनियमावली बनाता है। पारेषण प्रशुल्क के निर्धारण तथा पारेषण से संबंधित सभी पहलुओं के उद्देश्य के लिए यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण एवं पारेषण के लिए बहुवर्षीय प्रशुल्क) विनियमावली, 2019 एवं इसके संशोधन का अधिक्रमण करेगी।

1- संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रयोज्यता एवं प्रारम्भ

(1) इस विनियमावली को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के लिए बहुवर्षीय टैरिफ) विनियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(2) इस विनियमावली का विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह विनियमावली राज्य पारेषण सुविधा (एस0टी0यू0) एवं उन पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू होगी, जिनका प्रशुल्क सकल राजस्व आवश्यकता (ए0आर0आर), वार्षिक निष्पादन समीक्षा (ए0पी0आर) प्रशुल्क तथा सत्यापन का अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत निर्धारण किया जाना है:

परंतु कि इस विनियमावली का खंड 4 टीबीसीबी पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू होगा, और टीएसए/संयोजन/कार्यान्वयन अनुबंध, या पक्षों के बीच किसी अन्य अनुबंध के समसीम प्राविधानों की अनुपस्थिति में, इस विनियमावली के खंड 8 एवं 9 टीबीसीबी पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कम्पनियों पर भी लागू होंगे:

परंतु कि किसी मौजूदा जनरेटर की समर्पित ट्रांसमिशन लाइन/प्रणाली की टैरिफ इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार, जहाँ भी लागू हो, और आयोग द्वारा समय-समय पर अपने आदेशों में अपनाई गई विधि के अनुसार निर्धारित की जा सकती है।

(4) यह विनियमावली अप्रैल 01, 2025 से प्रवृत्त होगी, एवं जब तक आयोग द्वारा इसकी समय-पूर्व समीक्षा नहीं की जाती या इसे बढ़ाया नहीं जाता, यह पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी:

परंतु कि सभी उद्देश्यों के लिए, एएआर, एपीआर, सत्यापन तथा संबंधित मामलों, जिसमें समीक्षा मामले भी शामिल हैं, संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए, उस विशिष्ट वर्ष के लिए अनुप्रयोज्य संबंधित प्रशुल्क विनियमावली द्वारा अधिचालित होगी।

2-परिभाषाएं

(1) इस विनियमावली में, जब तक अन्यथा सन्दर्भित न हो, —

(a) **“लेखा विवरण”** से तात्पर्य, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित से है:—

(i) यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के परिशिष्ट-3 में भाग-1 में समाहित प्रपत्र के अनुसार अंकेक्षित तुलन-पत्र।

(ii) यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के परिशिष्ट-3 में भाग-1 में समाहित अपेक्षाओं का अनुपालन में अंकेक्षित लाभ-हानि खाता।

(iii) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के धनापूर्ति विवरण (आई0एन0डी0ए0एस0-3) पर लेखा मानकों (एकाउन्टिंग स्टैन्डर्ड) अनुसार तैयार किया धनापूर्ति विवरण।

(iv) लाइसेंसधारी के साविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट।

(v) यथा संशोधित नियत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (घ) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा नियत लागत अभिलेख, यदि कोई हो।

(vi) टिप्पणियों के साथ ऐसे अन्य समर्थनकारी विवरण और सूचनायें भी जैसा आयोग द्वारा समय-समय पर निर्देशित की जायें।

(vii) वर्ष विशेष के लिए शेष-परीक्षण जो वित्तीय विवरणों के अनुकूल हो।

(b) **“अधिनियम”** का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) से है;

(c) **“अतिरिक्त पूंजीकरण”** का तात्पर्य पारेषण प्रणाली के वाणिज्यिक प्रचालन के दिनांक के पश्चात् वास्तव में उपगत, तथा विवेकपूर्ण जाँच के पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकृत पूँजी व्यय से है;

(d) **“सकल राजस्व आवश्यकता”** का तात्पर्य पारेषण लाइसेंसधारी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता से है, (अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष के लिए उसके लाइसेंस व्यवसाय से सम्बंधित अनुमन्य व्यय और साम्या पर वापसी) जिसे इस विनियमावली के अनुसरण टैरिफ एवं प्रभारों के माध्यम से वसूल किया जाना है;

(e) **“आवंटन विवरण”** का तात्पर्य लाइसेंसधारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रत्येक व्यवसाय के लिए इसकी आस्तियों के अनुकूलतम उपयोग के विवरण से है, जिसमें किसी राजस्व, लागत, आस्ति, देयता, रिजर्व, प्रावधान की राशि प्रदर्शित की गयी है जो या—

(i) अनुज्ञप्तिधारी के विभिन्न व्यवसायों के बीच प्रभाजन अथवा आवंटन द्वारा निर्धारित की गई हो तथा प्रभाजन अथवा आवंटन के आधार का विवरण हो।

(ii) उस प्रभार के आधार के विवरण के साथ सम्बंधित दूसरे व्यवसाय पर या को प्रभारित।

(f) **“उपलब्धता”** से तात्पर्य किसी प्रदत्त समय के लिए किसी पारेषण प्रणाली के संबंध में घंटों की अवधि से है जिसमें पारेषण प्रणाली अपने नियत वोल्टेज, जो प्रदत्त अवधि के घंटों की प्रतिशतता में व्यक्त हुआ हो, विद्युत पारेषण में सक्षम हो और इसकी गणना इस विनियमावली के परिशिष्ट-ग के अनुसार होंगी;

(g) **“आधार वर्ष”** से तात्पर्य नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के ठीक पहले के वित्तीय वर्ष से है और जो इस विनियमावली, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रयोज्य है;

(h) **“बैंक दर”** से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित बैंक दर से है;

(i) **“थोक विद्युत पारेषण अनुबंध”** से तात्पर्य ऐसे निष्पादित अनुबंध से है जिसमें वे निबंधन एवं शर्तें निहित हैं जिसके अंतर्गत कोई पारेषण प्रणाली प्रयोक्ता किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली को अभिगम करने का स्वत्वाधिकारी है;

(j) **“प्रतिस्पर्धी बोली”** से तात्पर्य उपकरण, सेवाओं तथा संकर्म की खरीद की एक पारदर्शी प्रक्रिया से है जिसमें परियोजना विकासकर्ता द्वारा खुली निविदा के माध्यम से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं जिसमें परियोजना के लिए अपेक्षित उपकरण, सेवाओं तथा संकर्म के कार्य-क्षेत्र तथा विनिर्देश, प्रस्तावित

संविदा के निबंधन एवं शर्तों तथा वे मापदंड जिन पर बोलियों का मूल्यांकन होगा, अन्तर्निहित होंगे, और जिसमें देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियां शामिल रहेंगी;

(k) **“विधि में परिवर्तन”** से तात्पर्य निम्न में से किसी घटना के घटित होने से है –

- (i) अधिनियमन, जिससे कोई नई भारतीय विधि प्रभाव में लाई जाती या रूखापित होती हो; अथवा
- (ii) किसी वर्तमान भारतीय विधि का अभिग्रहण, संशोधन, उपांतरण, निरसन या पुनराधिनियमन; अथवा
- (iii) न्यायिक उद्घोषणा, केंद्र एवं/या राज्य सरकार का कोई आदेश; अथवा
- (iv) किसी सक्षम न्यायालय, अधिकरण अथवा उपकरण द्वारा किसी भारतीय विधि की व्याख्या या अनुप्रयोग में परिवर्तन जो विधि के अंतर्गत ऐसी व्याख्या या अनुप्रयोग के लिए अंतिम प्राधिकारी हो; अथवा
- (v) किसी परियोजना के लिए उपलब्ध या प्राप्त कोई सहमति, समाशोधन या अनुमोदन या अनुज्ञप्ति की शर्तों या प्रसंविदा में किसी सक्षम सांविधिक प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन; अथवा
- (vi) भारत सरकार तथा किसी अन्य संप्रभु सरकार के बीच किसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अनुबंध या संधि के प्रभावी होने या उसमें परिवर्तन, जिसका इस विनियमावली के अंतर्गत विनियमित पारेषण प्रणाली पर निहितार्थ हो; अथवा
- (vii) जब तक कि इस विनियमावली में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी कर या शुल्क का समावेशन या ऐसे कर या शुल्क में कोई परिवर्तन।

(l) **“आयोग”** से तात्पर्य तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है।

(m) **“कार्यभार संचालन विनियमावली”** से तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्यभार संचालन) विनियमावली, 2019 तथा इसमें परवर्ती संशोधनों/अधिशेषों/इसके निरसन के पश्चात् इसके पुनः-विनियमन से है;

(n) **“नियंत्रण अवधि”** से तात्पर्य 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक की पांच वर्षों की अवधि से है, जब तक कि इसे आयोग द्वारा बढ़ाया न जाए;

(o) **“संयोजन अनुबंध”** से तात्पर्य समय-समय पर यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आंतर-राज्यीय प्रणाली को संयोजन का अनुदान) विनियमावली, 2010 से है;

(p) **“निर्दिष्ट तिथि”** से तात्पर्य परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन तिथि के बारह महीने उपरांत समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से है;

(q) **“वाणिज्यिक परिचालन तिथि”** से तात्पर्य उस तिथि के 00:00 घंटे से है जो विनियम द्वारा, प्रेषक छोर से प्राप्ति छोर तक विद्युत पारेषण एवं संचार सिग्नल के सफल आवेषण और परीक्षण प्रचालन के पश्चात् जिस पारेषण प्रणाली के अवयव के नियमित सेवा में होने के बारे में घोषित है:

परंतु कि यदि पारेषण लाइन या उपकेंद्र किसी विशेष उत्पादन केंद्र से विद्युत निकासी के लिए समर्पित है तो उत्पादक कम्पनी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारक, यथा-साध्य, उत्पादन केंद्र तथा पारेषण लाइन को एक साथ चालू करने का उद्योग करेंगे और इसे उपयुक्त कार्यान्वयन अनुबंध के द्वारा सुनिश्चित करेंगे:

परंतु कि यह भी कि यदि कोई पारेषण प्रणाली या उसका कोई अवयव नियमित सेवा नहीं दे पाती जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारक या उसके आपूर्तिकर्ता या ठेकेदारों पर आरोपित नहीं किया जा सकता परंतु जो संबंधित उत्पादन केंद्र अथवा धारा-प्रतिकूल या धारा-अनुकूल के प्रारंभ होने में विलम्ब के कारण है, तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारक ऐसे पारेषण प्रणाली या उसके अवयव के वाणिज्यिक परिचालन तिथि के अनुमोदन के लिए एक उपयुक्त आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रस्ताव देगा:

परंतु कि यह भी कि किसी वर्तमान पारेषण प्रणाली के मामले में ऐसा अनुरोध इस विनियमावली के अंतर्गत दाखिल किए जाने वाले वार्षिक राजस्व आवश्यकता याचिका या वार्षिक निष्पादन समीक्षा याचिका या सत्यापन याचिका में भी सम्मिलित कर सकता है;

(r) **“वितरण अनुज्ञप्ति-धारक”** से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (ख) के अंतर्गत अनुज्ञप्ति दी गई हो और जिसमें एक मानित अनुज्ञप्तिधारक भी शामिल है;

(s) **“अपरिहार्य घटना”** से, इस विनियमावली के उद्देश्य के लिए, तात्पर्य निम्न-उल्लिखित, किंतु उसी तक सीमित नहीं, ऐसी घटना या परिस्थिति अथवा घटना या परिस्थिति के संयोजन से है जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारक को पूंजी निवेश अनुमोदन/संविदा अनुबंध में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, पूर्ण या आंशिक रूप से परियोजना को पूरा करने से रोकती है अथवा इसे अपरिहार्य रूप से विलम्बित करती है,

मात्र तभी जब ऐसी घटनाएं या परिस्थितियां पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के नियंत्रण के बाहर हों और यदि पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा युक्तियुक्त सावधानी बरतने अथवा विवेकशील सेवाधारिता व्यवहार के बावजूद उनका परिहार संभव नहीं था—

- (i) ईश्वरीय कृत्य, जिसमें सम्मिलित हैं पर उन्हीं तक सीमित नहीं, तड़ित, दुर्भिक्ष, अग्निकांड तथा विस्फोट, भूकंप, ज्वालामुखीय प्रस्फुटन, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, तूफान, बवंडर, भूगर्भीय अप्रत्याशित घटना; या
- (ii) युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष का कोई कृत्य, यह किसी विदेशी शत्रु का कोई कृत्य, संरोध, व्यापार प्रतिरोध, क्रांति, दंगा, राजद्रोह, आतुकी या सैन्य कार्यवाही; या
- (iii) पूरे उद्योग में हड़ताल और श्रमिक अशांति जिसका भारत में देश-व्यापी प्रभाव हो;
- (iv) परियोजना के लिए सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब जो अनुज्ञप्तिधारक पर आरोपित नहीं किया जा सकता;
- (v) परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में विलम्ब जो अनुज्ञप्तिधारक पर आरोपित नहीं किया जा सकता;
- (t) **“कार्यान्वयन अनुबंध”** से तात्पर्य, एक समन्वित रूप में, उत्पादन एवं पारेषण परियोजना के अंतर-संयुज्य/संबद्ध पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए उत्पादन कम्पनी तथा/अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारक (कों) के मध्य प्रविष्ट किसी बहुपक्षीय अनुबंध या प्रसंविदा से है;
- (u) **“भारत सरकार का उपकरण”** से तात्पर्य भारत सरकार या राज्य सरकार(रों) या दोनों के प्रत्यक्ष: अथवा अप्रत्यक्ष: अधीन किसी मंत्रालय, विभाग, बोर्ड, प्राधिकरण, अभिकरण, निगम, तथा आयोग, एवं उपयुक्त आयोग(गों) या अधिकरण या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकाय से है;
- (v) **“अनुज्ञप्ति”** से तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त अनुज्ञप्ति से है;
- (w) **“अनुज्ञप्त व्यवसाय”** से तात्पर्य आयोग द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति अथवा अधिनियम के अंतर्गत एक मानित अनुज्ञप्तिधारक के अनुसार उन कार्यो तथा गतिविधियों से है जो अनुज्ञप्तिधारक से अपेक्षित है;
- (x) **“दीर्घ-कालिक पारेषण उपभोक्ता”** से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जैसा, समय-समय पर संशोधित, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मुक्त उपगम के निबंधन एवं शर्तों) विनियमावली, 2019 में पारिभाषित है;
- (y) **“मध्य-कालिक पारेषण उपभोक्ता”** से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जैसा, समय-समय पर संशोधित, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मुक्त उपगम के निबंधन एवं शर्तों) विनियमावली, 2019 में पारिभाषित है;
- (z) **“अन्य व्यवसाय”** से तात्पर्य अधिनियम की धारा 51 के अर्थ के तहत अपनी आस्तियों के अनुकूलतम उपयोग के लिये अनुज्ञप्तिधारक के किसी व्यवसाय से है;
- (aa) **“मुक्त उपगम उपभोक्ता”** से तात्पर्य है जैसा, समय-समय पर संशोधित, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मुक्त उपगम के निबंधन एवं शर्तों) विनियमावली, 2019 में पारिभाषित है;
- (bb) **“परियोजना”** से तात्पर्य, संचार प्रणाली को सम्मिलित करके, पारेषण प्रणाली के सभी अवयवों और तत्वों से है;
- (cc) **“नियत वोल्टेज”** से तात्पर्य उत्पादक के डिज़ाइन वोल्टेज से है जिस पर प्रचालन के लिए पारेषण प्रणाली की संरचना की गई है, और जिसमें, दीर्घ-कालिक पारेषण उपभोक्ताओं से सलाह के बाद, जिस निम्नतर वोल्टेज पर पारेषण लाइन प्रभारित किया जाता है या कुछ समय के लिए प्रभारित किया जाता है;
- (dd) **“अल्प-कालिक पारेषण उपभोक्ता”** से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जैसा, समय-समय पर संशोधित, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मुक्त उपगम के निबंधन एवं शर्तों) विनियमावली, 2019 में पारिभाषित है;
- (ee) **“प्रशुल्क-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीसीबीसी) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक”** से तात्पर्य ऐसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारक से है जिसका प्रशुल्क, अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अन्वेषित एवं अंगीकृत किया जाता है।
- (ff) **“पारेषण सेवा अनुबंध (टी.एस.ए)”** से तात्पर्य पारेषण प्रणाली के परिचालन चरण के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारक तथा दीर्घ-कालिक पारेषण उपभोक्ता के मध्य प्रविष्ट अनुबंध, संविदा, समझौता ज्ञापन, और ऐसे किसी प्रसंविदा से है;

(gg) "पारेषण प्रणाली" से तात्पर्य, संबद्ध उपकेंद्र के साथ या उसके बिना, किसी लाइन या लाइन-समूह से है, जिसमें पारेषण तथा उपकेंद्र से संबद्ध उपकरण सम्मिलित हैं;

(hh) "पारेषण प्रणाली प्रयोक्ता (टीएसयू)" से तात्पर्य, इस विनियमावली के उद्देश्य के लिए, आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली का प्रयोग करने वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारकों तथा मुक्त उपगम उपभोक्ताओं से है;

(ii) पारेषण क्षमता अधिकार (टीसीआर)" से तात्पर्य, सामान्य परिस्थितियों में, ऐसे अंतःक्षेपण तथा निकासी बिंदुओं के बीच, किसी पारेषण प्रणाली प्रयोक्ता द्वारा मेगावॉट में ऊर्जा हस्तांतरण से है;

(jj) "पारेषण अनुज्ञप्तिधारक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है;

(kk) "समग्र पारेषण प्रणाली लागत" से तात्पर्य जैसा इस विनियमावली के खंड 29 (1) में प्रदत्त है;

(ll) "वर्ष" से तात्पर्य 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से है;

I. "वर्तमान वर्ष" से तात्पर्य उस वर्ष से है जिसमें वार्षिक लेखा-जोखा का विवरण या प्रशुल्क निर्धारण के लिए आवेदन दिया जाता है;

II. "आगामी वर्ष" से तात्पर्य वर्तमान वर्ष के अगले वर्ष से है;

III. "पिछला वर्ष" से तात्पर्य वर्तमान वर्ष के ठीक पहले के वर्ष से है;

(2) शब्दों और अभिव्यक्तियों जो इस विनियमावली में प्रयुक्त हुए हैं तथा परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो विद्युत अधिनियम, 2003 या आयोग के अन्य किसी विनियमावली, समय-समय पर संशोधित, के अधीन उन्हें समनुदिष्ट किये गये हैं। ऐसी अभिव्यक्तियां, जो यहां प्रयुक्त हुईं और विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली या विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु किसी सक्षम विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन परिभाषित हैं और राज्य में विद्युत उद्योग पर लागू होते हैं, के वही अर्थ होंगे, जो ऐसी विधि में उनको समनुदेशित किया गया है। ऐसी अभिव्यक्ति, जो इसमें प्रयुक्त हुई है, किन्तु विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली या अधिनियमों या किसी सक्षम द्वारा पारित किसी विधि में परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो विद्युत उद्योग में उनको सामान्यतः समनुदेशित किया जाता है।

(3) "आवेदन" या "याचिका" शब्द की समानार्थ व्याख्या की जाएगी।

(4) इस विनियमावली की व्याख्या में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(a) जैसा भी हो, एकवचन या बहुवचन वाले शब्दों में क्रमशः उनके बहुवचन या एकवचन वाले शब्द भी शामिल किये जाएंगे।

(b) यहां विनियमावली के प्रति किये संदर्भों को, लागू विधियों के अनुसरण में आयोग द्वारा समय समय पर यथासंशोधित या उपान्तरित विनियमावली के रूप में माना जाएगा।

(c) शीर्षकों को सुविधा के लिए डाला गया है और इन्हें इस विनियमावली के निर्वचन के प्रयोजनार्थ संज्ञान में नहीं लिया जाएगा।

(d) विधानों, विनियमावली या दिशा निर्देशों के प्रति संदर्भों/निर्देशों को यथास्थिति, ऐसे विधानों, विनियमावली या दिशा निर्देशों को समेकित, संशोधित या प्रतिस्थापित करने वाले सभी वैधानिक प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए माना जाएगा।

(e) इस विनियमावली के अंग्रेजी तथा हिन्दी पाठ के निर्वचन में किसी विवाद की दशा में अंग्रेजी पाठ प्रवृत्त होगा।

अध्याय-1

प्रशुल्क याचिका तथा प्रशुल्क निर्धारण की प्रक्रिया

3-सामान्य सिद्धांत

(1) आयोग, इस विनियमावली में निर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर, बहुवर्षीय प्रशुल्क ढांचे के अंतर्गत, पांच वर्षों के नियंत्रण अवधि के दौरान हर वर्ष आंतर-राज्यीय पारेषण प्रशुल्क निर्धारित करेगा।

(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक नियंत्रण अवधि के दौरान हर वर्ष पिछले वर्ष के एआरआर के सत्यापन, वर्तमान वर्ष के एपीआर तथा आगामी वर्ष के एआरआर/प्रशुल्क के लिए, इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट विधि एवं स्वरूप में, संगत प्रारूप में, विस्तृत अभिकलनों से समर्थित, हर दृष्टि से पूर्ण, हर वर्ष के तीस नवंबर तक, एक वार्षिक याचिका दाखिल करेगा:

तालिका 1: नियंत्रण अवधि में दायर की जाने वाली याचिका के विवरण

दाखिल करने की तिथि	द्व-अप	ए0पी0आर0	ए0आर0आर0 / टैरिफ
30-11-2024	वित्तीय वर्ष 2023-24*	वित्तीय वर्ष 2024-25*	वित्तीय वर्ष 2025-26**
30-11-2025	वित्तीय वर्ष 2024-25***	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2026-27
30-11-2026	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2026-27	वित्तीय वर्ष 2027-28
30-11-2027	वित्तीय वर्ष 2026-27	वित्तीय वर्ष 2027-28	वित्तीय वर्ष 2028-29
30-11-2028	वित्तीय वर्ष 2027-28	वित्तीय वर्ष 2028-29	वित्तीय वर्ष 2029-30

* यूपीईआरसी (वितरण एवं पारेषण के लिए बहु-वर्षीय प्रशुल्क) विनियमावली, 2019 के अनुसार याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी हैं।

** आयोग के आदेशानुसार याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, इस विनियमावली के अनुसार, और भी प्रविष्टियां मांगी जाएंगी।

*** दायर करने का कार्य यूपीईआरसी (वितरण एवं पारेषण के लिए बहुवर्षीय प्रशुल्क) विनियमावली, 2019 के अनुसार होगा; तथापि, इस विनियमावली के अनुसार, याचिकाओं को संबद्ध वर्ष के तीस नवंबर तक दायर करना होगा:

परंतु कि पिछले नियंत्रण अवधि में आने वाले उन वर्षों के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारक एआरआर का सत्यापन यूपीईआरसी (वितरण एवं पारेषण प्रशुल्क का बहु-वर्षीय प्रशुल्क) विनियमावली, 2019 में विनिर्दिष्ट विधि एवं स्वरूप में दाखिल करेगा।

(3) आंतर-राज्यीय पारेषण प्रशुल्क के निर्धारण के लिए, पिछले वर्ष के टीटीएससी (समग्र पारेषण प्रणाली लागत) के सत्यापन, वर्तमान वर्ष के एपीआर तथा आगामी वर्ष के टीटीएससी एआरआर/प्रशुल्क के लिए, इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट विधि एवं स्वरूप में, संगत प्रारूप में, विस्तृत अभिकलनों से समर्थित, हर दृष्टि से पूर्ण, हर वर्ष के तीस नवंबर तक, एक वार्षिक याचिका दाखिल करेगा:

परंतु कि जब तक एस0टी0यू के कार्य-कलाप किसी पृथक् इकाई को नहीं सौंपे जाते, तब तक राज्य पारेषण सेवाप्रदाता की हैसियत से, उत्तर प्रदेश ऊर्जा पारेषण निगम मर्यादित इस विनियमावली के खंड 2 तथा 3 के अनुपालन के लिए एक एकल याचिका दायर करेगा।

(4) निदेशक बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कमेटी/व्यक्ति के उचित अनुमोदन के पश्चात्, पारेषण अनुज्ञप्तिधारक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों तथा प्रारूपों के अनुसार, प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा डिजिटल स्वरूप में हस्ताक्षरित, आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर सत्यापन/एपीआर/एआरआर याचिका दायर करेगा:

परंतु कि आयोग की पूर्व अनुमति के बिना किए गए पूंजीगत निवेश एआरआर याचिका में सम्मिलित नहीं किए जायेंगे।

(5) याचिका की हार्ड प्रतियां भी दायर की जायेंगी जैसा कि समय-समय पर संशोधित यूपीईआरसी (व्यवसाय का व्यवहार) विनियमावली, 2019 में विनिर्दिष्ट हैं, जिसके साथ समय-समय पर संशोधित यूपीईआरसी (शुल्क एवं अर्थदंड) विनियमावली, 2010 के अनुसार उपयुक्त शुल्क भी संलग्न होगा:

परंतु कि इस विनियमावली के अंतर्गत याचिका दायर करने के शुल्क से एसटीयू को तब तक मुक्त रखा जाएगा जब तक एसटीयू के कार्य-कलाप किसी पृथक् इकाई को नहीं सौंपे जाते।

(6) याचिकाकर्ता आयोग को आयोग द्वारा यथा-अपेक्षित अंकेक्षित/अनंतिम लेखांकन विवरण, परिचालन, लागत एवं कार्य-निष्पादन से संबंधित डाटा सहित ऐसे सभी दस्तावेज तथा अभिलेख आयोग को प्रस्तुत करने होंगे। पारेषण अनुज्ञप्ति-धारक/एस0टी0यू, जैसा भी मामला हो, द्वारा दायर याचिका में आवश्यक सूचनाओं के साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, लेकिन उसी तक सीमित नहीं:

(I) ए0आर0आर/प्रशुल्क दायर करना

(a) वर्ष-विशेष के लिए पारेषण प्रणाली या नेटवर्क प्रचलन पूर्वानुमान, प्रक्षेपित पारेषण क्षमता, परिपथ लाइन विस्तार, उपकेंद्रों की संख्या, पूंजी निवेश योजना, वित्तपोषण योजना तथा भौतिक लक्ष्य, इक्विटी, अनुदान, इत्यादि;

(b) एस0टी0यू0 पारेषण योजना द्वारा अनुमोदित योजनाओं की प्रक्षेपित सूची जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा वर्ष विशेष के लिए पूंजीकृत किये जायेंगे;

(c) वर्ष विशेष के लिए पर्याप्त औचित्य के साथ, पारेषण हानियों सहित पारेषण प्रभारों के प्रस्ताव;

(d) अनुज्ञप्त व्यवसाय से अपेक्षित राजस्व, गैर-प्रशुल्क आय और दूसरे व्यवसायों से आय और पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य मामले।

(II) वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा

(a) (याचिका दायर करने की तिथि को) वास्तविक बनाम प्रक्षेपित पारेषण क्षमता, परिपथ लाइन विस्तार, उपकेंद्रों की संख्या, पूंजी निवेश योजना, वित्तपोषण योजना तथा भौतिक लक्ष्य, इक्विटी, अनुदान, इत्यादि;

(b) समीक्षाधीन अवधि में, पुष्टिकारक दस्तावेजों सहित, किये गए पूंजीगत व्यय तथा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का विवरण;

(c) वर्तमान वित्त वर्ष के लिए छह माह का अनंतिम लेखा विवरण और परीक्षण संतुलन।

(III) ट्रू-अप

(a) वास्तविक बनाम प्रक्षेपित पारेषण क्षमता, परिपथ लाइन विस्तार, उपकेंद्रों की संख्या, पूंजी निवेश योजना, वित्तपोषण योजना तथा भौतिक लक्ष्य, इक्विटी, अनुदान, इत्यादि;

(b) योजना-वार पूंजीकरण के विवरण के विपरीत आयोग से प्राप्त अनुमोदन;

(c) पूंजीकरण तथा मूल्य-हास दर्शाते हुए वर्ष-वार आस्तियों का रजिस्टर;

(d) इक्विटी निषेचन सहित वित्त-पोषण के स्रोत का विवरण;

(e) प्रासंगिक वर्ष में पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा लिए गये ऋणों के लिए ऋण-उपयोग प्रमाण-पत्र जो सांविधिक लेखा दस्तावेजों से उचिततः सामंजस्यित हों तथा जिसमें सम्मिलित हों:

(i) पूंजी व्यय;

(ii) पूंजीगत प्रगति-अधीन कार्य;

(iii) कार्यशील पूंजी।

(f) नियंत्रणाधीन प्राचलों के संबंध में लाभ/हानि का सहभाजन;

(g) लेखा विवरण और परीक्षण तुलन-पत्र का अंकक्षित विवरण।

इस विनियमावली में निर्दिष्ट कोई अन्य विवरण या जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो:

परंतु कि यदि इस विनियमावली में अनुबद्ध समय-सीमा में सत्यापन याचिका दायर नहीं होती तो विलंब अवधि के लिए सत्यापन-वर्ष में इस अंतर पर वहन लागत की अनुमति नहीं दी जाएगी, हालाँकि, अधिशेष के मामले में, वहन लागत के साथ इसकी वसूली की जाएगी:

परंतु कि यह भी कि याचिका के साथ आयोग द्वारा पिछले प्रशुल्क आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर अनुज्ञप्तिधारक एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(7) याचिका को स्वीकार करने के पूर्व आयोग एक तकनीकी मान्यकरण करेगा। अपेक्षित कार्यवाही तथा प्रस्तुतियों, जो आयोग को संतोषजनक लगे, के पश्चात्, आयोग याचिका को स्वीकार करेगा और एक प्रवेशन आज्ञा जारी करेगा।

(8) प्रवेशन आज्ञा जारी होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर याचिकाकर्ता, अपने अनुज्ञप्ति-क्षेत्र में विस्तृत प्रसार रखने वाले कम से कम दो अंग्रेजी और दो हिंदी दैनिक समाचार-पत्रों में एक जन-सूचना प्रकाशित करेगा जिसमें सत्यापन/एपीआर/एआरआर, प्रस्तावित प्रशुल्क तथा आयोग द्वारा निर्देशित अन्य कोई विवरण शामिल रहेंगे तथा हितधारकों एवं जन-सामान्य से सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित किये गये हों:

परंतु कि याचिका-कर्ता आयोग द्वारा विहित मूलपाठ-खोजनीय प्रारूप अथवा डाउनलोड हो सकने योग्य स्प्रेड शीट प्रारूप में, सभी नियामक प्रस्तुतियां, विस्तृत संगणन, ब्यौरे तथा दस्तावेज भी अपने वेबसाइट पर प्रदान करेगा:

परंतु कि यह भी कि इस विनियमावली के प्रथम परंतुक में उल्लिखित सूचना का वेब संपर्क सहजता से अभिगम्य होना चाहिए, डाउनलोड करने के लिए संग्रहीत होगा और याचिकाकर्ता के वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित होगा:

परंतु और भी कि याचिकाकर्ता अपने हितधारकों को ऐसी याचिका दायर करने, जन-परामर्श लोक-सुनवाई आदि की उपयुक्त सूचना अपने वेबसाइट तथा समाचार-पत्रों के माध्यम से देगा:

परंतु यह भी कि आयोग याचिकाकर्ता को ऐसी किसी सूचना, विवरण या दस्तावेज देने से मुक्त कर सकता है, जिसे गोपनीय समझा गया हो।

(9) प्रवेशन के एक सौ बीस दिनों के भीतर, हितधारकों एवं जन-सामान्य से प्राप्त सुझावों व आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् तथा इस विनियमावली के प्रावधानों के अनुकूल: याचिका को, ऐसे संशोधनों या शर्तों के अधीन जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट हों, स्वीकार करके एक आदेश जारी करेगा;

(a) याचिका को स्वीकृत करते हुए, सत्यापन/एपीआर/एआरआर एवं प्रशुल्क के लिए, उस आदेश में निर्दिष्ट ऐसे संशोधनों या निबंधों के साथ, एक आदेश जारी करेगा।

(b) याचिकाकर्ता को सुनवाई का एक तर्कसंगत अवसर देने के बाद, लिखित में कारण लेख्यांकित करके याचिका को अस्वीकृत करेगा, यदि ऐसी याचिका अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों या विधि के किसी अन्य के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

(10) राज्य पारेषण सेवाप्रदाता आंतर-राज्यीय पारेषण प्रशुल्क की आयोग की अनुमति के तीन कार्यशील दिनों के भीतर अपने अनुज्ञप्ति-क्षेत्र में विस्तृत प्रसार रखने वाले कम से कम दो अंग्रेजी और दो हिंदी दैनिक समाचार-पत्रों में एक जन-सूचना प्रकाशित करेगा, और इस अनुमत प्रशुल्क को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अपने इंटरनेट वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

(11) इस प्रकार से प्रकाशित प्रशुल्क आदेश में निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होंगे और, जब तक वे संशोधित या पुनरीक्षित नहीं होते, इसमें निर्दिष्ट ऐसी अवधि तक प्रभाव में बने रहेंगे।

(12) आयोग इस विनियमावली के प्रावधानों में निर्दिष्ट सत्यापन-व्यवहार करेगा। सत्यापन व्यय तथा राजस्व वित्तीय वर्ष के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के लेखा-विवरण के विवेकपूर्ण जांच के आधार पर अनुमत तथा वास्तविक व्यय, राजस्व, इत्यादि पर आधारित होंगे।

4-प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा निष्पादित कार्य को संवर्धित/सुदृढ़ करने के लिए प्रशुल्क निर्धारण की प्रक्रिया

(1) आंतर-राज्यीय पारेषण उपकेंद्रों पर संवर्धन/सुदृढ़ता कार्यों के कार्यान्वयन करने और/अथवा लाइन, जो एस0टी0यू0 पारेषण योजना का हिस्सा है, उस संबंधित टीबीसीबी पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा कार्यान्वयित होगा जिनके परिसर में कार्य होना है:

परंतु कि आयोग द्वारा अनुमत कार्य का लागत यूपीपीटीसीएल द्वारा संबंधित टीबीसीबी पारेषण अनुज्ञप्तिधारक को हस्तांतरित किया जाएगा, जो इस विनियमावली के अनुसार, यूपीपीटीसीएल के एआरआर में अग्रेषित कर दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि यूपीआईआरसी (प्रशुल्क की रूपात्मकताएं) विनियमावली, 2023 की विनियमावली 7.2 इन विनियमों में निर्दिष्ट सीमा तक अधिक्रमित हो जाएगी।

(2) यूपीपीटीसीएल इन योजनाओं/कार्यों का पूर्व अनुमोदन लेगा और आयोग उपयुक्त समझे जाने वाले के निबंधन एवं शर्तों के साथ योजना की अनुमति देगा।

(3) इन कार्यों का परिचालन एवं अनुरक्षण संबंधित विकासकर्ता द्वारा किया जाएगा जिसके लिए मानक मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत, यूपीपीटीसीएल द्वारा संबंधित टीबीसीबी विकासकर्ता जिसके परिसर में कार्य सम्पादित किया जाना है, को हस्तांतरित किया जाएगा, जो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आयोग द्वारा जारी प्रशुल्क आदेश के अनुसार होगा।

(4) यूपीपीटीसीएल कार्यों के लागत को अंतिम रूप देने के लिए प्रक्रिया, टीबीसीबी पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा बोली की कार्यविधि के संचालन तथा उसको अंतिम रूप देने के लिए, कार्यों के कार्यान्वयन के लिए निधि-हस्तांतरण के लिए, संचालन एवं अनुरक्षण की निधि आवश्यकता इत्यादि के लिए, इस विनियमावली की अधिसूचना के तीन महीनों के भीतर, आयोग की सहमति के लिए प्रस्तुत करेगा।

(5) आयोग, अपने आदेशों द्वारा, टीसीबीसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारक को निर्देश दे सकता है, तथा अनुपालन स्थिति मांग सकता है।

5-नियंत्रणीय तथा अनियंत्रणीय कारक

(1) अनियंत्रणीय कारकों में, आयोग द्वारा नियत, निम्नलिखित कारक शामिल होंगे, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के नियंत्रण के बाहर हों, या उसके द्वारा उपशमित नहीं किये जा सकते:

(a) अप्रत्याशित घटनाएं;

(b) विधि में परिवर्तन;

(c) विवेकपूर्ण जांच के अधीन दीर्घ-कालिक सामयिक ऋण के ब्याज दर में रूपांतर;

(d) आयोग द्वारा अनुमत अन्य कोई व्यय।

(2) नियंत्रणीय कारकों में, आयोग द्वारा नियत, निम्नलिखित, किंतु उन्हीं तक सीमित नहीं, कारक शामिल होंगे:

(a) समय और/या लागत अधिधाय/पूँजीगत व्यय योजनाओं के कार्यान्वयन में दक्षता, जो ऐसी योजना के परिक्षेत्र में अनुमत परिवर्तन या सांविधिक करारोपणों में परिवर्तन या अप्रत्याशित घटनाओं और पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता द्वारा योजना के कार्यान्वयन में विलंब पर आरोप्य न हों, के कारण पूँजीगत व्यय में रूपांतर;

(b) अशोध्य एवं संदेहास्पद ऋणों को बढ़े-खाते में डालने का प्रावधान;

(c) विनिर्दिष्ट कार्य-निष्पादन के मानकों एवं मानदंडों में रूपांतर;

(d) कार्यशील पूँजी पर ब्याज में रूपांतर;

(e) आंतर-राज्यीय पारेषण हानियों में रूपांतर;

(f) परिचालन एवं अनुरक्षण व्ययों के किसी घटक में रूपांतर;

(g) पारेषण प्रणाली की उपलब्धता में रूपांतर।

6-अनियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ या हानि का व्यवहार

(1) अनियंत्रणीय कारकों के कारण अनुमत लाभ या हानि को, जैसा इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट है और जैसा इस विनियमावली के अधीन आयोग के आदेश में निर्धारित किया जा सकता है, पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के प्रशुल्क या एआरआर में समायोजित किया जायेगा।

(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक ऐसे विस्तृत संगणन तथा समर्थनकारी दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा जो आयोग द्वारा सत्यापन के लिए अपेक्षित हैं।

7-नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ या हानि का व्यवहार

(1) वित्तीय लाभ या हानि परिचालन एवं अनुरक्षण व्ययों के प्रत्येक घटक के संदर्भ में संगणित किया जाएगा।

(2) खंड 7 (1) के अनुसार, पारेषण अनुज्ञप्तिधारक का अनुमत लाभ निम्नलिखित रूप में व्यवहृत होगा:

(a) ऐसे लाभ का दो-तिहाई हिस्सा, आयोग के आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रशुल्क/एआरआर में अग्रेषित किया जाएगा;

(b) ऐसे लाभ की शेष राशि पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के विवेक के अनुसार उपयोगित होगा।

(3) खंड 7 (1) के अनुसार, पारेषण अनुज्ञप्तिधारक की अनुमत हानि निम्नलिखित रूप में व्यवहृत होगी:-

(a) ऐसी हानि का एक-तिहाई हिस्सा, आयोग के आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रशुल्क/एआरआर में अग्रेषित किया जाएगा;

(b) ऐसी हानि की शेष राशि पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अवशोषित किया जाएगा।

अध्याय-2

वाणिज्यिक परिचालन में विलंब

8-वाणिज्यिक परिचालन में विलंब की प्रक्रिया

(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक (कों) और/या उत्पादक कम्पनी, एक सामयिक तथा समन्वित रूप में, आंतर-संयोजन सुविधाओं सहित पारेषण परियोजनाओं के निष्पादन के लिए, अनिवार्यतः एक "कार्यान्वयन अनुबंध" करेगा जिससे वाणिज्यिक परिचालन तिथि में किसी विमेल का वर्जन हो सके।

(2) किसी पारेषण प्रणाली या उसके अवयव तथा संबद्ध संचार प्रणाली की वाणिज्यिक परिचालन तिथि ग्रीड कोड के प्रावधानों के अनुसार होगी।

(3) यदि पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा निष्पादित पारेषण प्रणाली या उसका अवयव वाणिज्यिक परिचालन के लिए तैयार है, परंतु दूसरे अनुज्ञप्तिधारक की आंतर-संयुज्य उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली, प्रवर्तन में आने की सहमत अनुसूचित तिथि पर वाणिज्यिक परिचालन के लिए तैयार नहीं है, तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारक आयोग में, ऐसे पारेषण प्रणाली या उसके अवयव के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के अनुमोदन के लिए, एक याचिका दायर कर सकता है या आयोग द्वारा अनुमोदित टीएसए के अनुसार अग्रसर हो सकता है:

परंतु यह कि इस खंड के अंतर्गत वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के अनुमोदन का गवेषक अनुज्ञप्तिधारक उत्पादक कम्पनी और/या दूसरे पारेषण अनुज्ञप्तिधारक तथा अपने पारेषण प्रणाली के दीर्घ-कालिक उपभोक्ताओं को, जैसा भी मामला हो, वाणिज्यिक परिचालन की तिथि का कम से कम एक महीने का पूर्व नोटिस देगा:

परंतु यह भी कि इस खंड के अंतर्गत वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के अनुमोदन का गवेक्षक अनुज्ञप्तिधारक को याचिका के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ देने होंगे:—

- (a) विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी ऊर्जाकरण निर्बाधन;
- (b) विद्युत भार के साथ या उसके बिना आवेशन तत्त्व के लिए एसएलडीसी द्वारा जारी परीक्षण परिचालन प्रमाणपत्र;
- (c) पक्षों द्वारा निष्पादित कार्यान्वयन अनुबंध, संयोजन अनुबंध;
- (d) इस खंड के प्रथम परंतुक के अनुसार अनुज्ञप्तिधारक द्वारा जारी नोटिस और उस पर प्रतिवचन;
- (e) सभी संदर्भों में संबद्ध संचार प्रणाली सहित पारेषण प्रणाली की पूर्णता का कम्पनी के सक्षम प्राधिकारी का प्रमाणपत्र।
- (4) अनुज्ञप्तिधारक के उपरोक्त प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के पश्चात्, आयोग यथावश्यक आदेश पारित करेगा या निर्देश जारी करेगा।

9—वाणिज्यिक परिचालन तिथि में विमेल का वाणिज्यिक समाधान

(1) उत्पादक स्टेशन तथा पारेषण प्रणाली के वाणिज्यिक परिचालन तिथि में किसी विमेल पर, टीबीसीबी पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के पारेषण प्रभार के उत्तरदायित्व का निर्धारण निम्नांकित रूप से होगा:

(a) जहां उत्पादक स्टेशन ने संबद्ध पारेषण प्रणाली के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि को अपना वाणिज्यिक परिचालन प्राप्त नहीं किया है (जो उत्पादक स्टेशन के परिगणित वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के पूर्व नहीं है), तो उत्पादक कम्पनी आयोग द्वारा अनुमत संबद्ध पारेषण प्रणाली का पारेषण प्रभार टीबीसीबी पारेषण अनुज्ञप्तिधारक को तब तक देने के लिए उत्तरदायी होगी जब तक उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई वाणिज्यिक परिचालन प्राप्त नहीं कर लेती;

(b) जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारकों से सम्बंधित प्रणाली ने वाणिज्यिक परिचालन की तिथि को अपना वाणिज्यिक परिचालन प्राप्त नहीं किया है (जो पारेषण प्रणाली के परिगणित वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के पूर्व नहीं है), तो उक्त स्थिति में टीबीसीबी पारेषण अनुज्ञप्तिधारक को आयोग द्वारा अनुमत पारेषण प्रभार तब तक देने के लिए उत्तरदायी होगा जब तक पारेषण प्रणाली वाणिज्यिक परिचालन प्राप्त नहीं कर लेती:

परंतु कि एक से अधिक इकाई द्वारा व्यतिक्रम की स्थिति में, टीबीसीबी पारेषण अनुज्ञप्तिधारक का पारेषण प्रभारों का उत्तरदायित्व व्यतिक्रमक इकाईयों में समान अनुपात में सहभाजित किया जाएगा, जब तक कि व्यतिक्रम का निराकरण किसी भी इकाई द्वारा न हो जाए। किसी भी इकाई द्वारा व्यतिक्रम का निराकरण हो जाने पर, पूर्ण उत्तरदायित्व शेष व्यतिक्रमक इकाईयों में समान अनुपात में सहभाजित किया जाएगा, जब तक कि मात्र एक व्यतिक्रमक इकाई न बचे, जिस स्थिति में पारेषण प्रभारों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उसी व्यतिक्रमक इकाई पर होगा जब तक वह उसका निराकरण न कर दे।

(2) आयोग, पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के उपरोक्त प्रस्तुतिकरण पर विचार के पश्चात्, यथावश्यक आदेश पारित कर सकता है अथवा निर्देश दे सकता है।

अध्याय—3

वित्तीय सिद्धांत

10—वित्तीय विवेकशीलता

(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक अपना वित्तीय प्रबंधन अनुकूलतम तथा विवेकपूर्ण रीति से करेगा।
(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के प्रशुल्क तथा एआरआर के निर्धारण में, आयोग निम्नलिखित कारकों के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय विवेकशीलता का आकलन करेगा:—

(a) क्या प्रक्षेपित पूंजी व्यय एवं पूंजीकरण यथार्थवादी आकलन पर आधारित हैं, तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्रक्षेपित वित्तीय व्यय तथा पूंजीकरण में असंगत वृद्धि के लिए पर्याप्त औचित्य है;

(b) उनके मौलिक समय—सारिणी के परिप्रेक्ष्य में परियोजनाओं की भौतिक प्रगति के अनुश्रवण का स्थापित तंत्र;

(c) पूंजीगत व्यय परियोजनाओं की भौतिक प्रगति के अनुसार ऋणों का अनुकूलतम आहरण, और ऐसे ऋणों का दक्ष उपयोगीकरण;

(d) यदि वर्ष के दौरान वास्तविक पूंजी व्यय तथा पूंजीकरण में आयोग द्वारा अनुमत एसटीयू पारेषण योजना से 10 प्रतिशत से अधिक रूपांतर है तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारक ऐसे रूपांतर के लिए, अपनी सत्यापन याचिका के साथ, विस्तृत औचित्य देगा;

(e) यदि आयोग की अनुमति के बावजूद वर्ष के दौरान कोई परियोजना प्रारंभ नहीं हुई है तो सत्यापन याचिका के साथ विस्तृत औचित्य दिया जायेगा;

(f) आयोग द्वारा अनुमत पूंजीगत-व्यय (कैपेक्स) योजना के अनुसार आस्तियों का निर्माण तथा साथ ही साथ सेवा-निवृत्ति, प्रतिस्थापन, निरसन/समायोजन;

(g) प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी रूप में वस्तु एवं सेवाओं की खरीद;

(h) बद्ध आस्ति पंजिका में आस्तियों का उचित अभिलेखन;

(i) क्या क्रीत आस्तियों, जैसे भूमि, का वास्तविक प्रयोग हुआ है;

(j) अनुमत व्यय के अनुपालन, जिसमें दीर्घ-कालिक ऋण पर ब्याज भुगतान की समय-सारिणी तथा कार्यशील पूंजी शामिल है, के अनुश्रवण के लिए स्थापित तंत्र।

11-पूँजीगत व्यय/लागत तथा पूँजी संरचना

(1) किसी पूंजी निवेश परियोजना के पूंजीगत लागत में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

(a) निर्माण के दौरान ब्याज तथा वित्तपोषण प्रभार सहित, किया गया अथवा किये जाने का प्रक्षेपित व्यय, जैसा कि आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के पश्चात् अनुमोदित हो;

(b) इस विनियमावली में निर्दिष्ट उच्चतम सीमा दर के अधीन, पूंजीकृत प्रारंभिक कलपुर्ज;

(c) आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के पश्चात् अनुमोदित, मार्गाधिकार की प्राप्ति पर, पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा किया गया व्यय;

(d) इस विनियमावली के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित अतिरिक्त पूंजी व्यय;

(e) निर्माण के दौरान, परिचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) के संगत अवयवों पर प्रभाजित व्यय सहित आनुषंगिक व्यय;

(f) परिचालन की तिथि तक प्रयोजित ऋण राशि से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिम में रूपांतर के कारण कोई लाभ या हानि, जैसा कि आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के पश्चात् अनुमोदित हो:

परंतु कि परिचालन की तिथि तक प्रयोजित ऋण राशि से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिम में रूपांतर के कारण कोई लाभ या हानि केवल पूंजीगत लागत के ऋण अवयव से ही समायोजित होगी:

परंतु यह भी कि आस्तियों की पूंजीगत लागत, जो परियोजना का भाग हैं पर जिन्हें उपयोग में नहीं लाया गया है या जो उपयोग में नहीं हैं, उन्हें पूंजीगत व्यय से अपवर्जित कर दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारक अपनी आस्तियों के प्रयोग में लिए जाने के दावे के समर्थन में प्रलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(2) आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के पश्चात् अनुमत पूंजीगत लागत प्रशुल्क निर्धारण का आधार होगी।

(3) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के अंकेक्षित लेखा पर आधारित मौलिक कार्य-क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक परिचालन की तिथि पर किसी परियोजना के वास्तविक पूंजीगत व्यय पर, जैसा भी मामला हो, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के पश्चात् विचार किया जाएगा।

(4) प्रशुल्क निर्धारण के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत किए जाने वाली पूंजी लागत एसटीयू द्वारा तैयार, प्रशुल्क निर्धारण की रीतियां विनियमावली, 2023 तथा आयोग द्वारा स्वीकृत वार्षिक पूंजी निवेश योजना के अंतर्गत पारेषण योजना पर आधारित होगी।

(5) पूंजीगत लागत में नियत तिथि तक संयंत्र एवं मशीनरी लागत की प्रतिशतता के रूप में प्रारंभिक कलपुर्ज का निम्नांकित उच्चतम सीमा के अधीन पूंजीकरण सम्मिलित होगा:

(क) पारेषण प्रणाली

(i) पारेषण लाइन:	1.0%
(ii) पारेषण उपकेंद्र (एआईएस)	
हरित/नई परियोजना	4.0%
वर्तमान परियोजना का विस्तार	6.0%
(iii) गैस-रोधित/संकरित उपकेंद्र (जीआईएस/एचजीआईएस)	
हरित/नई परियोजना	5.0%

वर्तमान परियोजना का विस्तार	7.0%
(iv) सिरीज प्रतिकर उपकरण एवं एचवीडीसी उपकेंद्र	4.0%
(v) अचल तुल्यकालिक प्रतिकरकः	6.0%
(vi) संचार प्रणाली	3.5%
(ख) बैटरी ऊर्जा संचरण प्रणाली:	1.0%

(6) आस्तियों के पुनराकलन के संघात की अनुमति दी जाएगी बशर्ते इससे पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के प्रशुल्क में वृद्धि नहीं होती:

परंतु कि ऐसे किसी पुनराकलन का लाभ पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के दीर्घ-कालिक आंतर-राज्यीय सुलभ उपगम उपभोक्ताओं को, एआरआर/प्रशुल्क निर्धारण या सत्यापन के समय, जैसा भी मामला हो, अग्रेषित कर दिया जाएगा।

(7) पुराने बद्ध आस्तियों के प्रतिस्थापन, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण या जीवन-विस्तार पर किसी व्यय पर, जैसा कि किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारक पर लागू हो, ऐसी प्रतिस्थापित आस्तियों के मौलिक पूंजीगत लागत से उनके शुद्ध मूल्य को बढ़े-खाते में डालने के बाद, विचार किया जाएगा और उनका संगणन निम्नानुसार किया जाएगा:

$$\text{Net Value of Replaced Assets} = \text{OCRA} - \text{AD};$$

जहां,

OCRA: Original Capital Cost of Replaced Assets:

AD: Accumulated depreciation pertaining to the Replaced Assets

परंतु कि यदि किसी कारण से प्रतिस्थापित आस्ति का पूंजीगत लागत किसी कारण से उपलब्ध न हो तो आयोग इस पर केस-दर-केस आधार पर विचार करेगा:

परंतु यह भी कि किसी आस्ति को क्षति, जिससे उसका प्रतिस्थापन आवश्यक हो जाता है, से प्राप्त बीमा आगम राशि का, यदि कोई हो, समायोजन पहले अदत्त वास्तविक या मानक ऋण से किया जाएगा; और शेष राशि का उपयोग, यदि कोई हो, ऐसे प्रतिस्थापित आस्ति के पूंजीगत लागत को कम करने में किया जाएगा; और अन्य कोई और भी शेष राशि गैर-प्रशुल्क आय मानी जायेगी।

12-अतिरिक्त पूंजीकरण

A. मूल कार्य-क्षेत्र तथा नियत समयावधि के अंतर्गत अतिरिक्त पूंजीकरण

(1) किसी नयी या वर्तमान परियोजना के संबंध में अतिरिक्त पूंजी व्यय, जो वास्तव में किया गया है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर) के अनुसार कार्य-क्षेत्र के भीतर, वाणिज्यिक परिचालन तिथि के पश्चात् तथा नियत समयावधि तक, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अधीन, निम्नांकित आधारों पर स्वीकृत किया जा सकता है:

- आस्थगित देनदारियां;
- निष्पादन के लिए आस्थगित कार्य;
- इस विनियमावली में निर्दिष्ट उच्चतम सीमा के अधीन मूल कार्य-क्षेत्र में प्रारंभिक पूंजीगत कलपुर्जों की खरीद;
- विवाचन पंचाट या किसी सांविधिक प्राधिकारी के आदेश अथवा निर्देश या न्यायालय की डिक्री अथवा आदेश के अनुपालन पर भुगतान;
- विधि में परिवर्तन के कारण या किसी वर्तमान विधि के अनुपालन के कारण, जो मूल कार्य-क्षेत्र में विहित नहीं है;
- अप्रत्याशित घटनाएं:

परंतु कि अनंतिम एवं अंतिम प्रशुल्क के आवेदन के साथ व्यय के अनुमान सहित मूल कार्य-क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु यह भी कि किसी आस्ति के प्रतिस्थापन की स्थिति में, अतिरिक्त पूंजीकरण का हिसाब, सकल बद्ध आस्तियों और अ-पूंजीकरण के कारण आस्तियों के संचयी मूल्यहास के समायोजन के बाद किया जाएगा:

परंतु यह भी कि भविष्य के किसी तिथि को देय आस्थगित देनदारियों तथा निष्पादन के लिए आस्थगित कार्यों की सूची वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के बाद अनंतिम एवं अंतिम प्रशुल्क के आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी:

B. मूल कार्य-क्षेत्र तथा नियत समयावधि के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण

(1) किसी नयी या वर्तमान परियोजना के संबंध में अतिरिक्त पूंजी व्यय, जो वास्तव में किया गया है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीओपीओआर) के अनुसार कार्य-क्षेत्र के भीतर, वाणिज्यिक परिचालन तिथि के भीतर तथा नियत समयावधि के बाद, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अधीन, निम्नांकित आधारों पर स्वीकृत किया जा सकता है:

(a) विवाचन पंचाट या किसी सांविधिक प्राधिकारी के आदेश अथवा निर्देश या न्यायालय की डिक्री अथवा आदेश के अनुपालन पर भुगतान;

(b) विधि में परिवर्तन के कारण या किसी वर्तमान विधि के अनुपालन के कारण, जो मूल कार्य-क्षेत्र में विहित नहीं है;

(c) अप्रत्याशित घटनाएं;

(d) नियत तिथि के पूर्व मूल कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत निष्पादित कार्य जो स्वीकृत देनदारियों के लिए हैं;

(e) वास्तविक भुगतान तक सीमित और आयोग द्वारा स्वीकृत कार्य जो मूल कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत हैं नियत तिथि के बाद निष्पादित होते हैं।

(2) नियत तिथि के बाद, मूल कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत परिनियोजित आस्तियों के प्रतिस्थापन के मामले में, आयोग द्वारा, विवेकपूर्ण जांच के बाद, अतिरिक्त पूंजीकरण, सकल बद्ध आस्तियों तथा संचयी मूल्य-ह्रास में आवश्यक समायोजन के बाद निम्नलिखित आधारों पर स्वीकृत किया जा सकता है:-

(a) ऐसी आस्तियां जिनका उपयोगी जीवन परियोजना के उपयोगी जीवन से सम्मेल्य नहीं है, और ऐसी आस्तियां, इस विनियमावली के अनुसार, पूर्ण रूप से मूल्य-ह्रासित हो गई हैं; या

(b) विधि में परिवर्तन या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण आस्तियों या उपकरणों का प्रतिस्थापन आवश्यक है; या

(c) तकनीक के कालातीत विधि में परिवर्तन या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण आस्तियों या उपकरणों का प्रतिस्थापन आवश्यक है; या

(d) आयोग ने भिन्न प्रकार से ऐसी आस्तियों या उपकरणों के प्रतिस्थापन की अनुमति दे दी है:

C. मूल कार्य-क्षेत्र के परे अतिरिक्त पूंजीकरण

(1) वर्तमान पारेषण परियोजनाओं के संबंध में, मूल कार्य-क्षेत्र के परे अतिरिक्त पूंजीकरण, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अधीन, निम्नलिखित आधारों पर स्वीकृत किया जा सकता है:-

(a) विवाचन पंचाट या किसी सांविधिक प्राधिकारी के आदेश अथवा निर्देश या न्यायालय की डिक्री अथवा आदेश के अनुपालन पर भुगतान;

(b) विधि में परिवर्तन के कारण या किसी वर्तमान विधि के अनुपालन में;

(c) अप्रत्याशित घटनाएं;

(d) राष्ट्रीय या आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार भारत सरकार की उपयुक्त अथवा सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा सुविचारित या निर्देशित परियोजना की सुरक्षा तथा संरक्षा की आवश्यकता:

परंतु कि यदि नवीनीकरण अथवा आधुनिकीकरण (आरएंडएम) या परिचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) के अंतर्गत किसी व्यय का दावा किया जाता है तो फिर उसका दावा इस विनियमावली के अंतर्गत नहीं किया जा सकता।

13. परिचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) व्यय

(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के परिचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) का व्यय इन तीन अवयवों के लिए संगणित किया जाएगा (i) कर्मचारियों पर व्यय, (ii) मरम्मत एवं अनुरक्षण (आरएंडएम) व्यय, तथा (iii) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय।

(2) ओएंडएम के प्रत्येक अवयव के व्यय के मानक इस विनियमावली के अनुसार निर्धारित किए जायेंगे। उसके पश्चात्, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ओएंडएम व्यय निम्नलिखित सूत्र से निर्धारित होंगे:

$$O\&M_n - EMP_n + R\&M_n + A\&G_n$$

जहां:

$O\&M_n$ - O&M expense for n^{th} year

EMP_n - Employee expense for n^{th} year

$R\&M_n$ - R&M expenses for n^{th} year

$A\&G_n$ - A&G expenses for n^{th} year

(3) सत्यापन के समय, ओएंडएम के प्रत्येक अवयव के व्यय पर लाभ या हानि इस विनियमावली के खंड 7 के अनुसार निर्धारित किए जायेंगे।

(4) वेतन पुनरीक्षण, पेंशन योजना आदि में परिवर्तन का आघात, संबंधित अवयव के मानक व्ययों के अतिरिक्त आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के उपरांत अनुमोदित किया जाएगा। तथापि, वेतन पुनरीक्षण, पेंशन योजना आदि में परिवर्तन के आघात के कारण ऋण शेष के भुगतान जैसे एक बार के व्यय, संबंधित अवयव के मानक निर्धारण के लिए विचारित नहीं होंगे।

(5) यदि मानक स्थापित करने के लिए डाटा उपलब्ध नहीं हैं तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारक औचित्य के साथ ओएंडएम मानक प्रस्तावित करेगा। आयोग, विवेकपूर्ण जांच के पश्चात्, पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के मानक का अनुमोदन करेगा जो शेष नियंत्रण अवधि के लिए लागू होगा।

(6) कर्मचारी लागत

(a) कर्मचारी लागत 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले पिछले पांच (5) वर्षों के अंकक्षित लेखा के मूल्य के औसत के आधार पर आयोग के विवेकपूर्ण जांच के अधीन व्युत्पन्न किया जाएगा। तथापि, यदि वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए अंकक्षित लेखा उपलब्ध नहीं है तो पिछले पांच (5) वर्षों के अंकक्षित लेखा पर विचार किया जा सकता है, और तत्पश्चात् जब वे उपलब्ध हो जाएं तो आधार-वर्ष मूल्य (वित्तीय वर्ष 24-25) का पुनर्गणन किया जाएगा।

(b) ऐसे कर्मचारी लागत का औसत पिछले नियंत्रण अवधि के मध्य-वर्ष (01-04-2020 से 31-03-2025 तक) के लिए कर्मचारी लागत माना जाएगा और इसमें वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि होगी, जिसका वृद्धि-कारक, वित्तीय वर्ष 24-25 तक के परवर्ती वर्षों के संबद्ध वर्षों का सीपीआई होगा।

परन्तुकि वेतन पुनरीक्षण पेंशन योजना में परिवर्तन आदि जैसे एक बार के खर्चों के प्रभाव को आधार कर्मचारी लागत से हटाया जाएगा।

वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़े प्राप्त करने के बाद मानक कर्मचारी व्यय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना किया जाएगा:

$$EMP_n - EMP_{n-1}(1 + CPI\ inflation) \times (1 + G_n)$$

जहां:

EMP_n : Employee expense for the n^{th} year

EMP_{n-1} : Employee expense for the $(n-1)^{th}$ year

एआरआर के उद्देश्य के लिए, सीपीआई मुद्रास्फीति भारत सरकार, श्रम ब्यूरो के अनुसार औद्योगिक कर्मचारियों (अखिल भारतीय) का ठीक पहले के तीन वित्तीय-वर्षों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत होगा।

सत्यापन के उद्देश्य के लिए, सीपीआई मुद्रास्फीति संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक बिंदु से बिंदु मुद्रास्फीति होती है।

जीएन एन-वें वर्ष का एक विकास कारक है और यह वास्तविक कार्य-निष्पादन के अनुसार शून्य से अधिक या कम हो सकता है। जीएन का मूल्य प्रशुल्क आदेश में अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने में आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो अनुज्ञप्तिधारक की फाइलिंग, तल-चिह्नांकन या आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गए किसी अन्य कारक के आधार पर होगा।

(7) मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय

नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष का मानक मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय, आयोग द्वारा अनुमत वर्ष के सकल बद्ध आस्ति के अधशेष के 2% दर पर स्वीकृत होगा। नियंत्रण अवधि के परवर्ती वर्षों के मानक मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय, पिछले वर्ष के मानक आरएंडएम मूल्य के अतिरिक्त, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) एक वार्षिक वृद्धि सहित, मुद्रास्फीति पर आधारित संबंधित वर्ष के वार्षिक सकल बद्ध आस्ति के अधशेष के 2% दर पर स्वीकृत होगा:

परन्तुकि उपरोक्त पूर्वापेक्षा के अनुसार निर्धारित मानक मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय में प्रयोज्य करों या शुल्कों में परिवर्तन के आघात समावेशित होगा।

एआरआर के उद्देश्य के लिए, डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के अनुसार ठीक पहले के तीन वित्तीय-वर्षों का थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) होगा।

सत्यापन के उद्देश्य के लिए, डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक बिंदु से बिंदु मुद्रास्फीति होती है।

(8) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

(a) मानक एएंडजी व्यय 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले पांच (5) वर्षों के अंकेक्षित लेखा के मूल्य के औसत के आधार पर आयोग के विवेकपूर्ण जांच के अधीन व्युत्पन्न किया जाएगा। तथापि, यदि वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए अंकेक्षित लेखा उपलब्ध नहीं है तो पिछले पांच (5) वर्षों के अंकेक्षित लेखा पर विचार किया जा सकता है, और तत्पश्चात् जब वे उपलब्ध हो जाएं तो आधार-वर्ष मूल्य (वित्तीय वर्ष 24-25) का पुनर्गणन किया जाएगा।

(b) ऐसे एएंडजी व्यय का औसत पिछले नियंत्रण अवधि के मध्य-वर्ष (01-04-2020 से 31-03-2025 तक) के लिए एएंडजी व्यय माना जाएगा और इसमें वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि होगी, जिसका वृद्धि-कारक, वित्तीय वर्ष 24-25 तक के परवर्ती वर्षों के संबद्ध वर्षों का डब्ल्यूपीआई होगा।

(c) एएंडजी व्यय निम्नलिखित सूत्र से निर्धारित होगा जिसमें थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की अभिवृद्धि होगी और जिसमें पुष्ट पहलों (पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्रस्तावित तथा आयोग द्वारा विधिमाम्य आईटी इत्यादि पहल) या दूसरे अपेक्षित एक बार के व्यय का समावेश होगा।

वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़े प्राप्त होने के बाद, मानक प्रशासनिक और सामान्य (A&G) खर्च निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना किए जाएंगे:-

$$A\&G_n = A\&G_{n-1} (1 + WPI \text{ inflation}) + \text{provision}$$

जहां:

$A\&G_n$: is the A&G expense for the n^{th} year

$A\&G_{n-1}$: is the A&G expense for the $(n-1)^{\text{th}}$ year

एआरआर के उद्देश्य के लिए, डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के अनुसार ठीक पहले के तीन वित्तीय-वर्षों का थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) होगा।

सत्यापन के उद्देश्य के लिए, डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक बिंदु से बिंदु मुद्रास्फीति होती है।

प्रावधान: पहलों के लागत जो पूंजीगत-व्यय (कैपेक्स) परियोजनाओं के (टोटेक्स) या (ओपेक्स) रूप में परिवर्तन के लिए अपरिहार्य हैं, या जो आयोग के किसी निर्देश के अनुपालन में किये जाते हैं या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्रस्तावित तथा आयोग द्वारा स्वीकृत कोई अन्य व्यय।

14. ऋण/ईक्विटी

(1) आयोग द्वारा स्वीकृत 31 मार्च, 2025 को जमा-शेष को वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए अधशेष ईक्विटी माना जाएगा।

(2) 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद वाणिज्यिक परिचालन के लिए घोषित पूंजीगत निवेश योजना **ऋण-ईक्विटी** अनुपात वाणिज्यिक परिचालन की तिथि को इस विनियमावली के खंड 11 के अधीन आयोग द्वारा स्वीकृत 70:30 होगा, जो उपभोक्ता योगदान/जमा निर्माण कार्य/पूंजीगत अनुवृत्ति/अनुदान द्वारा पोषित आस्तियों के समावेशन के बाद, प्रशुल्क के निर्धारण के लिए विवेकपूर्ण जांच के अधीन होगा:

परंतु कि यदि वास्तविक रूप से परिनियोजित ईक्विटी पूंजीगत लागत के 30% से अधिक है तो 30% से अधिक की ईक्विटी को, प्रशुल्क के निर्धारण के लिए, पारेषण अनुज्ञप्तिधारक का मानक ऋण माना जाएगा:

परंतु यह भी कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारक वास्तविक परिनियोजित ईक्विटी के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेगा और ईक्विटी के लिए वित्त के स्रोत को स्पष्ट करेगा:

परंतु यह भी कि यदि वास्तविक रूप से परिनियोजित ईक्विटी पूंजीगत आस्ति के पूंजीगत लागत से 30% से कम है, तो वास्तविक ईक्विटी को प्रशुल्क के निर्धारण के लिए माना जाएगा:

परंतु यह भी कि विदेशी मुद्रा में निवेशित ईक्विटी को निवेश की तिथि पर भारतीय मुद्रा में अभिहित किया जाएगा:

परंतु यह भी कि आस्तियों की सेवा-निवृत्ति या प्रतिस्थापन या अ-पूंजीकरण या निरसन/समायोजन के कारण, उपरोक्त उल्लिखित ईक्विटी पूंजी ऐसी आस्तियों के मूल लागत के 30% की सीमा तक (या, यदि यह 30% से कम है तो, प्रलेखी साक्ष्य के आधार पर वास्तविक ईक्विटी अवयव) घटा दी जाएगी:

परंतु यह भी कि आस्तियों की सेवा-निवृत्ति या प्रतिस्थापन या अ-पूंजीकरण या निरसन/समायोजन के कारण, उपरोक्त उल्लिखित स्वीकृत ऋण पूंजी, प्रलेखी साक्ष्य के आधार पर, ऐसे ऋण के मूल लागत के अदत्त ऋण अवयव, या मानक ऋण अवयव, जैसा भी मामला हो, की सीमा तक, घटा दी जाएगी।

15. मूल्य-ह्रास

(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक को अपने संबंध व्यवसायों में प्रयुक्त बद्ध आस्तियों पर मूल्य-ह्रास की अनुमति दी जाएगी जिसका संगणन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(a) बद्ध आस्तियों की स्वीकृत मूल लागत मूल्य-ह्रास की गणना का मूल्य आधार होगा:

परंतु कि मूल्य-ह्रास की स्वीकृति नई आस्तियों की सम्पूर्ण पूंजीभूत राशि पर, निरसित या प्रतिस्थापित या अ-पूँजीकृत आस्तियों के स्वीकृत मूल लागत से घटा कर, स्वीकृत की जाएगी।

(b) मूल्य-ह्रास की स्वीकृति वार्षिक आधार पर ऋजु-रेखा प्रणाली के आधार परिशिष्ट-क में विनिर्दिष्ट दरों पर वर्तमान आस्तियों के लिए (31-03-2025 को या उसके पूर्व) तथा नियंत्रण अवधि में पूंजीकृत आस्तियों के लिए परिशिष्ट-ख में विनिर्दिष्ट दरों पर अनुमत होगी:

परंतु कि अनुज्ञप्तिधारक यह सुनिश्चित करेगा कि जब कोई एक आस्ति का मूल्य-ह्रास सत्तर प्रतिशत हो जाता है तो समाप्त होने वाले वर्ष के 31 मार्च को शेष मूल्य-ह्रास आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर, उनके विस्तारित जीवन को सम्मिलित करके, प्रकीर्ण कर दिया जाएगा।

(c) आस्ति का निस्तारण मूल्य पूंजी लागत का 10% होगा तथा मूल्य-ह्रास आस्ति के स्वीकृति-योग्य पूंजी लागत का अधिकतम 90% होगा:

परंतु कि स्वामित्व वाली ज़मीन को मूल्य-ह्रास योग्य आस्ति नहीं माना जाएगा, और मूल्य-ह्रास की गणना के समय पूंजी लागत से अपवर्जित रहेगा:

परंतु यह भी कि मूल्य-ह्रास वाणिज्यिक परिचालन के प्रथम वर्ष से प्रभार्य होगा:

परंतु कि आईटी उपकरणों, सॉफ्टवेयर तथा भूमिगत केबल्स का नाशरक्षण मूल्य शून्य माना जाएगा और ऐसी आस्तियों का मूल्य 100% मूल्य-ह्रास योग्य माना जाएगा।

(d) उपभोक्ता योगदान या अनुवृत्ति या अनुदान या जमा निर्माण कार्य से पोषित आस्तियों पर ह्रास-मूल्य की अनुमति नहीं होगी।

(2) विद्यमान आस्तियों के संदर्भ में, मूल्य-ह्रास की गणना के उद्देश्य से, सकल बद्ध आस्तियों का प्रारंभिक मूल्य को 31 मार्च 2025 को समापन मूल्य माना जाएगा, जैसे आयोग अपने प्रशुल्क आदेश में स्वीकृत करता है।

(3) वर्ष के किसी भाग के लिए आस्तियों के प्रक्षेपित वाणिज्यिक परिचालन के संदर्भ में, मूल्य-ह्रास की गणना आस्तियों के प्रारंभिक मूल्य तथा समापन मूल्य के औसत के आधार पर की जाएगी:

परंतु कि सत्यापन के समय पूंजीकृत आस्तियों की मूल्य-ह्रास की पुनर्गणना, याचिकाकर्ता द्वारा पूंजीकृत आस्तियों के लेखा-विवरणों एवं प्रलेखी साक्ष्यों के आधार पर होगी, जो आयोग के विवेकपूर्ण जांच के अधीन होगा।

16-लाभांश

पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के लाभांश की गणना, ईक्विटी-आधार पर, कर के पश्चात्, 14.50% वार्षिक रुपयों के रूप में की जाएगी (एतत्-पश्चात् 'आधार दर' के रूप में संदर्भित) जो इस विनियमावली के खंड 14 के अनुसार निश्चित किया जाएगा:

परंतु कि उपभोक्ता योगदान/जमा निर्माण कार्य/पूँजीगत अनुवृत्ति/अनुदान तथा संगत मूल्य-ह्रास पूंजी-लागत का हिस्सा नहीं होंगे।

17-दीर्घ-कालिक ऋण पर ब्याज

(1) उपयोगाधीन आस्तियों पर, इस विनियमावली में निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार प्राप्त दीर्घ-कालिक ऋण को ऋण पर ब्याज के लिए सकल मानक ऋण माना जाएगा:

परंतु कि तुलन-पत्र में आस्तियों की सेवा-निवृत्ति या प्रतिस्थापन या अ-पूँजीकरण या निरसन/समायोजन के मामले में, उपर्युक्त स्वीकृत ऋण पूंजी, प्रलेखी साक्ष्य के आधार पर, ऐसी आस्तियों के मूल लागत के अदत्त ऋण अवयव की सीमा तक घटा दिया जाएगा।

(2) 31 मार्च 2025 को अदत्त जमा-शेष मानक दीर्घकालिक ऋण को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अदत्त अध शेष मानक दीर्घकालिक ऋण माना जाएगा।

(3) प्रत्येक वर्ष के लिए दीर्घकालिक ऋणों का पुनर्भुगतान उस वर्ष के स्वीकृत मूल्य-ह्रास के बराबर माना जाएगा।

(4) किसी अधिस्थगन अवधि का लाभ उठाने के न होते हुए भी, ऋण पुनर्भुगतान पर आस्ति के वाणिज्यिक परिचालन के प्रथम वर्ष से विचार किया जाएगा।

(5) आगामी वर्ष का ब्याज दर ब्याज का भारित औसत दर होगा जिसकी आगणना पिछले वर्ष के वास्तविक दीर्घकालिक ऋण निवेश सूची के आधार पर की जाएगी:

परंतु कि यदि किसी वर्ष-विशेष में कोई वास्तविक दीर्घ-कालिक ऋण नहीं है लेकिन मानक ऋण अभी भी अप्रदत्त है, तो मानक दीर्घ-कालिक ऋण पर ब्याज की स्वीकृति के उद्देश्य के लिए, ब्याज दर, 100 आधार बिंदुओं सहित, पिछले वर्ष में प्रचलित एसबीआई एमसीएलआर (1 वर्ष) का भारित औसत होगा।

(6) सत्यापन के समय ब्याज-दर, संबंधित वर्ष की वास्तविक दीर्घ-कालिक निवेश-सूची का भारित औसत ब्याज-दर माना जाएगा:

परंतु कि यदि वर्ष-विशेष के लिए कोई वास्तविक दीर्घ-कालिक ऋण नहीं है, लेकिन मानक ऋण अभी भी अदत्त है, तो मानक दीर्घ-कालिक ऋण की अनुमति के उद्देश्य के लिए ब्याज-दर 100 आधार अंकों के साथ संबंधित वर्ष में प्रवृत्त एसबीआई एमसीएलआर (01 वर्ष) होगा।

(7) दीर्घ-कालिक ऋण पर ब्याज-दर, भारित औसत ब्याज-दर को लागू करके, वर्ष के मानक औसत दीर्घ-कालिक ऋण पर आगणित होगा।

परंतु कि सत्यापन के समय संबंधित वर्ष का मानक औसत ऋण उस वर्ष के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत वास्तविक आस्ति पूंजीकरण के आधार पर माना जाएगा।

18-बैंकिंग तथा वित्त प्रभार

सत्यापन में, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अधीन, बैंकिंग तथा वित्त प्रभार वास्तविकता के आधार पर होगा:

परंतु कि एआरआर में बैंकिंग तथा वित्त प्रभार अद्यतन सत्यापन-वर्ष के लिए आयोग की स्वीकृति पर अनुमत होगा।

19-निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी)/निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (आईडीसी)

(1) निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी), वास्तविक सीओडी की सीमा तक निधि के विवेकपूर्ण चरणाबद्धन को ध्यान में रखते हुए वास्तविक ऋण तथा मानक ऋण पर विचार करके आगणित किया जाएगा:

परंतु कि किसी मानक ऋण पर आईडीसी, जो प्रयुक्त निधि के 30% के ऊपर की ईक्विटी के संगत हो की उन्हीं मामलों में स्वीकृति दी जाएगी जहां समान-स्तर पर ईक्विटी का वास्तविक निषेचन सम्पूर्ण प्रयुक्त निधि के 30% से अधिक हो और इसे त्रैमासिक आधार पर आगणित किया जाएगा:

परंतु यह भी कि यदि मानक ऋण पर आईडीसी की स्वीकृति ऋण के वास्तविक निषेचन के पूर्व की जानी हो तो ऐसी आईडीसी की आगणना के लिए ब्याज-दर संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को प्रचलित 1-वर्ष के एसबीआई एमसीएलआर के बराबर होगा:

परंतु और भी कि वास्तविक ऋण के निषेचन के पश्चात् मानक ऋण पर आईडीसी की आगणना उस वर्ष-विशेष के ब्याज-दर का भारित औसत (डब्ल्यूएआरओ आई) होगा:

परंतु यह भी कि मानक ऋण पर आईडीसी की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब अनुज्ञप्तिधारक यह प्रदर्शित करे कि मानक ऋण पर आईडीसी के बाद प्राप्त पूंजीगत लागत उपभोक्ताओं के लाभ में है।

(2) निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय की आगणना शून्य तिथि पर की जाएगी, जिसमें वास्तविक सीओडी तक परिचालन-पूर्व व्ययों का ध्यान रखा जाएगा:

परंतु कि वास्तविक सीओडी तक निर्माणावधि में अर्जित किसी राजस्व को, जो जमा पर ब्याज या अग्रिम या किन्हीं अन्य पावतियों के कारण हो, निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्ययों में कमी के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

(3) आईडीसी तथा आईडीसी के खाते में अतिरिक्त लागतों के मामले में, जो सीओडी प्राप्त करने में विलंब के कारण हो, पारेषण अनुज्ञप्तिधारक इस विलंब के लिए प्रलेखी साक्ष्यों के साथ विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करेगा, जिसमें विलंबावधि में आईडीसी के मामले में निधि का विवेकपूर्ण चरणाबद्धन तथा आईडीसी का विवरण एवं विलंब के प्रासंगिक पुनर्प्राप्त या पुनर्प्राप्य परिसमापन हर्जाना भी सम्मिलित होगा।

(4) यदि सीओडी में होने वाला विलंब पारेषण अनुज्ञप्तिधारक पर आरोपणीय नहीं है, तो ऐसे अतिरिक्त आईडीसी अथवा आईडीसी की स्वीकृति, विवेकपूर्ण जांच के बाद, तथा ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता से पुनर्प्राप्त परिसमापन हर्जाना, यदि कोई हो, पारेषण प्रणाली के पूंजीगत लागत में समायोजित किया जाएगा।

(5) यदि सीओडी में होने वाला विलंब पारेषण या पूर्णतः या आंशिक रूप से अनुज्ञप्तिधारक या उसके ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता पर आरोपणीय नहीं है, तो ऐसे मामलों में, ऐसे विलंब के कारण, विवेकपूर्ण जांच के बाद, आईडीसी तथा आईडीसी या पूर्णतः या यथानुपात आधार पर, उस अस्वीकृत प्रासंगिक विलंबावधि के लिए अस्वीकृत हो जाएगा, तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता अभिकरण से पुनर्प्राप्त परिसमापन

हर्जाना, उस विलंब के अनुपात में जिस पर छूट नहीं मिली है, सम्पूर्ण कार्यान्वयन अवधि के सापेक्ष, अपने पास रख लेगा:

परंतु कि उन मामलों में जहां सीओडी प्राप्त करने में विलंब एससीओडी के छह महीनों से अधिक है जो निम्नलिखित में से किन्हीं भी कारवाहियों के लिए स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब के कारण है (i) वन समाशोधन, (ii) एनएचआई समाशोधन, (iii) रेलवे की अनुमति, तो विवेकपूर्ण जांच के बाद, अधिकतम 95% की सीमा तक समय अतिक्रमण अनुमत होगा।

(6) इस विनियमावली के खंड 19 के उपखंडों (4) तथा (5) के उद्देश्य के लिए वास्तविक ऋण तथा मानक ऋण पर आईडीसी पर इस विनियमावली के खंड 14 के उपखंड (2) में विनिर्दिष्ट मानक ऋण-ईक्विटी अनुपात में विचारित होगा।

20—विदेशी मुद्रा दर रूपांतर की प्रतिरक्षा लागत

(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मुद्रा ऋण तथा अभिगृहीत विदेशी ऋण के संबंध, आंशिक या पूर्ण रूप से, पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के विवेक पर, में विदेशी मुद्रा अनावृत्ति की प्रतिरक्षा कर सकता है।

(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मुद्रा दर रूपांतर एवं की प्रतिरक्षा की लागत, वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर, उस वर्ष में जिसमें यह होता है, आय या व्यय के रूप में पुनर्प्राप्त करेगा। तथापि इसकी अनुमति सत्यापन के समय आयोग के विवेकपूर्ण जांच के अधीन दी जाएगी।

21—कार्यशील पूंजी पर ब्याज

(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में सम्मिलित होंगे,—

- एक महीने का परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय;
- दो महीनों के आरएंडएम व्यय के 40% पर अनुरक्षण कल-पुर्ज;
- प्रचलित प्रशुल्क पर पारेषण प्रभारों से डेढ़ महीनों के समतुल्य अपेक्षित राजस्व;

ऋणात्मक

(d) पारेषण प्रणाली प्रयोक्ताओं से सुरक्षा जमा राशि के रूप में रखी राशि, यदि कोई हो:

परंतु कि यदि उपरोक्त सूत्र पर आधारित नियत कार्यशील पूंजी सकारात्मक है तो इसमें से, जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकृत हो, पिछले वर्ष के 31 मार्च का राजस्व अधिशेष (यदि कोई हो), घटा दिया जाएगा:

परंतु कि यह भी कि किसी वर्ष के सत्यापन के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का पुनर्गणन सत्यापन में आयोग द्वारा स्वीकृत कार्यशील पूंजी के अवयवों के मूल्यों के आधार पर किया जाएगा।

(2) आगामी वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज दर, 200 आधार बिंदुओं सहित, उस दिन का एसबीआई एमसीएलआर (1 वर्ष) होगा जिस दिन प्रशुल्क निर्धारण के लिए याचिका दायर की गई है:

परंतु कि किसी वर्ष के सत्यापन के उद्देश्य के लिए, कार्यशील पूंजी पर सरल ब्याज की स्वीकृति दी जाएगी जो 200 आधार बिंदुओं सहित, संबद्ध वर्ष में प्रचलित एसबीआई एमसीएलआर (1 वर्ष) का भारित औसत के बराबर होगा।

22—लाभांश पर कर

(1) इस विनियमावली के खंड 16 के अंतर्गत आयोग द्वारा स्वीकृत लाभांश पर कर संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रभावी कर दर के साथ सकल-अप किया जाएगा (एतत्-पश्चात् 'टी' के रूप में संदर्भित)। प्रभावी कर दर की गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में होगी जो उस वित्तीय वर्ष में संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारक पर लागू संबंधित वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा जो देय अनुमानित लाभ तथा कर पर आधारित होगा जिसमें से दूसरे व्यवसाय और उस पर प्रासंगिक कर का अपवर्जन होगा:

परंतु कि अनुज्ञप्त व्यवसाय से इतर किसी आय पर कर को अग्रेषित नहीं किया जाएगा और यह स्वयं पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा देय होगा:

परंतु कि यह भी कि यदि कोई पारेषण अनुज्ञप्तिधारक आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 115जेबी के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) देता है तो प्रभावी कर दर, अधिभार एवं उपकर सहित, एमएटी दर होगा:

परंतु कि और भी कि यदि कोई पारेषण अनुज्ञप्तिधारक धारा 115बीए का विकल्प लेता है तो प्रभावी कर दर आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 115बीए में विनिर्दिष्ट, अधिभार एवं उपकर सहित, कर दर होगा।

(2) लाभांश का दर दशमलव के तीन स्थानों तक समायोजित किया जाएगा और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार आगणित किया जाएगा:

कर-पूर्व लाभांश का दर = आधार वर्ष / (1-टी)

(3) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी कर दर का सत्यापन करेगा, जो वास्तविक प्रदत्त कर पर आधारित होगा, जिसमें उस पर ब्याज सहित कोई अतिरिक्त कर मांग शामिल होगा, जिसमें इस

विनियमावली के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के वास्तविक सकल आय पर प्रशुल्क अवधि से संबंधित आयकर अधिकारियों से प्राप्त ब्याज सहित कोई कर प्रतिदाय यथाविधि समायोजित होगा। इसके अतिरिक्त, पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा देय कर की गणना के समय कर राशि के न जमा करने या कम जमा करने के कारण किसी दण्ड पर विचार नहीं किया जाएगा:

परंतु कि यदि कोई पारेषण अनुज्ञप्ति धारक आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 115जेबी के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) देता है तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारक लाभांश के सकल-अप दर का, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, अधिभार एवं उपकर सहित, लागू एमएटी दर सहित, सत्यापन करेगा:

परंतु कि और भी कि यदि कोई पारेषण अनुज्ञप्तिधारक धारा 115 बीए के अंतर्गत कर देता है तो पारेषण अनुज्ञप्ति धारक लाभांश के सकल-अप दर का, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, धारा 115 बीए में विनिर्दिष्ट अधिभार एवं उपकर सहित, सत्यापन करेगा:

परंतु कि और भी कि, सत्यापन के बाद, लाभांश के सकल-अप दर की कोई कम-वसूली या अधिक-वसूली, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, की वसूली होगी या प्रतिदेय होगी।

23. गैर-प्रशुल्क आय

(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के वार्षिक पारेषण प्रभार को निर्धारित करते समय, आयोग द्वारा स्वीकृत पारेषण व्यवसाय से संबंधित गैर-प्रशुल्क आय की राशि एआरआर से घटा दी जाएगी:

परंतु कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारक आयोग द्वारा यथा अनुपपन्न अपने गैर-प्रशुल्क आय के पूर्वानुमान का पूर्ण विवरण आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(2) गैर-प्रशुल्क आय में सम्मिलित होंगे:

- (a) भूमि या भवन के किराये की आय;
- (b) कबाड़ बिक्री से आय;
- (c) निवेशों से आय:

परंतु कि शेयरधारक की निधियों के निवेशों से आय, यदि कोई हो, पारेषण अनुज्ञप्ति धारक द्वारा आयोग को प्रस्तुत अपेक्षित विस्तृत विवरण के विवेकपूर्ण जांच के अधीन, गैर-प्रशुल्क आय में शामिल नहीं होगी।

- (d) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को दिये गए अग्रिम पर ब्याज आय;
- (e) कर्मचारियों को दिये गए ऋण/अग्रिम पर ब्याज आय;
- (f) स्टाफ क्वार्टर्स के किराये की आय;
- (g) ठेकेदारों के किराये की आय;
- (h) ठेकेदारों तथा अन्य से किराया प्रभार की आय;
- (i) पर्यवेक्षण प्रभार से आय;
- (j) विज्ञापनों से आय;
- (k) निविदा संलेखों की बिक्री से आय;
- (l) भौतिक सत्यापन पर प्राप्त आधिक्य;
- (m) बीमा दावों से आय;
- (n) पूर्वावधि की आय;
- (o) विविध प्राप्तियां; तथा
- (p) अन्य कोई गैर-प्रशुल्क आय।

(3) उपरोक्त आइटम (J) (विज्ञापनों से आय) के अंतर्गत आय पारेषण अनुज्ञप्तिधारक तथा शेयरधारकों के बीच क्रमशः 30% तथा 70% के अनुपात में सहभाजित होगा:

परंतु कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारक इस विनियमावली की अधिसूचना के छह महीनों के भीतर आस्ति मुद्राकरण जांच का उपक्रम करेगा।

24-अन्य व्यवसाय से आय

(1) जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारक, अपनी आस्तियों के अनुकूलतम उपयोगीकरण के लिए, अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत किसी अन्य व्यवसाय में लिप्त है तो ऐसे व्यवसाय से प्राप्त आय, पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के राजस्व आवश्यकता की गणना में, आयोग द्वारा यथा अनुपपन्न रीति से तथा समानुपात में, एआरआर से घटा दी जाएगी। अन्य व्यवसाय से आय का समानुपात, जो पारेषण व्यवसाय में उपयोगित होगा, यथा यूपीआरईसी (पारेषण अनुज्ञप्ति धारकों तथा वितरण अनुज्ञप्ति-धारकों के अन्य व्यवसाय का व्यवहार) विनियमावली, 2004 अथवा उसके परवर्ती संशोधनों, के निर्दिष्टानुसार होगा:

परंतु कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारक पारेषण व्यवसाय तथा अन्य व्यवसाय के बीच सभी संयुक्त एवं उभयनिष्ठ लागतों के आवंटन के एक तर्कसंगत आधार का पालन करेगा, तथा निदेशक-मंडल द्वारा विधिवत् प्रमाणित, एआरआर के निर्धारण के लिए याचिका के साथ, आयोग को आवंटन विवरण दाखिल करेगा:

परंतु कि यह भी कि जहां ऐसे अन्य व्यवसाय की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागत ऐसे अन्य व्यवसाय के राजस्व से अधिक है तो ऐसे अन्य व्यवसाय से आय शून्य मानी जाएगी।

25—छूट, प्रोत्साहन, दण्ड एवं विविध

(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अर्जित सभी छूट या प्रोत्साहन को गैर-प्रशुल्क आय के अधीन माना जाएगा, जबकि, आयोग द्वारा स्वीकृत, पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्रदत्त सभी छूट या प्रोत्साहन पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के व्यय के रूप में स्वीकृत किए जायेंगे।

(2) पारेषण प्रभारों तथा भुगतान में विलंब पर अधिभार के भुगतान की सामयिकता तथा छूट प्रतिशतता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशुल्क आदेश के अनुसार होगी।

(3) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा दिया गया अर्थदण्ड, पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा:

परंतु कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारक पर दायर दण्ड/मुआवज़ा, जो इसके तर्कसंगत नियंत्रण के परे हो, जो इसके द्वारा आयोग की संतुष्टि के लिए उपयुक्त औचित्य तथा समर्थनकारी अभिलेखों द्वारा परिपुष्ट किया गया हो, विवेकपूर्ण जांच के अधीन स्वीकृत किया जाएगा।

(4) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के एआरआर की रिकॉर्ड का वहन-लागत आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के बाद, इस विनियमावली में प्रदत्त कार्यशील पूंजी पर ब्याज दर पर दिया जाएगा।

(5) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक का राजस्व आधिक्य सर्वप्रथम उस वर्ष के कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में समायोजित किया जाएगा और शेष राजस्व आधिक्य, यदि कोई हो, संबंधित वर्ष के लिए लागू कर दर को आरबीआई द्वारा मुद्रित बैंक दर के भारित औसत से शुद्ध करके, वहन-लागत का पात्र होगा:

परंतु कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारक राजस्व आधिक्य की राशि जोखिम-मुक्त प्रतिभूतियों, जैसे आरबीआई ऋणपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों या अनुसूचित बैंकों की सावधि जमा प्राप्तियों में ही निवेशित करेगा।

अध्याय-4

परिचालनीय सिद्धांत

26—प्रशुल्क के सिद्धांत

(1) आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली में उपगम तथा उसके प्रयोग के लिए पारेषण प्रभार निम्नलिखित अवयवों या उन अवयवों के संयोजन से युक्त होगा:

- पारेषण प्रणाली के उपगम का प्रभार;
- वार्षिक पारेषण प्रभार;
- संचारित ऊर्जा का प्रति यूनिट प्रभार;
- प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा प्रभार:

परंतु कि प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा प्रभार यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ग्रीड कोड, 2007 या आयोग द्वारा जारी किसी आदेश के अनुसार निर्धारित होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली में उपगम के लिए आवेदन का पात्र है, वह, पारेषण मुक्त उपगम को संचालित करने वाली आयोग की विनियमावलियों एवं आदेशों के अनुसार ऐसे उपगम को प्राप्त करने का पात्र होगा, और ऐसे उपगम को प्राप्त करने के लिए इस विनियमावली एवं आदेशों में निर्दिष्ट प्रभार का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

(3) जहां आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली में उपगम के लिए इच्छुक पारेषण प्रणाली प्रयोक्ता के लिए ऐसे प्रयोक्ता को समर्पित पारेषण लाइन या दूसरी पारेषण आस्तियों पर कार्य अपरिहार्य है, तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारक, पारेषण प्रणाली में उपगम प्रभारों के माध्यम से, इच्छुक पारेषण प्रणाली प्रयोक्ता को उपगम देने के लिए ऐसे कार्यों पर सभी तर्कसंगत व्ययों की वसूली का पात्र होगा।

(4) जहां पारेषण प्रणाली में उपगम के लिए इच्छुक पारेषण प्रणाली प्रयोक्ता के लिए दूसरे कार्य अपरिहार्य हैं, जो आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली से संबंधित इस विनियमावली के खंड 26 (3) से आवृत नहीं हैं, तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारक ऐसे कार्यों से संबंधित व्यय की, इस विनियमावली के खंड 26 (10) के अनुसार वार्षिक पारेषण प्रभारों से वसूली का पात्र होगा।

(5) जहां पारेषण प्रणाली में उपगम के लिए इच्छुक पारेषण प्रणाली प्रयोक्ता के द्वारा कोई कार्य किए गए हैं, लिए दूसरे कार्य अपरिहार्य हैं, तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारक ऐसे कार्यों को करने के लिए लगाए गए श्रमिकों की लागत, सामग्री लागत, सामग्री संचालन तथा भण्डार/इन्वेंटरी लागत के 15% की दर से पर्यवेक्षण लागत, जिसमें अधिष्ठान लागत शामिल नहीं होगा, की वसूली का पात्र होगा, और ऐसे कार्यों के लिए किसी अन्य व्यय का पात्र नहीं होगा:

परंतु कि ऐसे पर्यवेक्षण प्रभार संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के गैर-प्रशुल्क आय का अंग होंगे तथा इच्छुक पारेषण प्रणाली प्रयोक्ता द्वारा ओएंडएम पर किए गए व्यय माने जाएंगे, जो आस्ति पूंजीकरण के संबंधित वर्ष में पूंजीकृत किए जाएंगे।

(6) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली में उपगम देने के लिए किए गए कार्यों का अनुरक्षण पारेषण अनुज्ञप्तिधारक तथा पारेषण प्रणाली प्रयोक्ता के बीच थोक विद्युत पारेषण अनुबंध की अवधि के लिए किया जाएगा।

(7) जहां पारेषण प्रणाली प्रयोक्ता ने पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली में उपगम के लिए कार्यों के लिए भुगतान कर दिया है, तो, थोक विद्युत पारेषण अनुबंध की समाप्ति पर, पारेषण प्रणाली प्रयोक्ता ऐसे कार्यों के लिए प्रदत्त (कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उसके संशोधनों) ह्रासित मूल्य का पात्र होगा:

परंतु कि जहां जहां पारेषण प्रणाली प्रयोक्ता ने पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली में उपगम के लिए कार्य किया है, तो, थोक विद्युत पारेषण अनुबंध की समाप्ति पर, पारेषण प्रणाली प्रयोक्ता ऐसे कार्यों को अपने पास रखने का पात्र होगा।

(8) पारेषण प्रणाली उपगम प्रभार की वसूली, थोक विद्युत पारेषण अनुबंध की शर्तों के अनुसार, निम्नलिखित में से किसी भी प्रणाली से हो सकती है:

- (a) उपगम प्राप्त करते समय पारेषण प्रणाली प्रयोक्ता द्वारा एक-मुश्त भुगतान; या
- (b) थोक विद्युत पारेषण अनुबंध के दौरान भुगतानों की श्रृंखला; या
- (c) उपरोक्त (a) या (b) का कोई संयोजन।

(9) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक तथा पारेषण प्रणाली में उपगम का इच्छुक प्रयोक्ता के बीच, पारेषण प्रणाली में उपगम के इच्छुक प्रयोक्ता को उपगम प्रदान करने के लिए कार्य किए जाने अथवा पारेषण प्रणाली उपगम प्रभार से संबंधित कोई भी विवाद आयोग या आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी फोरम को अधिनिर्णयन के लिए संदर्भित किया जाएगा।

(10) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक का एआरआर निम्नलिखित अवयवों के संयोजन से युक्त होगा:

- (a) परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय;
- (b) मूल्य-ह्रास;
- (c) ऋण-पूंजी पर ब्याज;
- (d) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;
- (e) बैंकिंग तथा वित्तीय प्रभार;
- (f) लाभांश;
- (g) लाभांश पर कर;

ऋणात्मक

- (h) गैर-प्रभार प्रशुल्क;
- (i) दूसरे व्यवसाय से आय;

परंतु कि मूल्य-ह्रास, ऋण-पूंजी पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, लाभांश तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारक का आयकर इस विनियमावली के अध्याय 3 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा:

परंतु कि यह भी कि एआरआर के अवयव की वसूली, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के स्वामित्व वाली पारेषण लाइन्स से संगत हों लेकिन दूसरे राज्यों को विद्युत आपूर्ति करती हों, और जिनकी वसूली केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की विनियमावलियों तथा आदेशों के अनुसार हो रही हो, इस विनियमावली में निर्धारित प्रशुल्क से नहीं की जाएगी:

परंतु कि यह भी कि यदि ऐसे किसी अवयवों की वसूली, आंतर-राज्यीय पारेषण प्रशुल्क के माध्यम से पहले ही हो गई हो तो ऐसी वसूली का आधिक्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के भविष्य के वर्षों के एआरआर से, यथा-लागू संबद्ध वहन-लागत सहित, घटा दिया जाएगा:

परंतु और भी कि पूर्वावधि की आय/व्यय की स्वीकृति आयोग द्वारा सत्यापन के समय, अंकक्षित लेखा के आधार पर, केस-दर-केस आधार पर, यदि उस पूर्वावधि की आय/व्यय की स्वीकृति वास्तविक आधार पर, विवेकपूर्ण जांच के अधीन, दी जा चुकी हो:

परंतु और भी कि कार्य-निष्पादन के मानकों को पूरा करने में अथवा क्षतिपूर्ति में विफलता के कारण, आयोग या सक्षम न्यायालय, प्राधिकारी आदि के आदेश के परिणाम-स्वरूप पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा किसी पक्ष को प्रदेय सभी दण्ड एवं अवयवों की वसूली की स्वीकृति एआरआर के माध्यम से नहीं दी जाएगी:

परंतु और भी कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारक उसके द्वारा प्रदेय ऐसे दण्ड एवं अवयवों का, यदि कोई हों, पृथक् विवरण रखेगा और अपनी याचिका के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(11) अंतर-राज्यीय पारेषण प्रशुल्क सहित वार्षिक पारेषण प्रभार आयोग द्वारा, इस विनियमावली में निर्दिष्ट प्रशुल्क निर्धारण की एक याचिका के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

27-पूँजी निवेश योजना

(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक, आयोग को प्रशुल्क याचिका के साथ, एक विस्तृत प्रक्षेपित पूँजी व्यय योजना प्रस्तुत करेगा जो एसटीयू पारेषण योजना, वित्तपोषण योजना तथा आगामी वर्ष के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के सुदृढीकरण तथा वृद्धिकरण का कोई भौतिक लक्ष्य का भाग होगा, जो भार-वृद्धि, आपूर्ति-गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरिंग, संकुलन में कमी, आदि की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

(2) पूँजी निवेश योजना निवेश करने के लिए न्यूनतम लागत योजना होनी चाहिए:

परंतु कि बीस करोड़ रुपये से अधिक के पूँजीगत व्यय आयोग के पूर्ववर्ती अनुमोदन तथा विवेकपूर्ण जांच के अधीन होंगे:

परंतु यह भी कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्रस्तावित पूँजीगत व्यय परियोजनाएं/योजनाएं आंतर-राज्यीय पारेषण नेटवर्क के लिए होंगी जिसमें, यदि कोई हों, संबद्ध धारा-प्रतिकूल/धारानुकूल कार्य शामिल रहेंगी, तथा परियोजनाएं/योजनाएं खंडशः प्रस्तुत नहीं की जाएंगी:

परंतु और भी कि किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारक की विशिष्ट आवश्यकता पर आधारित कोई पूँजीगत व्यय परियोजना/योजना अनिवार्य की उसके लिए आवेदन के रूप में प्रलेखी साक्ष्यों द्वारा पुष्टि की जाएगी।

(3) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक सभी पारेषण परियोजनाओं/योजनाओं की अनुमति लेगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारक ऐसी सभी अर्हकारी मानदंड योजनाओं को एक पृथक् याचिका त्रैमासिक आधार पर आयोग की पूर्व अनुमति के लिए प्रस्तुत करेगा।

(4) आयोग की पूर्व अनुमति के लिए प्रस्तुत पूँजीगत व्यय परियोजना(ओं)/योजना(ओं) के साथ यथापेक्षित ऐसी सूचना, विवरण और दस्तावेज़ रहेंगी जिसमें सम्मिलित होंगी, पर उन्हीं तक सीमित नहीं, जैसे बाड़ों की संख्या, ग्रिड उपकेन्द्रों के नाम, विन्यास एवं अवस्थिति, उपकेन्द्रों की क्षमता (एमवीए), पारेषण लाइन की लंबाई (सर्किट किलोमीटर), जो प्रस्तावित निवेशों की आवश्यकता दिखाता है, विचारित विकल्प, लागत/लाभ विश्लेषण तथा दूसरे पहलू जिनका पारेषण प्रभारों पर प्रभाव होता है।

(5) आस्ति के प्रयोग में आने के बाद, पारेषण अनुज्ञप्तिधारक, वास्तविक पूँजीगत व्यय होने पर, त्रैमासिक आधार पर, पूँजीकरण तथा समय अतिक्रमण एवं लागत अतिक्रमण पूँजीगत व्यय परियोजनाओं/योजनाओं की सूची प्रस्तुत करेगा:

परंतु कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारक, समय-समय पर आयोग द्वारा विहित विद्युत निरीक्षक के प्रमाणपत्र तथा अन्य आलेखों के साथ, प्रत्येक तिमाही के अंत में, परियोजना/योजना-वार आस्तियों के पूँजीकरण के विवरण प्रस्तुत करेगा।

(6) आयोग परियोजना के समापन पर स्वीकृत पूँजीगत व्यय के प्रतिरूप वास्तविक पूँजीगत व्यय और पूँजीकरण की समीक्षा करेगा। आयोग द्वारा स्वीकृत त्रैमासिक पूँजीकरण प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में सत्यापन का आधार होगा।

(7) पारेषण अनुज्ञप्तिधारक, एआरआर निर्धारण की याचिका या वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा याचिका के साथ, जैसा भी मामला हो, पूँजीगत व्यय परियोजनाओं की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें ऐसी सूचना, विवरण तथा प्रलेख होंगे जैसा कि आयोग द्वारा ऐसी प्रगति के आकलन के लिए अपेक्षित हो।

अध्याय-5 परिचालन के प्रतिमान

28-परिचालन के प्रतिमान

(1) लक्ष्य की उपलब्धता

(a) मानक वार्षिक पारेषण प्रणाली की उपलब्धता कारक (एनएटीएसएफ) निम्नानुसार होगा:

I. एसी सिस्टम : 98.00%

II. एचवीडीसी दो-ध्रुवीय संसर्ग तथा बैक-टु-बैक स्टेशन : 95.00%

(2) उपकेन्द्र में आनुशंगिक ऊर्जा उपभोग:

(a) एसी सिस्टम

शीतानुकूलन, प्रकाश-व्यवस्था तथा दूसरे उपकरण में उपभोग के उद्देश्य के लिए एसी उपकेन्द्र में आनुशंगिक ऊर्जा उपभोग के प्रभार पारेषण अनुज्ञप्तिधारक वहन करेगा और वे मानक परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय में शामिल रहेंगे।

(b) एचवीडीसी उपकेन्द्र

एचवीडीसी उपकेन्द्र में आनुशंगिक ऊर्जा उपभोग के लिए, केन्द्रीय/राज्य सरकार एक या अधिक आईएसजीएस उत्पादन स्टेशन से एक उपयुक्त शेयर का आवंटन करेगा। ऐसी ऊर्जा के लिए प्रभार पारेषण अनुज्ञप्तिधारक वहन करेगा और वे मानक परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय में शामिल रहेंगे।

(3) उपकेन्द्र में आनुशंगिक ऊर्जा उपभोग:

$ARR \times (NDM/NDY) \times (TAFM/NATSAF)$

जहाँ,

ARR = Aggregate Revenue Requirement specified for the year;

NATSAF = Normative annual transmission availability factor, in per cent stipulated in these Regulations;

NDM = Number of days in the month;

NDY = Number of days in the Year; and

TAFM = Transmission System Availability Factor for the month, in per cent, computed in accordance with Annexure- C to these Regulations;

परंतु कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारक पारेषण प्रभारों का एक महीने का बिल, टीएफएम के आकलन के आधार पर बनाएगा। समायोजन, यदि कोई हो, टीएफएम के आधार पर किया जाएगा, जो संबद्ध महीने के अंतिम दिन के तीस दिनों के भीतर एसएलडीसी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

अध्याय 6

अंतर-राज्यीय पारेषण प्रशुल्क एवं टीटीएससी का सहभाजन

29-आंतर-राज्यीय पारेषण प्रशुल्क का निर्धारण

(1) सभी पारेषण अनुज्ञप्तिधारकों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली का 'सकल पारेषण प्रणाली की लागत' (टीटीएससी) बनेगा, जिसकी वसूली नियंत्रण अवधि के संबद्ध वर्ष के लिए पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ताओं (टीएसयू) से निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी:

$$TTSC = \sum_{i=1}^n ARR_i + \sum_{j=1}^m ATSC_j + \text{Adjustment for ATSC}$$

जहाँ,

TTSC = Pooled Total Transmission System Cost of year of the Control Period;

n = Number of Transmission Licensee(s) with projects under Section 62 of the Act;

m = Number of Transmission Licensee(s) with projects under Section 63 of the Act;

ARR_i = Yearly revenue requirement approved by the Commission for i_{th} Transmission Licensee for the year of the Control Period as determined by the Commission under Section 62 of the Act;

$ATSC_j$ = Annual Transmission Service Charges (ATSC) of TBCB Projects adopted by the Commission under Section 63 of the Act;

Adjustment for ATSC (during True-Up) = (Actual ATSC paid by LTTC - ATSC as adopted by the Commission) or nil whichever is lower.

(2) आयोग वार्षिक 'आधार पारेषण क्षमता अधिकार' की स्वीकृति, वितरण अनुज्ञप्तिधारक तथा भारतीय रेलवे के, नियंत्रण अवधि के संबद्ध वर्ष के लिए प्रक्षेपित 'दैनिक अधिकतम आईएनएसटीएस निकासी का वार्षिक

औसत' तथा 'वार्षिक अधिकतम आईएनएसटीएस निकासी' के औसत पर देगा, और जो आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली की 'क्षमता उपयोगीकरण' का प्रतिनिधित्व करेगा, तथा तद्वानुसार, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 'आंतर-राज्यीय पारेषण प्रशुल्क' का निर्धारण करेगा:

आधार पारेषण क्षमता अधिकार

$$(\text{Base TCR}) \text{ for the respective year} = \sum_{u=1}^n ([X + Y]/2)$$

जहां,

X = Yearly average of daily max InSTS drawal of respective year for each Distribution Licensee or Indian Railways (u) as the case may be;

Y = Yearly max InSTS drawal of respective year for each Distribution Licensee or Indian Railways (u) as the case may be;

टिप्पणी:- X एवं Y में वितरण लाइसेंसी (आंशिक ओपन एक्सेस ग्राहकों द्वारा वितरण लाइसेंसी से विद्युत की निकासी सहित) या भारतीय रेलवे, जैसा भी मामला हो, की निकासी दर्शाई जाएगी, तथा इसमें ओपन एक्सेस के माध्यम से ओपन एक्सेस ग्राहकों द्वारा विद्युत की निकासी शामिल नहीं होगी।

(3) वितरण लाइसेंसधारियों और भारतीय रेलवे द्वारा देय वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी।

$$\text{ATC}(u) = \text{TTSC} \times ([\text{Base TCR}(u)] / \sum_{u=1}^n [\text{Base TCR}(u)])$$

Where,

ATC(u) = Annual Transmission Charges to be shared by Distribution Licensees and Indian Railways (u) for the year;

परंतु कि आगामी वर्ष के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारक तथा भारतीय रेलवे के लिए, पिछले वर्षों के उपलब्ध डाटा को ध्यान में रखते हुए, 'X' तथा 'Y' के प्रक्षेपण पर निर्धारित होंगे:

परंतु कि यह भी कि आगामी वर्ष के आधार टीसीआर का प्रक्षेपण वितरण अनुज्ञप्तिधारक तथा भारतीय रेलवे द्वारा एसटीयू को विद्यमान वर्ष के अद्यतन अगस्त माह के अंतिम सप्ताह तक प्रस्तुत किए जाएंगे:

परंतु कि यह भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारक तथा भारतीय रेलवे को छोड़कर मुक्त उपगम उपभोक्ता इस विनियमावली के खंड 29 (4) में प्रदत्त रु/केडब्ल्यूएच में बिलड होगा:

परंतु कि और भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारक तथा भारतीय रेलवे के मामले में, जिनका 'X' तथा 'Y' डाटा, आधार टीसीआर के निर्धारण के समय, पूर्ववर्ती 12 महीनों के लिए उपलब्ध नहीं है, तो कम से कम 4 महीनों का उपलब्ध डाटा या वितरण अनुज्ञप्तिधारक तथा भारतीय रेलवे द्वारा आवेदित मुक्त उपगम की प्रमात्रा को, आधार पारेषण क्षमता अधिकारों की गणना के लिए, औसत मासिक 'X' तथा 'Y' के बदले में स्वीकार किया जाएगा:

परंतु कि और भी कि इस विनियमावली के नियंत्रण अवधि के संबद्ध वर्ष के सत्यापन के लिए, आधार पारेषण क्षमता अधिकारों का निर्धारण वितरण अनुज्ञप्तिधारक तथा भारतीय रेलवे के वास्तविक 'X' तथा 'Y' डाटा के आधार पर होगा, वितरण अनुज्ञप्तिधारक तथा भारतीय रेलवे को एसएलडीसी से प्राप्त हुआ है। उपरोक्त डाटा, मुक्त उपगम उपभोक्ताओं की निकासी को घटाने के बाद, वितरण अनुज्ञप्तिधारक तथा भारतीय रेलवे द्वारा राज्य पारेषण सुविधा-प्रदाता (एसटीयू) को प्रेषित की जाएगी।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारक तथा भारतीय रेलवे को छोड़कर मुक्त उपगम उपभोक्ता आंतर-राज्यीय पारेषण प्रशुल्क का भुगतान (आईएनआर/केडब्ल्यूएच में) वास्तविक ऊर्जा उपभोग के अनुसार करेंगे जो आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली का टीटीएससी कम कर देगा:

परंतु कि नियंत्रण अवधि के किसी वर्ष-विशेष में, वितरण अनुज्ञप्तिधारक तथा भारतीय रेलवे को छोड़कर मुक्त उपगम उपभोक्ता का आंतर-राज्यीय पारेषण प्रशुल्क, आयोग द्वारा पिछले वर्ष के लिए निर्धारित लागू पारेषण प्रशुल्क के सापेक्ष वृद्धि 15% से अधिक नहीं होगी।

(5) प्रत्येक वर्ष के लिए आंतर-राज्यीय पारेषण प्रशुल्क का निर्धारण आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए स्वीकृत टीटीएससी तथा स्वीकृत 'आधार पारेषण क्षमता अधिकार' के अनुपात में होगा और इसे (वितरण अनुज्ञप्तिधारक के लिए) आईएनआर/एमडब्ल्यू/वर्ष के रूप में या (वितरण अनुज्ञप्तिधारक तथा भारतीय रेलवे को छोड़कर मुक्त उपगम उपभोक्ताओं के लिए) आईएनआर/केडब्ल्यूएच के रूप में, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार नामित किया जाएगा:

वितरण अनुज्ञप्तिधारक तथा भारतीय रेलवे के लिए आंतर-राज्यीय पारेषण प्रशुल्क

वितरण अनुज्ञप्तिधारक तथा भारतीय रेलवे के लिए आंतर-राज्यीय पारेषण प्रशुल्क
आईएनआर/एमडब्ल्यू/वर्ष में = टीटीएससी/आधार टीसीआर

वितरण अनुज्ञप्तिधारक तथा भारतीय रेलवे को छोड़कर मुक्त उपगम उपभोक्ताओं के लिए आंतर-राज्यीय पारेषण प्रशुल्क

वितरण अनुज्ञप्तिधारक तथा भारतीय रेलवे को छोड़कर मुक्त उपगम उपभोक्ताओं के लिए आंतर-राज्यीय पारेषण प्रशुल्क आईएनआर/के0डब्ल्यू0एच0 = TTSC / E (वर्ष के लिए राज्य सीमा पर कुल ऊर्जा निवेश)

जहां,

टीटीएससी = नियंत्रण अवधि के वर्ष के लिए आईएनएसटीएस (प्रत्येक वर्ष आईएनआर में) संचित लागत

परंतु कि राज्य के भीतर संचरित ऊर्जा इकाइयां राज्य की परिधि पर ऊर्जा इनपुट आवश्यकता पर आधारित होंगी, जो प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अपने एमवाईटी याचिका के भाग के रूप में प्रक्षेपित होगा और जिसकी स्वीकृति आयोग द्वारा आगामी वर्ष के लिए दी जाएगी। जबकि, सत्यापन अवधि के लिए, राज्य के भीतर संचरित ऊर्जा इकाइयां राज्य की परिधि पर प्रबंधित वास्तविक ऊर्जा पर आधारित होंगी।

(6) आंतर-राज्यीय पारेषण प्रशुल्क के निर्धारण के लिए, राज्य पारेषण सेवाकर्ता, वितरण अनुज्ञप्तिधारक तथा भारतीय रेलवे के आधार पारेषण क्षमता अधिकारों तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारक/एलटीटीसी द्वारा इस विनियमावली के अनुसार प्रक्षेपित या वास्तविक टीटीएससी, जैसा भी मामला हो, के योग के आधार पर, एक याचिका दायर करेगा।

(7) वितरण अनुज्ञप्तिधारक एवं भारतीय रेलवे, आयोग द्वारा ही समय-समय पर स्वीकृत आधार पारेषण क्षमता अधिकारों के आधार पर, आंतर-राज्यीय पारेषण प्रशुल्क का मासिक भुगतान करेगा।

(8) अंतर-राज्यीय पारेषण के प्रयोग की निकासी में आधिक्य/कमी का प्रभार सत्यापन में निम्नलिखित रूप में व्यवहृत होगा:

(a) आयोग द्वारा स्वीकृत, आधार पारेषण क्षमता अधिकारों से ऊर्जा के आधिक्य निकासी के मामले में, आधिक्य निकासी के प्रभार पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ताओं (वितरण अनुज्ञप्ति-धारकों को छोड़कर मुक्त उपगम उपभोक्ता) द्वारा, 1-वर्ष एसबीआई एमसीएलआर की दर से वहन लागत सहित, देय होंगे जो वर्ष के सकल पारेषण प्रणाली लागत में समायोजित किया जाएगा:

परंतु कि आधार टीसीआर से कम ऊर्जा निकासी के मामले में, आयोग द्वारा स्वीकृत पारेषण प्रभार, जो प्रक्षेपित आधार टीसीआर के संगत हों, पर विचार किया जाएगा।

(9) प्रक्षेपित तथा सत्यापित टीटीएससी में रूपांतरण की स्थिति में, ऐसा आधिक्य/कमी परवर्ती वर्ष में संबद्ध वर्ष के भारित औसत बैंक दर के वहन लागत के साथ समायोजित की जाएगी।

अध्याय 7

आंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों की वसूली

30-आईएनएसटीएस प्रभारों की बिलिंग तथा भुगतान

(1) एसटीयू पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ताओं से, आयोग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशुल्क आदेश के अनुसार आंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों की मासिक बिलिंग तथा संग्रहण के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) एसटीयू द्वारा आंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों की इस प्रकार से संग्रहीत राशि एसटीयू द्वारा एक पृथक् खाते में रखी जाएगी और परिचालित की जाएगी।

(3) एसटीयू द्वारा आंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों की संग्रहीत राशि सकल पारेषण प्रणाली लागत (टीटीएससी) के संवितरण तथा समायोजन के लिए अनन्यतः आवंटित किया जाएगा तथा कोई शेष राशि पर आयोग द्वारा सत्यापन के दौरान विचारित किया जाएगा।

(4) अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत कार्यान्वित टीबीसीबी परियोजनाओं का मासिक पारेषण प्रभार एसटीयू द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारक को, टीबीसीबी पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा एलटीटीसी को मासिक बीजक तथा एलटीटीसी द्वारा प्रदत्त संगत भुगतान को ध्यान में रखते हुए, एलटीटीसी द्वारा ऐसी सूचना प्रदान करने के पांच कार्यशील दिनों के भीतर समायोजित/आकलित किया जाएगा।

(5) अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत मासिक पारेषण प्रभार/टीबीसीबी परियोजनाओं की लागत एलटीटीसी द्वारा, उनके बीच निष्पादित पारेषण सेवा अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के अनुसार व्यवस्थित की जाएगी।

(6) अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत पारेषण अनुज्ञप्तिधारक का मासिक पारेषण प्रभार एसटीयू द्वारा ऐसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारक को, आयोग द्वारा उपयुक्त प्रशुल्क आदेश के अंतर्गत निर्धारित आंतर-राज्यीय पारेषण प्रभार संग्रहण के पांच कार्यशील दिनों के भीतर आकलित किया जाएगा।

(7) सभी टीएसयू एसटीयू को पारेषण प्रभार का भुगतान नियमित रूप से करना सुनिश्चित करेंगे जिससे एसटीयू प्रस्तुत दावों का सामयिक व्यवस्थापन कर सकें।

(8) पारेषण प्रभारों के संवितरण के बाद, राशि का आधिक्य, यदि कोई हो, एसटीयू द्वारा एक पृथक खाते में रखा जाएगा, जिस पर आयोग संबद्ध वर्ष के लिए वहन लागत स्वीकृत करेगा।

(9) पारेषण प्रभारों के संग्रहण में किसी न्यूनता की स्थिति में, एसटीयू संवितरण अनुपात्मक रूप में करेगा और ऐसी न्यूनता की राशि, सत्यापन में संबद्ध वर्ष के बैंक दर पर वहन लागत के साथ स्वीकृत की जाएगी।

(10) एसटीयू पारेषण प्रभारों में, अल्प-कालीन पारेषण प्रभारों के कारण उपयुक्त समायोजन करेगा, यदि ये एसटीयू/यूपीपीटीसीएल द्वारा विद्युत एक्सचेंज से प्राप्त किये जाते हैं।

(11) एसटीयू आंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों की वसूली के लिए इस विनियमावली के अंतर्गत एक प्रक्रिया बनायेगा, जो सभी पारेषण प्रणाली प्रयोक्ताओं पर प्रभावी होगा और जिसे वह तीन महीनों के भीतर आयोग की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगा।

31. आंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क पर छूट का उपचार

(1) उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं डाटा केन्द्र नीति, 2021 के अनुपालन में, आंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों पर लागू माफी या छूट इस विनियमावली में निर्दिष्टानुसार व्यवहृत की जाएगी।

(2) छूट के लिए लागू और प्राप्त की गई ऊर्जा (के0डब्ल्यू0एच0) की मात्रा को उस खरीद से संबंधित कुल ट्रांसमिशन शुल्क की लागत की गणना करते समय शामिल किया जाएगा।

(3) छूट के लिए अर्ह ऊर्जा से संगत पारेषण प्रयोग प्रभार नियंत्रण अवधि के संबद्ध वर्ष के लिए आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के सकल पारेषण प्रणाली लागत (टीटीएससी) में जोड़ा जाएगा, जो विनियमावली 29 के खंड 1 के अंतर्गत समायोजित टीटीएससी की गणना के लिए निर्धारित किया गया है।

(4) समायोजित टीटीएससी वितरण अनुज्ञप्ति-धारकों तथा भारतीय रेलवे में, संबद्ध वर्ष के लिए उनके स्वीकृत आधार पारेषण क्षमता अधिकारों (आधार टीसीआर) के अनुपात में आवंटित होगा;

परंतु कि अनुज्ञप्तिधारकों तथा भारतीय रेलवे आगामी वर्ष के लिए, अपने सकल ऊर्जा (के0डब्ल्यू0एच0 में) का प्रक्षेपित खंड-विवरण, सौर तथा सौर-इतर स्रोतों में पृथक्कीकृत, राज्य पारेषण सुविधा-प्रदाता (एसटीयू) को प्रवेशन के भाग के रूप में देंगे।

(5) विनियमावली 29 के खंड 5 के अंतर्गत निर्धारित रु0/के0डब्ल्यू0एच0 में पारेषण प्रशुल्क के आधार पर, मासिक लागू छूट की आगणना संबद्ध नीति के अंतर्गत की जाएगी। प्रति इकाई छूट दर (रु0/के0डब्ल्यू0एच0) से संगत ऊर्जा उपभोग की मासिक प्रमात्रा (जिस पर छूट लागू है) पर आगणित छूट अनुज्ञप्ति-धारक(कों) तथा भारतीय रेलवे को दिये गए मासिक पारेषण प्रशुल्क बीजक में आकलित की जाएगी।

(6) प्रक्षेपित तथा सत्यापित समायोजित टीटीएससी के बीच किसी रूपांतर की स्थिति में, ऐसे आधिक्य या न्यूनता का, अगले वर्ष के समायोजित टीटीएससी में, संबद्ध वर्ष के लिए लागू भारित औसत बैंक दर के वहन लागत में समायोजन किया जाएगा।

32-पारेषण मूल्य-निर्धारण रूपरेखा

आयोग, एक विस्तृत अध्ययन तथा उचित नियामक प्रक्रिया के बाद, विद्यमान पारेषण मूल्य-निर्धारण रूपरेखा को परिवर्तित कर सकता है, जो वाल्टेज, दूरी, प्रवाह-आधार की दिशा तथा प्रमात्रा आदि कारकों या केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य-प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग द्वारा यथोचित समझा जाए।

33-पारेषण हानियां

राज्य भार प्रेशन केन्द्र द्वारा निर्धारित तथा आयोग द्वारा स्वीकृत आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली में ऊर्जा हानियां पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ताओं द्वारा उनके आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के उपयोग के अनुपात में वहित होगी।

अध्याय-8

राज्य द्वारा अनुवृत्तियों का अनुदान

34—राज्य द्वारा अनुवृत्ति के अनुदान की प्रक्रिया

यदि राज्य सरकार को किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के समूह को आयोग द्वारा निर्धारित प्रशुल्क में अनुवृत्ति का अनुदान करना हो तो वह अधिनियम की धारा 65 के अनुसार दिया जाएगा।

अध्याय-9

विविध

35—आयोग की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति

(1) इस विनियमावली में कुछ भी, ऐसे आदेश पारित करने अथवा जो न्याय के उद्देश्य को पूरा करने की आयोग की शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा।

(2) इस विनियमावली में कुछ भी, आयोग को, अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, किसी प्रक्रिया को अपनाने से बाधित करेगा जो इस विनियमावली के प्रावधानों के रूपांतर में हों, यदि आयोग किसी मामले या मामलों के समूह की विशेष परिस्थिति के दृष्टिगत, ऐसे मामले या मामलों के समूह पर निर्णय लेना न्यायसंगत या वांछनीय समझता है।

(3) इस विनियमावली में कुछ भी, प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः, आयोग को, अधिनियम के अंतर्गत, किसी मामले को व्यवहृत करने या किसी शक्ति का उपयोग करने किसी प्रक्रिया को अपनाने से बाधित करेगा जिनके लिए कोई विनियमावली नहीं बनी है, और आयोग ऐसे मामलों को इस प्रकार व्यवहृत कर सकता है जैसा इसे न्यायसंगत तथा उचित लगे।

36—निरसन तथा अपरक्षण

निरसन जब तक इस विनियमावली में अन्यथा प्रदत्त न हो, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण एवं पारेषण के लिए प्रशुल्क) विनियमावली, 2019 तथा इनके संशोधन, इस विनियमावली में उल्लिखित अवधि के लिए एपीआर तथा सत्यापन के कार्यान्वयन के सिवाय, एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

37—कठिनाइयों के अपनयन की शक्ति

यदि इस विनियमावली के किसी प्रावधान के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग, सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से, ऐसे निर्देश दे सकता है जो अधिनियम के प्रावधानों से विसंगत न हों, जो कठिनाइयों के अपनयन के लिए आवश्यक या उचित हों।

38—संशोधन की शक्ति

आयोग, किसी भी समय, इस विनियमावली के किसी प्रावधान में योग, रूपांतरण, परिवर्तन, उपांतरण या संशोधन कर सकता है।

39—शिथिलीकरण की शक्ति

आयोग, स्वतः—पहल से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर, सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से, कारणों को अभिलिखित करते हुए, तथा आवश्यक पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, इस विनियमावली के किसी भी प्रावधानों को शिथिल कर सकता है।

आयोग के आदेश द्वारा
सुमीत कुमार अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग।

अनुलग्नक ए – 31-03-2025 से पहले पूंजीकृत वर्तमान परिसंपत्तियों हेतु मूल्य ह्रास अनुसूची

परिसंपत्तियों का वर्णन		मूल्य ह्रास दर
ए.	पूर्ण स्वामित्व के तहत स्वामित्व वाली भूमि	0.00
बी.	पट्टे के तहत भूमि	
(क)	भूमि में निवेश के लिए	3.34%
(ख)	निर्माण स्थान की सफाई के लिए	3.34%
(सी)	नई खरीदी गई संपत्तियाँ:	
(क)	स्थायी किस्म के भवन और सिविल इंजीनियरिंग कार्य	
	(i) कार्यालय और शोरूम	3.34%
	(ii) लकड़ी की संरचना जैसे अस्थायी निर्माण	100%
	(iii) कच्ची सड़कों के अलावा अन्य सड़कें	3.34%
	(iv) अन्य	3.34%
(ख)	ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर (कियोस्क) सब-स्टेशन उपकरण और अन्य स्थायी उपकरण (प्लांट फाउंडेशन सहित)	
	(i) ट्रांसफार्मर (फाउंडेशन सहित) जिनकी रेटिंग 100 किलोवोल्ट एम्पीयर और उससे अधिक है	5.28%
	(ii) अन्य	5.28%
(ग)	केबल संयोजन सहित स्विचगियर	5.28%
(घ)	तड़ित विद्युत अवरोधक	
	(i) स्टेशन प्रकार	5.28%
	(ii) पोल प्रकार	5.28%
	(iii) सिंक्रोनस कंडेंसर	5.28%
(ङ)	बैटरी	9.00%
	(i) ज्वाइंट बॉक्स और डिस्कनेक्टेड बॉक्स सहित भूमिगत केबल	5.28%
	(ii) केबल डक्ट सिस्टम	5.28%
(च)	सपोर्ट सहित ओवरहेड लाइनें:	
	(i) 66 वाट से अधिक सांकेतिक वोल्टेज पर संचालित फ़ैब्रिकेटेड स्टील पर लाइनें	5.28%
	(ii) 13.2 किलोवोल्ट से अधिक लेकिन 66 किलोवोल्ट से अधिक नहीं सांकेतिक वोल्टेज पर संचालित स्टील सपोर्ट पर लाइनें	5.28%
	(iii) स्टील या प्रबलित कंक्रीट सपोर्ट पर लाइनें	5.28%
	(iv) उपचारित लकड़ी के सहारे लाइनें	5.28%
(छ)	मीटर	9.00%
(ज)	स्वचालित वाहन	9.00%
(प)	एयर कंडीशनिंग संयंत्र:	
	(i) अचल	5.28%
	(ii) चल	9.00%
(झ)	फर्नीचर और फिटिंग्स	
	(i) कार्यालय फर्नीचर और फिटिंग्स	6.33%
	(ii) कार्यालय उपकरण	6.33%
	(iii) आंतरिक वायरिंग जिसमें फिटिंग और उपकरण शामिल हैं	6.33%
	(iv) स्ट्रीट लाइट फिटिंग	5.28%
(ञ)	किराए पर दिए गए उपकरण	
	(i) मोटर्स से इतर	9.00%
	(ii) मोटर्स	6.33%
(ट)	सॉफ्टवेयर सहित आईटी00 उपकरण	15.00%
(ठ)	कोई अन्य संपत्ति जो ऊपर उल्लेखित नहीं है	5.28%

टिप्पणी: परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन उपर्युक्त तालिका में दी गई मूल्य ह्रास दर के आधार पर तय किया जाएगा।

अनुलग्नक बी – 31-03-2025 के बाद पूंजीकृत वर्तमान परिसंपत्तियों हेतु मूल्य ह्रास अनुसूची

परिसंपत्तियों का वर्णन		मूल्य ह्रास दर
ए.	पूर्ण स्वामित्व के तहत स्वामित्व वाली भूमि	0.00
बी.	पट्टे के तहत भूमि	
(क)	भूमि में निवेश के लिए	3.34%
(ख)	निर्माण स्थान की सफाई के लिए	3.34%
सी.	नई खरीदी गई संपत्तियाँ:	
(क)	स्थायी किस्म के भवन और सिविल इंजीनियरिंग कार्य	
	(i) कार्यालय और शोरूम	3.34%
	(ii) लकड़ी की संरचना जैसे अस्थायी निर्माण	100%
	(iii) कच्ची सड़कों के अलावा अन्य सड़कें	3.34%
	(iv) अन्य	3.34%
(ख)	ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर (कियोस्क) सब स्टेशन उपकरण और अन्य स्थायी उपकरण (प्लांट फाउंडेशन सहित)	
	(i) ट्रांसफार्मर (फाउंडेशन सहित) जिनकी रेटिंग 100 किलो वोल्ट एम्पीयर और उससे अधिक है	4.22%
	(ii) अन्य	4.22%
(ग)	केबल संयोजन सहित स्विचगियर	4.22%
(घ)	तड़ित विद्युत अवरोधक	
	(i) स्टेशन प्रकार	4.22%
	(ii) पोल प्रकार	4.22%
	(iii) सिंक्रोनस कंडेंसर	4.22%
(ङ)	बैटरी	9.00%
	(i) ज्वाइंट बॉक्स और डिस्कनेक्टेड बॉक्स सहित भूमिगत केबल	4.22%
	(ii) केबल डक्ट सिस्टम	4.22%
(च)	सपोर्ट सहित ओवरहेड लाइनें:	
	(i) 66 किलोवाट से अधिक सांकेतिक वोल्टेज पर संचालित फैब्रिकेटेड स्टील पर लाइनें	4.22%
	(ii) 13.2 किलोवोल्ट से अधिक लेकिन 66 किलोवोल्ट से अधिक नहीं सांकेतिक वोल्टेज पर संचालित स्टील सपोर्ट पर लाइनें	4.22%
	(iii) स्टील या प्रबलित कंक्रीट सपोर्ट पर लाइनें	4.22%
	(iv) उपचारित लकड़ी के सहारे लाइनें	4.22%
(छ)	मीटर	9.00%
(ज)	स्वचालित वाहन	9.00%
(प)	एयर कंडीशनिंग संयंत्र:	
	(i) अचल	4.22%
	(ii) चल	9.00%
(झ)	फर्नीचर और फिटिंग्स	
	(i) कार्यालय फर्नीचर और फिटिंग्स	6.33%
	(ii) कार्यालय उपकरण	6.33%

परिसंपत्तियों का वर्णन			मूल्य ह्रास दर
	(iii)	आंतरिक वायरिंग जिसमें फिटिंग और उपकरण शामिल हैं	6.33%
	(iv)	स्ट्रीट लाइट फिटिंग	4.22%
(ज)		किराए पर दिए गए उपकरण	
	(i)	मोटर्स से इतर	9.00%
	(ii)	मोटर्स	6.33%
(ट)		संचार उपकरण	
	(i)	रेडियो और उच्च आवृत्ति वाहक प्रणाली	15.00%
	(ii)	टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन	15.00%
	(iii)	फाइबर ऑप्टिक/ओपीजीडब्ल्यू	6.33%
(ठ)		सॉफ्टवेयर सहित आईटी उपकरण	15.00%
(ड)		कोई अन्य संपत्ति जो ऊपर उल्लेखित नहीं है	4.22%

टिप्पणी: परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन उपर्युक्त तालिका में दी गई मूल्य ह्रास दर के आधार पर तय किया जाएगा।

अनुलग्नक : स

एक माह के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता, घटक की गणना के लिए पद्धति

1—एक कैलेण्डर माह के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता घटक (टीएएफएम) सम्बन्धित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आगणित किया जायेगा, प्रत्येक ए0सी0 पारेषण प्रणाली के लिए पृथक रूप से एवं पारेषण प्रभारों की भागीदारी के अनुसार समूहीकरण किया जायेगा एवं एसएलडीसी से सत्यापित तथा प्रमाणित कराया जायेगा।

2—टीएएफएम, प्रतिशत में $(100 - 100 \times \text{NAFM})$ बराबर होगा जहां एनएएफएम पारेषण प्रणाली/उप-प्रणाली के लिए माह के लिए प्रति इकाई में, गैर-उपलब्धता घटक है।

3—एस0सी0 सिस्टम/सब सिस्टम के लिए एन0ए0एफ0एम0 निम्न के बराबर होगा :-

$$= \frac{[\sum_{l=1}^L (OH_l \times Cktkm_l \times NSC_l) + \sum_{t=1}^T (OH_t \times MVA_t \times 2.5) + \sum_{r=1}^R (OH_r \times MVAR_r \times 4)]}{THM \times [\sum_{l=1}^L (Cktkm_l \times NSC_l) + \sum_{t=1}^T (MVA_t \times 2.5) + \sum_{r=1}^R (MVAR_r \times 4)]}$$

जहाँ :

l = पारेषण लाइन सर्किट चिन्हित करता है;

t = एक परिवर्तक/अन्तर सम्बन्धित परिवर्तक को चिन्हित करता है (आईसीटी);

r = ए बस रिएक्टर, स्विचएबुल लाईन रिएक्टर आर स्टेटिक वीएआर कम्पेनशेसन (एसवीसी) को चिन्हित करता है;

L = लाइन सर्किटों की कुल संख्या;

T = बस रिएक्टर, स्विचएबुल लाईन रिएक्टर एण्ड एसवीसीज की कुल संख्या;

R = बस रिएक्टर, स्विचएबुल लाईन रिएक्टर एण्ड एसवीसीज की कुल संख्या;

OH = माह में कटौती के घंटे या अनुपलब्धता के घंटे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर आरोपणीय नहीं कटौती को छोड़ते हुए;

$ckt\ Km$ = ट्रान्समिशन लाईन सर्किट की किलोमीटर में लम्बाई;

NSC = सब कन्डेक्टर पर फेज की संख्या;

MVA = एक ट्रान्सफार्मर/आईसीटी की एमवीए रेटिंग;

$MVAR$ = एक बस रिएक्टर स्विचबल लाईन रिएक्टर आरएनएसटीसी की एमवीएआर रेटिंग (उस मामले में यह प्रेरक एवं क्षमतात्मक क्षमताओं का योग होगा);

THM = माह में कुल घंटे।

4—निम्नलिखित कारणों से कटौती के समय के अन्तर्गत पारेषण अवयवों को उपलब्ध माना जायेगा :

(क) अन्य पारेषण योजना के अवयवों के अनुरक्षण एवं निर्माण के लिए किया गया शटडाउन। यदि अन्य पारेषण योजना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से सम्बन्धित होती है, एसएलडीसी अन्तर निहित कार्य के लिए उसके द्वारा समुचित रूप से विचारित करके मानी हुई उपलब्धता अवधि को प्रतिबन्धित कर सकता है।

या "आयोग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य पारेषण योजना के रख रखाव या नए तत्व के निर्माण या मौजूदा प्रणाली में नवीनीकरण/उन्नयन/अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए लिया गया विराम।

(ख) एसएलडीसी के निर्देशानुसार पारेषण लाइन को अधिक वोल्टेज एवं स्विच रिएक्टरों की मानवीय ट्रिपिंग को प्रतिबन्धित करने हेतु बन्द करना।

5—पारेषण अवयवों की कटौती का समय निम्नलिखित आकस्मिकताओं के लिए विचारित अवधि के अन्तर्गत अवयवों के कुल समय में से निकाल दिया जायेगा :

(क) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण के बाहर की अप्रत्याशित घटनाएं जैसे युद्ध, हड़ताल, दंगे, बाढ़ एवं भूचाल आदि के कारण अवयवों की कटौती।

फिर भी एसएलडीसी को संतुष्ट करने का दायित्व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का होगा कि अवयव कटौती उपरोक्त वर्णित घटनाओं के कारण थी और डिजाइन असफलता के कारण नहीं थी। एसएलडीसी द्वारा एक उचित पुनः स्थापन समय अवयवों के लिए विचारित किया जायेगा तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उचित समय से आगे अवयवों की पुनः स्थापना के लिए कोई अतिरिक्त समय लिया जाता है वह पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर आरोपणीय कटौती समय माना जायेगा। एसएलडीसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा किसी विशेषज्ञ से उचित समय के निर्धारण

के लिए विचार विमर्श कर सकता है। आपात पुनः स्थापन प्रणाली से फिर से चालू किये गये विद्युत परिपथों को उपलब्ध माना जायेगा।

(ख) ग्रीड घटनाओं/गड़बड़ी के कारण कटौती पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर आरोपणीय नहीं है। उदाहरणार्थ ग्रीड में विध्न के कारण अन्य संस्थाओं द्वारा स्वामित्व वाले उपसंस्थान या बे में दोषों के कारण पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के अव्ययों तथा लाईनो की ट्रिपिंग, आईसीटी आदि की कटौती। फिर भी, ग्रीड घटना/विध्न होने पर प्रणाली को उचित समय में सामान्य करते समय एसएलडीसी से प्राप्त निर्देशों पर अवयव को चालू नहीं किया जाता, एसएलडीसी के पुनः स्थापन के लिए निर्देशों के निर्गत होने के पश्चात कटौती की अवधि के लिए अवयव को उपलब्ध नहीं माना जायेगा।

6-ग्रीड घटनाओं/गड़बड़ी के कारण कटौती पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर आरोपणीय नहीं है। उदाहरणार्थ ग्रीड में विध्न के कारण अन्य संस्थाओं द्वारा स्वामित्व वाले उपसंस्थान या बे में दोषों के कारण पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के अव्ययों तथा लाईनो की ट्रिपिंग, आईसीटी आदि की कटौती। फिर भी, ग्रीड घटना/विध्न होने पर प्रणाली को उचित समय में सामान्य करते समय एसएलडीसी से प्राप्त निर्देशों पर अवयव को चालू नहीं किया जाता, एसएलडीसी के पुनः स्थापन के लिए निर्देशों के निर्गत होने के पश्चात कटौती की अवधि के लिए अवयव को उपलब्ध नहीं माना जायेगा।

7-इस अनुलग्नक -स के खंड (5) और (6) के प्रयोजन के लिए जिस कटौती अवधि का अपवर्जन किया जा सकता है, उसे निम्नानुसार घोषित किया जाएगा:

(क) एसपीसी के सदस्य सचिव द्वारा अधिकतम एक महीने तक;

(ख) एसपीसी में निर्णय के बाद एक महीने से अधिक और तीन महीने तक;

(ग) आयोग द्वारा तीन महीने से अधिक जिसके लिए पारेषण लाइसेंस कटौती और बहाली समय-सीमा को कम करने के लिए उठाए गए कदमों और कारणों के साथ आयोग से संपर्क करेगा।

8-असंगतता की स्थिति में, ये विनियमावली, आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के संबंध में मानित उपलब्धता के संबंध में आयोग द्वारा जारी/पारित किसी अन्य विनियमावली या संहिता या आदेश के ऊपर अधिभावी होंगे।

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (MULTI YEAR TARIFF FOR TRANSMISSION) REGULATIONS, 2025 CONTENTS		
1	Short title, Extent, Applicability and Commencement	35
2	Definitions	35-39
	CHAPTER 1	39
	TARIFF PETITION AND PROCEDURE FOR DETERMINATION OF TARIFF	39
3	General Principles	39-41
4	Method for Determination of Tariff for augmentation/strengthening works executed by TBCB Transmission Licensee	41-42
5	Controllable and Uncontrollable Factors	42
6	Treatment of Gains or Losses on account of Uncontrollable Factors	42
7	Treatment of Gains or Losses on account of Controllable Factors	42
	CHAPTER 2	43
	DELAY IN COMMERCIAL OPERATION	43
8	Procedure for Delay in Commercial Operation	43
9	Commercial Settlement in case of Mismatch in Date of Commercial Operation	43- 44
	CHAPTER 3	44
	FINANCIAL PRINCIPLES	44
10	Financial Prudence	44
11	Capital Expenditure/ Cost and Capital Structure	44- 45
12	Additional Capitalisation	45- 47
13	Operation and Maintenance Expenses	47- 48
14	Debt-Equity	48- 49
15	Depreciation	49
16	Return on Equity	49- 50
17	Interest on Long-Term Loan	50
18	Banking and Finance Charges	50
19	Interest During Construction (IDC)/Incidental Expenditure During Construction (IEDC)	50- 51
20	Hedging Cost of Foreign Exchange Rate Variation (FERV)	51
21	Interest on Working Capital	51
22	Tax on Return on Equity	52
23	Non-Tariff Income	52- 53
24	Income from Other Business	53
25	Rebate, Incentive, Penalties and Miscellaneous	53

	CHAPTER 4	53
	OPERATIONAL PRINCIPLES	53
26	Components of Tariff	53- 55
27	Capital Investment Plan	55- 56
	CHAPTER 5	56
	NORMS OF OPERATION	56
28	Norms of Operation	56- 57
	CHAPTER 6	57
	INTRA-STATE TRANSMISSION TARIFF AND SHARING OF TTSC	57
29	Determination of Intra-State Transmission Tariff	57- 59
	CHAPTER 7	59
	RECOVERY OF INTRA-STATE TRANSMISSION CHARGES	59
30	Billing and Payment of the InSTS Charges	59- 60
31	Treatment of Rebate on intra-State Transmission Charges	60
32	Transmission Pricing Framework	60
33	Transmission Losses	60
	CHAPTER 8	60
	GRANT OF SUBSIDIES BY STATE GOVERNMENT	60
34	Manner of grant of subsidy by State Government	60
	CHAPTER 9	60
	MISCELLANEOUS	60
35	Saving of Inherent Powers of the Commission	60- 61
36	Repeal and Saving	61
37	Power to remove difficulties	61
38	Power to Amend	61
39	Power to Relax	61
	Annexure-A	62
	Depreciation Schedule for Existing Assets Capitalised on or before 31.03.2025	62
	Annexure-B	63
	Depreciation Schedule for Existing Assets Capitalised After 31.03.2025	63
	Annexure-C	64
	Procedure for calculation of Transmission System Availability Factor for a Month	64- 65

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(MULTI YEAR TARIFF FOR TRANSMISSION) REGULATIONS, 2025

Regulation No.: UPERC/D(T)/JD(Transmission)/156-012

Dated Lucknow, June 6, 2025

IN exercise of the powers conferred Section 181 read with the Section 36, Section 39, Section 40, Section 41, Section 61, Section 62, Section 64, Section 65, Section 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations. These Regulations shall supersede the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Distribution and Transmission) Regulations, 2019 and its amendments for determination of Transmission Tariff and all aspects given thereto related to Transmission.

1. Short title, Extent, Applicability and Commencement

(1) These Regulations shall be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Transmission) Regulations, 2025.

(2) These Regulations shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) These Regulations shall be applicable to State Transmission Utility (STU) & Transmission Licensees whose Tariff is to be determined under Section 62 of the Act for determination of Aggregate Revenue Requirement (ARR), Annual Performance Review (APR), Tariff, True-Up and associated matters as covered under these Regulations:

Provided that clause 4 of these Regulations shall be applicable on TBCB Transmission Licensee and clause 8 and clause 9 of these Regulations shall also be applicable on TBCB Transmission Licensee and Generating Companies in absence of co-terminus provisions in the TSA/ connection/implementation agreement or in any other agreement executed between the parties:

Provided further that the tariff of Dedicated Transmission Line/system of an existing generator may be determined as per the principles underlined in these Regulations, wherever applicable, as per the methodology adopted by the Commission in its Orders issued from time to time.

(4) These Regulations shall come into force from April 01, 2025 and unless reviewed earlier or extended by the Commission, shall remain in force for a period of five years:

Provided that for all purposes, the issues relating to the determination of ARR, APR, Tariff, True-Up and other associated matters, including review matters, for respective Financial Years shall be governed by the respective Tariff Regulations applicable for that specific year.

2. Definitions

(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires:

(a) “**Accounting Statement**” means for each financial year the following statements, namely: -

- (i) Audited Balance sheet, prepared in accordance with the form contained in Part I of Schedule 3 to the Companies Act, 2013, as amended from time to time;
- (ii) Audited Profit and loss accounts, complying with the requirements contained in Part II of Schedule 3 to the Companies Act, 2013, as amended from time to time;
- (iii) Audited Cash flow statement, prepared in accordance with the Accounting Standard on cash flow Statement (IND AS-3) of the Institute of Chartered Accountants of India, as amended from time to time;
- (iv) Report of statutory auditors of the Licensee;
- (v) Cost records if any, prescribed by the Central Government under Section 148 of the Companies Act, 2013, as amended from time to time;
- (vi) Together with notes thereto, and such other supporting statements and information as the Commission may direct from time to time;
- (vii) Trial Balance for the year matching the accounts with Financial Statements.

(b) “**Act**” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), as amended from time to time;

(c) “**Additional Capitalization**” means the capital expenditure incurred or projected to be incurred, after the date of commercial operation of the project, admitted by the Commission after prudence check, subject to the provisions of these Regulations;

(d) **“Aggregate Revenue Requirement” or “ARR”** means the costs pertaining to the licensed business which are permitted, in accordance with these Regulations, to be recovered from the Tariffs determined by the Commission;

(e) **“Allocation Statement”** means for each Financial Year, statements in respect of each of the businesses of the Transmission Licensee for optimum utilization of its assets, showing the amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve or provision etc., which has been either,-

- (i) Determined by apportionment or allocation between different Businesses of the Licensee, including the Licensed business, together with a description of the basis of the apportionment or allocation; or
- (ii) Charged from or to each such Other Business together with a description of the basis of that charge.

(f) **“Availability”** in relation to a Transmission System for a given period means the time in hours during that period for which the Transmission System is capable of transmitting electricity at its rated voltage, expressed in percentage of total hours in the given period, and shall be computed as provided in **Annexure-C** of these Regulations;

(g) **“Base Year”** means the Financial Year immediately preceding first year of the Control Period and used for the purpose of these Regulations *i.e* FY 2024-25;

(h) **“Bank Rate”** shall mean the Bank Rate as declared by the Reserve Bank of India from time to time;

(i) **“Bulk Power Transmission Agreement”** means executed agreement that contains the terms and conditions under which a Transmission System User is entitled to access to an Intra-State Transmission System of a Transmission Licensee;

(j) **“Competitive Bidding”** means a transparent process for procurement of equipment, services and works in which bids are invited by the project developer by open advertisement covering the scope and specifications of the equipment, services and works required for the project, and the terms and conditions of the proposed contract as well as the criteria by which bids shall be evaluated, and shall include domestic competitive bidding and international competitive bidding;

(k) **“Change in Law”** means occurrence of any of the following events,-

- (i) enactment, bringing into effect or promulgation of any new Indian law; or
- (ii) adoption, amendment, modification, repeal or re-enactment of any existing Indian law; or
- (iii) judicial pronouncements, Orders of Central Government and/ or State Government; or
- (iv) change in interpretation or application of any Indian law by a competent court, Tribunal or Indian Governmental Instrumentality, which is the final authority under law for such interpretation or application; or
- (v) change in condition or covenant by any competent statutory authority in relation to any consent or clearances or approval or License available or obtained for the Project; or
- (vi) coming into force or change in any bilateral or multilateral agreement or treaty between the Government of India and any other Sovereign Government having implications for the Transmission System regulated under these Regulations;
- (vii) Any change in taxes or duties, or introduction of any taxes or duties levied by the Central or any State Government, unless specified otherwise in this Regulation.

(l) **“Commission”** means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (UPERC);

(m) **“Conduct of Business Regulations”** means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2019 and its subsequent amendments / addendum / re-enactment subsequent to its repeal;

(n) **“Control Period”** means the period comprising of five financial years from April 1, 2025 to March 31, 2030, and unless extended by the Commission;

(o) **“Connection Agreement”** means the agreement defined in UPERC (Grant of Connectivity to Intra-State System) Regulation, 2010 as amended from time to time;

(p) **“Cut-off Date”** shall mean the last day of the financial year closing after Twelve months from the date of commercial operation of the project;

(q) **“Date of Commercial Operation” (COD)** shall mean the date declared by the Transmission Licensee from 00:00 hour of which element of the Transmission System is in regular service after successful charging and trial operation for transmitting electricity and communication signal from sending end to receiving end:

Provided that where the transmission line or substation is dedicated for evacuation of power from a particular generating station, the Generating Company and Transmission Licensee shall endeavour to commission the generating station and the Transmission System simultaneously as far as practicable and shall ensure the same through appropriate Implementation Agreement:

Provided further that in case a Transmission System or an element thereof is prevented from regular service for reasons not attributable to the Transmission Licensee or its supplier or its contractors but is on account of the delay in commissioning of the concerned generating station or in commissioning of the upstream or downstream, the Transmission Licensee shall approach the Commission through an appropriate application for approval of the date of commercial operation of such Transmission System or an element thereof:

Provided also that in case of an existing Transmission Licensee, such request may be included as part of its Aggregate Revenue Requirement Petition or Annual Performance Review Petition or True-Up Petition to be filed under these Regulations;

(r) **“Distribution Licensee”** means a person who has been granted a License under sub-section (b) of Section 14 of the Act and shall include a deemed Licensee;

(s) **“Force Majeure”** for the purpose of these Regulations means the event or circumstance or combination of events or circumstances including but not limited to those stated below that wholly or partly prevents or unavoidably delays the Transmission Licensee from completing the project within the time specified in the Capital Investment Approval/ contract agreement, and only if such events or circumstances are not within the control of the Transmission Licensee and could not have been avoided, had the Transmission Licensee taken reasonable care or complied with prudent utility practices:

- (i) Act of God including but not limited to lightning, drought, fire and explosion, earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, cyclone, typhoon, tornado, geological surprises; or
- (ii) Any act of war, invasion, armed conflict or act of a foreign enemy, blockade, embargo, revolution, riot, insurrection, terrorist or military action; or
- (iii) Industry wide strikes and labour disturbances having a nationwide impact in India;
- (iv) Delay in obtaining statutory approvals for the projects where the delay is not attributable to Licensee;
- (v) Delay in land acquisition for the projects where the delay is not attributable to Licensee;

(t) **“Implementation Agreement”** means any multi-party agreement or covenant entered among the Generating Company and/ or the Transmission Licensee(s) of the interconnected/associated transmission system for the execution of generation and transmission projects in a coordinated manner, laying down the project implementation schedule and mechanism for monitoring the progress of the projects;

(u) **“Indian Government Instrumentality”** means any ministry department, board, authority, agency, corporation and commission under direct or indirect control of the Government of India or the State Government(s) or both or Appropriate Commission (s) or tribunal or judicial or quasi-judicial body;

(v) **“License”** means a license granted under Section 14 of the Act;

(w) **“Licensed Business”** means the functions and activities for which the Licensee is required to undertake in terms of the license granted by the Commission or on account of being a deemed Licensee under the Act;

(x) **“Long-term Transmission customer”** means a person as defined in UPERC (Terms & Conditions of Open Access) Regulation, 2019 as amended from time to time;

(y) **“Medium-term Transmission customer”** means a person as defined in UPERC (Terms & Conditions of Open Access) Regulation, 2019 as amended from time to time;

(z) **“Other Business”** means any business of the Licensee for optimum utilization of its assets within the meaning of Section 41 of the Act;

(aa) **“Open Access Customer”** means as defined in UPERC (Terms & Conditions of Open Access) Regulation, 2019 as amended from time to time;

(bb) **“Project”** means all components and elements of the Transmission system including communication system;

(cc) **“Rated voltage”** means the manufacturer's design voltage at which the Transmission System is designed to operate and includes such lower voltage at which Transmission line is charged or for the time being charged, in consultation with long- term Transmission customers;

(dd) **“Short term Transmission Customer”** means a person as defined in UPERC (Terms & Conditions of Open Access) Regulation, 2019 as amended from time to time;

(ee) **“Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) Transmission Licensee”** means Transmission Licensee, whose tariff is discovered through competitive bidding and adopted by the Commission under Section 63 of the Act;

(ff) **“Transmission Service Agreement (TSA)”** means the Agreement, Contract, Memorandum of Understanding, or any such covenant, entered into between the Transmission Licensees and the long-term Transmission customer for the operational phase of the Transmission system;

(gg) **“Transmission System”** means a line or a group of lines together with or without associated Sub- Stations, and includes equipment associated with Transmission lines and Sub- Stations;

(hh) **“Transmission System Users (TSU's)”** for the purpose of these Regulations means the Open Access Customers which includes distribution licensee using Intra State Transmission System;

(ii) **“Transmission Capacity Rights (TCR)”** means the right of a Transmission System User to transfer power in MW, under normal circumstances, between such points of injection and drawal;

(jj) **“Transmission Licensee”** means a person who has been granted a License under sub-section (a) of Section 14 of the Act;

(kk) **“Total Transmission System Cost (TTSC)”** means as provided under clause 29(1) of these Regulations;

(ll) **“Year”** means the financial year ending on 31st March;

(i) **“Current Year”** means the year in which the statement of annual accounts or application for determination of Tariff is filed;

(ii) **“Ensuing Year”** means the year next following the current year;

(iii) **“Previous Year”** means the year immediately preceding the current year.

(2) The words and expressions used in these Regulations and not defined herein, but defined in the Act, shall bear the same meaning as in the Electricity Act, 2003 or any other Regulations of the Commission, as amended from time to time. Expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Electricity Act, 2003 but defined under any law passed by a competent legislature and applicable to the electricity industry in the State shall have the meaning assigned to them in such law. Expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Act or any law passed by a competent legislature shall have the meaning as is generally assigned in the electricity industry.

(3) The words “Application” or “Petition” shall be used interchangeably.

(4) In the interpretation of these Regulations, unless the context otherwise requires:

(a) words in the singular or plural term, as the case may be, shall also be deemed to include the plural or the singular term, respectively;

(b) references herein to the “Regulations” shall be construed as a reference to these Regulations as amended or modified by the Commission from time to time in accordance with the applicable laws in force;

(c) the headings are inserted for convenience and may not be taken into account for the purpose of interpretation of these Regulations;

(d) references to the Statutes, Regulations or Guidelines shall be construed as including all statutory provisions consolidating, amending or replacing such Statutes, Regulations or Guidelines, as the case may be;

(e) in case of dispute in interpretation between English and Hindi version of these Regulations, the English version shall prevail.

CHAPTER 1

TARIFF PETITION AND PROCEDURE FOR DETERMINATION OF TARIFF

3. General Principles

(1) The Commission shall determine the Intra-State Transmission Tariff every year during five-year control period under a Multi-Year Tariff framework based upon the principles specified in these Regulations.

(2) The Transmission Licensee shall file an annual petition complete in all respect every year during control period for True-up of ARR for previous year, APR of current year and ARR / Tariff of ensuing year in such form and in such manner as specified in these Regulations along with relevant formats, duly supported with detailed computations, by 30th November of each year as per table below:

Table 1: Details of Petitions to be filed under the Control Period

Filing date	True- Up	APR	ARR / Tariff
30.11.2024	FY 2023-24*	FY 2024-25*	FY 2025-26**
30.11.2025	FY 2024-25***	FY 2025-26	FY 2026-27
30.11.2026	FY 2025-26	FY 2026-27	FY 2027-28
30.11.2027	FY 2026-27	FY 2027-28	FY 2028-29
30.11.2028	FY 2027-28	FY 2028-29	FY 2029-30

**The Petitions have already been filed as per UPERC (Multi-Year Tariff for Distribution & Transmission Tariff) Regulation, 2019.*

***As per the directions of the Commission, the Petitions have already been filed. Further submissions will be sought as per these Regulations for determination of ARR for FY 2025-26.*

****The filings shall be as per UPERC (Multi-Year Tariff for Distribution & Transmission Tariff) Regulation, 2019, however, filings have to be made on 30th November of the respective year as per these Regulations.*

Provided that True-up of ARR of Transmission Licensee for those years falling under past control period shall be filed by Transmission Licensee in such form and in such manner as specified in UPERC (Multi- Year Tariff for Distribution & Transmission Tariff) Regulations, 2019.

(3) STU shall file the annual Petition for True-up of TTSC (Total Transmission System Cost) for previous year, APR of current year and TTSC of ensuing year for determination of Intra State Transmission Tariff in such form and in such manner as specified in these Regulations along with relevant formats, duly supported with detailed computations, by 30th November of each year:

Provided that Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd. in the capacity of State Transmission Utility shall file a single Petition for compliance of clause 2 and clause 3 of these Regulations till functions of STU are assigned to a separate entity.

(4) The Transmission Licensee shall file the True-Up/ APR/ ARR Petition, in accordance with the guidelines and formats as may be prescribed by the Commission, electronically on e-filing portal of the Commission, after due authorization by the Board of Directors or by any Committee/person authorised by the Board in this regard, digitally signed by the authorized representative:

Provided that the Capital Investments of Transmission Licensee without prior approval of the Commission shall not be included in the ARR Petition.

(5) Hard copies of the Petition shall also be filed as provided for in the UPERC (Conduct of Business) Regulations, 2019, as amended from time to time, accompanied with applicable fees as per the UPERC (Fee and Fines) Regulations, 2010 as amended from time to time:

Provided that the fees for filing Petition under these Regulations by STU shall be exempted till functions of STU are assigned to a separate entity.

(6) The Petitioner shall furnish to the Commission all such books and records (or certified true copies thereof), including the audited/ provisional Accounting Statements, operational, cost and Performance related data as may be required by it. The Petition filed by the Transmission Licensee/ STU, as the case may be, shall comprise and be accompanied by the requisite information, which shall include but not limited to the following information:

(i) ARR/Tariff Filing

(a) The Transmission System or network usage forecast for the year, Projected Transmission Capacity, Circuit line length, Number of Sub-Stations, Capital Investment Plan, Financing Plan and Physical targets, Equity, Grants, etc.

(b) Projected list of Schemes as approved under STU Transmission Plan that will be Capitalised during the year by the Transmission Licensee;

(c) Proposal(s) for transmission charges including the transmission losses for the year supported by adequate justification;

(d) Expected Revenue from the Licensed Business, Non-Tariff Income and income from Other Business and other matters considered appropriate by the Transmission Licensee.

(ii) Annual Performance Review

(a) The Actual (as on date of filing of Petition) vs Projected Transmission Capacity, Circuit line length, Number of Sub-Stations, Capital Investment Plan, Financing Plan and Physical targets, Equity, Grants, etc.

(b) Details of Capital expenditure and additional capital expenditure incurred during the period under review along with supporting documents.

(c) Provisional Statement of Accounts and trial balance for six months for the current financial year.

(iii) True Up

(a) Actual vs Projected Transmission Capacity, Circuit line length, Number of Sub-Stations, Capital Investment, Financing Plan and Physical targets, Equity, Grants, etc.

(b) Details of scheme wise capitalisation viz á viz with approval obtained from the Commission;

(c) Year wise asset register indicating capitalisation and depreciation;

(d) Statement of source of financing including equity infusion;

(e) Loan utilisation certificate for all the loans availed by the Transmission Licensee during the relevant year duly reconciled with Statutory books of accounts including;

(i) Capital Expenditure

(ii) Capital work in Progress

(iii) Working Capital

(f) Gain/loss sharing with respect to controllable parameters;

(g) Audited Statement of Accounts and trial balance;

Any other detail in as specified in these Regulations or as required by the Commission from time to time.

Provided that if the true-up petition is not submitted within timelines as stipulated in these Regulations, no carrying cost for the period of delay shall be allowed for the gap arrived for the true-up year. However, in case of surplus, the same with carrying cost shall be recovered:

Provided also that the Transmission Licensee shall submit a yearly statement on the status of compliance to Directives, issued by the Commission in the previous Tariff Order, along with the Petition.

(7) The Commission shall conduct a Technical Validation before admission of the Petition. On completion of the required proceedings and submissions made to the satisfaction of the Commission, the Commission will admit the Petition and shall issue an Admittance Order.

(8) The Petitioner shall within three working days of the issuance of the Admittance Order, publish a Public Notice in at least two English and two Hindi daily newspapers having wide circulation in its license area, outlining the True-Up/APR/ARR, proposed Tariff and such other matters as may be directed by the Commission, inviting suggestions and objections from the stakeholders and public at large:

Provided that the Petitioner shall also provide on its website the Petition filed before the Commission along with all regulatory filings, detailed computations, particulars and documents, in text-searchable format or in downloadable spreadsheet format in the manner stipulated by the Commission:

Provided also that the web link to the information mentioned in the first proviso to this Regulation should be easily accessible, archived for downloading and be prominently displayed on the Petitioner's website:

Provided also that Petitioner shall intimate its stakeholders about filing of such Petition, period of public consultation, date of Public Hearing *etc.* through appropriate notice on its website and newspapers:

Provided further that the Petitioner may be exempted by the Commission from providing any such information, particulars or documents considered confidential in nature.

(9) The Commission shall, within one hundred and twenty days from admittance, after considering all suggestions and objections received from the stakeholders and public at large and in accordance with the provisions contained in these Regulations:

(a) Issue an Order for True-Up/APR/ARR & Tariff accepting the Petition with such modifications or such conditions as may be specified in that Order; or

(b) Reject the Petition for reasons to be recorded in writing if such Petition is not in accordance with the provisions of the Act, Rules and Regulations made there under or any other provisions of law, after giving the Petitioner a reasonable opportunity of being heard.

(10) The State Transmission Utility shall publish the Intra State Transmission Tariff within three working days approved by the Commission in at least two English and two Hindi daily newspapers having wide circulation in its license area and shall upload the approved Tariff on its internet website both in English and Hindi.

(11) The Tariff so published shall be in force from the date stipulated in the Order and shall, unless amended or revised, continue to be in force for such period as may be stipulated therein.

(12) The Commission shall carry out Truing-Up exercise stipulated in the provisions of these Regulations. True-Up of Expenses and Revenue shall be on the basis of approved and actual expenses, revenue, *etc.*, based on the prudence check of Accounting Statements of the Transmission Licensee for the Financial Year.

4. Method for Determination of Tariff for augmentation/strengthening works executed by TBCB Transmission Licensee

(1) Implementation of augmentation/strengthening works at the intra-State transmission sub-station and /or line being part of the STU Transmission Plan shall be carried out by the respective TBCB Transmission Licensee in whose premises work is to be carried out:

Provided that the cost of the works, as approved by the Commission, shall be transferred by UPPTCL to the respective TBCB Transmission Licensee, which shall be passed on in the ARR of UPPTCL in accordance with these Regulations:

Provided further that Regulation 7.2 of UPERC (Modalities of Tariff) Regulations, 2023 shall stand superseded to the extent specified in these Regulations.

(2) UPPTCL shall take prior approval of these schemes/works and the Commission may approve the scheme along with such terms and conditions as considered appropriate.

(3) The Operation and Maintenance of such works shall be carried out by the respective developer for which Normative Repair & Maintenance expenses shall be transferred by UPPTCL to the respective developer/Transmission Licensee in whose premises work is to be carried out, as per tariff order issued by the Commission for the respective year.

(4) UPPTCL shall submit a procedure for finalisation of cost of works, bid process to be conducted by TBCB Transmission Licensee and its finalisation, transfer of funds for carrying out the works, funds for operation & maintenance requirements *etc.* within three months of the notification of these Regulations for approval of the Commission.

(5) The Commission through its Orders may issue directive to TBCB Transmission Licensee and may call for compliance status.

5. Controllable and Uncontrollable Factors

(1) The “Uncontrollable Factors” shall comprise the following factors, which were beyond the control of, and could not be mitigated by the Transmission Licensee, as determined by the Commission:

- (a) Force Majeure events;
- (b) Change in Law;
- (c) Variations in interest rates for Long term loan subject to prudence check;
- (d) Any other expenses allowed by the Commission.

(2) The “Controllable Factors” shall include, but shall not be limited to the following:-

- (a) Variations in Capital Expenditure on account of time and/ or cost overruns/ efficiencies in the implementation of capital expenditure project not attributable to an approved change in scope of such project or change in statutory levies or force majeure events, and due to delay in execution of the project on account of contractor, supplier or agency of the Transmission Licensee;
- (b) Provision for Write-off of Bad and Doubtful debts;
- (c) Variation in performance parameters and standards specified;
- (d) Variation in interest on working capital;
- (e) Variation in Intra-State Transmission losses;
- (f) Variation in expenses under any component(s) of Operation & Maintenance expenses;
- (g) Variation in availability of transmission system.

6. Treatment of Gains or Losses on account of Uncontrollable Factors

(1) The approved gain or loss to the Transmission Licensee on account of Uncontrollable Factors shall be adjusted in the ARR or Tariff of the Transmission Licensee, as stipulated in these Regulations and as may be determined in the Order of the Commission passed under these Regulations.

(2) The Transmission Licensee shall submit such details of the variation on account of Uncontrollable factors along with the detailed computations and supporting documents as may be required for verification by the Commission.

7. Treatment of Gains or Losses on account of Controllable Factors

(1) The financial gain or loss shall be computed with respect to each component of Operation & Maintenance expenses.

(2) The approved gain to the Transmission Licensee, as per clause 7 (1), shall be dealt with in the following manner:-

- (a) Two-third of the amount of such gain shall be passed on in Tariff/ARR over such period as may be stipulated in the Order of the Commission;
- (b) The balance amount of such gain shall be utilised at the discretion of the Transmission Licensee.

(3) The approved loss to the Transmission Licensee, as per clause 7 (1), shall be dealt with in the following manner:-

- (a) One-third of the amount of such loss shall be passed on in Tariff/ARR over such period as may be stipulated in the Order of the Commission;
- (b) The balance amount of such loss shall be absorbed by the Transmission Licensee.

CHAPTER- 2**DELAY IN COMMERCIAL OPERATION****8. Procedure for Delay in Commercial Operation**

(1) The Transmission Licensee (s) and/ or the Generating Company shall necessarily enter into an “implementation agreement” for the execution of transmission projects including interconnection facilities in a timely and coordinated manner to avoid any mismatch of commercial operation date.

(2) The date of commercial operation of a transmission system or element thereof and associated communication system shall be in accordance with the provisions of the Grid Code.

(3) In case the transmission system or element thereof executed by a Transmission Licensee is ready for commercial operation but the interconnected generating station or the transmission system of other Transmission Licensee, as per the agreed scheduled date of commissioning, is not ready for commercial operation, the Transmission Licensee may file a petition before the Commission for approval of the date of commercial operation of such transmission system or element thereof or proceed in terms of TSA approved by the Commission:

Provided that the Transmission Licensee seeking approval of the date of commercial operation under this clause shall give prior notice of at least one month, to the Generating Company and/ or the other Transmission Licensee and the long-term customers of its transmission system, as the case may be, regarding the date of commercial operation:

Provided further that the Transmission Licensee seeking the approval of the date of commercial operation of the transmission system under this clause shall be required to submit the following documents along with the petition:-

(a) Clearance for Energisation issued by the Electrical Inspector;

(b) Trial operation certificate issued by the SLDC for charging element with or without electrical load;

(c) Implementation Agreement, Connection agreement, executed by the parties;

(d) Notice issued by the Transmission Licensee as per the first proviso under this clause and the response;

(e) Certificate of the Competent Authority of the company regarding the completion of the transmission system including associated communication system in all respects;

(4) The Commission shall, on consideration of the submissions of the Transmission Licensee as aforesaid, shall pass such orders or give such directions as may be necessary.

9. Commercial Settlement in case of Mismatch in Date of Commercial Operation

(1) In case of mismatch of the date of commercial operation of the Generating Station or Transmission Licensee (s) with the transmission system of TBCB developer, the liability for the transmission charges of TBCB Transmission licensee shall be determined as under: -

(a) Where the generating station has not achieved the commercial operation as on the date of commercial operation of the associated transmission system (which is not before the SCOD of the generating station), the Generating Company shall be liable to pay the transmission charges of the associated transmission system as approved by the Commission to the TBCB Transmission Licensee till the generating station or unit thereof achieves commercial operation;

(b) Where the transmission system of the Transmission Licensee(s) has not achieved the commercial operation as on the date of commercial operation of the interconnected transmission system of TBCB Transmission Licensee (which is not before the SCOD of the transmission system), the said Transmission Licensee shall be liable to pay the transmission charges of such interconnected transmission system to the TBCB Transmission Licensee as approved by the Commission till the transmission system achieves the commercial operation:

Provided that in case of default by more than one entity, the liability for the transmission charges of TBCB Transmission Licensee shall be shared in equal ratio by the defaulting entities until the default is rectified by any of the entity. Upon rectification of the default by any entity, the entire liability shall be equally shared amongst the remaining defaulting entity/ies again in equal ratio among the defaulting parties until there remains only one defaulting party in which case entire liability of transmission charges shall be on the same defaulting party till it cures its default.

(2) The Commission shall, on consideration of the submissions of the Transmission Licensee as aforesaid, pass such orders or give such directions as may be necessary.

CHAPTER- 3 **FINANCIAL PRINCIPLES**

10. Financial Prudence

(1) The Transmission Licensee shall manage its finances in an optimum and prudent manner.
(2) In determining the ARR and Tariff of the Transmission Licensee, the Commission shall assess the financial prudence with regard to the following factors:-

(a) Whether projected capital expenditure and capitalisation is based on realistic estimates, and adequate justification has been provided for any anomalous increase in capital expenditure and capitalisation projected by the Transmission Licensee;

(b) Mechanism put in place for monitoring the physical progress of projects with respect to their original schedule;

(c) Optimum drawal of loans in accordance with the physical progress of the capital expenditure schemes, and efficient utilisation of such loans;

(d) In case the actual capital expenditure and capitalisation during the year varies more than 10% of that approved under STU Transmission Plan by the Commission, the Transmission Licensee shall submit a detailed justification for such variation along with its True-Up Petition;

(e) In case any scheme has not been commenced during the year despite the Commission's approval, detailed justification shall be submitted along with the Petition for True-Up;

(f) Creation of assets in accordance with Capex Plan approved by the Commission along with their retirement, replacement or deletion/adjustments;

(g) Procurement of Goods and Services in competitive and transparent manner;

(h) Proper recording of assets in Fixed Asset Register;

(i) Whether the procured asset, such as land, has actually been put to use;

(j) Mechanism put in place for monitoring adherence to the approved expenditure, including schedule of interest payments for long-term loans and working capital.

11. Capital Expenditure/ Cost and Capital Structure

(1) Capital cost for a Capital investment project shall include,-

(a) The expenditure incurred or projected to be incurred, including interest during construction and financing charges, as admitted by the Commission after prudence check;

(b) Capitalised initial spares subject to the ceiling rates stipulated in these Regulations;

(c) Expenses incurred by the Transmission Licensee on obtaining right of way, as admitted by the Commission after prudence check;

(d) Additional capital expenditure determined under clause 12 of these Regulations;

(e) Incidental expenditure during construction including apportioned expenditure on relevant components of O&M;

(f) Any gain or loss on account of foreign exchange risk variation pertaining to the loan amount availed up to the date of commercial operation, as admitted by the Commission after prudence check;

Provided that any gain or loss on account of foreign exchange risk variation pertaining to the loan amount availed up to the date of commercial operation shall be adjusted only against the debt component of the capital cost:

Provided further that the capital cost of the assets forming part of the Project but not put to use or not in use, shall be excluded from the capital cost:

Provided also that the Transmission Licensee shall submit documentary evidence in support of its claim of assets being put to use.

(2) The capital cost admitted by the Commission after prudence check shall form the basis for determination of Tariff.

(3) The actual capital expenditure on a Project as on COD for the original scope of work based on audited accounts of the Transmission Licensee, as the case may be, shall be considered subject to prudence check by the Commission.

(4) Capital cost to be allowed by the Commission for the purpose of determination of Tariff will be based on the Transmission Plan prepared by the STU under Modalities of Tariff Determination Regulation, 2023 and Annual Capital Investment Plan approved by the Commission.

(5) The capital cost may include initial spares capitalised as a percentage of the Plant and Machinery cost up to the cut-off date, subject to the following ceiling norms:-

(a) Transmission System	
(i) Transmission Line:	1.0 %
(ii) Transmission Sub-Station (AIS):	
Green field	4.0 %
Brown field	6.0 %
(iii) Gas Insulated/Hybrid Sub-Station (GIS/HGIS):	
Green field	5.0 %
Brown field	7.0 %
(iv) Series compensation devices and HVDC Sub-Station	4.0 %
(v) Static Synchronous Compensator:	6.0 %
(vi) Communication System:	3.5 %
(b) Battery Energy Storage System:	1.0 %

(6) The impact of revaluation of assets shall be permitted provided it does not result in increase in Tariff of the Transmission Licensee:

Provided that any benefit from such revaluation shall be passed on to long-term Intra-State Open Access Customers of the Transmission Licensee, at the time of ARR / Tariff determination or Truing-Up, as the case may be.

(7) Any expenditure on replacement, Renovation and Modernisation or extension of life of old fixed assets, as applicable to Transmission Licensees, shall be considered after writing off the net value of such replaced assets from the original capital cost, and shall be computed as follows,-

Net Value of Replaced Assets = OCRA – AD;

Where;

OCRA: Original Capital Cost of Replaced Assets;

AD: Accumulated depreciation pertaining to the Replaced Assets:

Provided that in case the original capital cost of the replaced asset is not available for any reason, it shall be considered by the Commission on a case to case basis:

Provided further that the amount of insurance proceeds received, if any, towards damage to any asset requiring its replacement shall be first adjusted towards outstanding actual or normative loan; and the balance amount, if any, shall be utilised to reduce the capital cost of such replaced asset, and any further balance amount shall be considered as Non-Tariff Income.

12. Additional Capitalisation

A. Additional Capitalisation within the original scope and up to the cut-off date

(1) The additional capital expenditure in respect of a new project or an existing project, on the following counts within the original scope of work as per Detailed Project Report (DPR), actually incurred after the date of commercial operation and up to the cutoff date may be admitted by the Commission, subject to prudence check:

(a) Deferred liabilities;

(b) Works deferred for execution;

(c) Procurement of initial capital spares in the original scope of work, subject to ceiling specified in these Regulations;

(d) Payment against the award of arbitration or for compliance of the directions or order of any statutory authority or order or decree of a Court;

(e) On account of change in law or compliance with any existing law which is not provided for in the original scope of work;

(f) Force majeure events;

Provided that original scope of work along with estimates of expenditure shall be submitted along with the application for provisional and final tariff:

Provided that in case of any replacement of the assets, the additional capitalization shall be worked out after adjusting the gross fixed assets and cumulative depreciation of the assets replaced on account of de-capitalization:

Provided further that a list of the deferred liabilities to be payable at a future date and works deferred for execution shall be submitted along with the application for final tariff after the date of commercial operation.

B. Additional Capitalisation within the original scope and after the cut-off date

(1) The additional capital expenditure actually incurred in respect of an existing project or a new project on the following counts within the original scope of work and after the cut-off date may be admitted by the Commission, subject to prudence check:

(a) Payment made against award of arbitration or for compliance of the directions or order of any statutory authority, or order or decree of a Court;

(b) Change in Law or compliance with any existing law which has not been provided for in the original scope of work;

(c) Force majeure events;

(d) Payment made towards liability admitted for works within the original scope executed prior to the cut-off date;

(e) Works within original scope executed after the cut-off date and admitted by the Commission, to the extent of actual payments made.

(2) In case of replacement of assets deployed under the original scope of the existing project after the cut-off date, the additional capitalization may be admitted by the Commission after making necessary adjustments in the gross fixed assets and the cumulative depreciation, subject to prudence check on following grounds:-

(a) Assets whose useful life is not commensurate with the useful life of the project and such assets have been fully depreciated in accordance with the provisions of these Regulations;

(b) The replacement of the asset or equipment is necessary on account of a change in law or Force Majeure conditions; or

(c) The replacement of such asset or equipment is necessary on account of obsolescence of technology; or

(d) The replacement of such asset or equipment has otherwise been allowed by the Commission.

C. Additional Capitalisation beyond the original scope

(1) The capital expenditure, in respect of the existing transmission project incurred on the following counts beyond the original scope, may be admitted by the Commission, subject to prudence check:-

(a) Payment made against award of arbitration or for compliance of order or directions of any statutory authority, or order or decree of any court of law;

(b) Change in law or compliance of any existing law;

(c) Force Majeure events;

(d) Need for higher security and safety of the project as advised or directed by appropriate Indian Government Instrumentality or statutory authorities responsible for national or internal security;

Provided also that if any expenditure has been claimed under Renovation and Modernisation (R&M) or repairs and maintenance under O&M expenses, the same shall not be claimed under this Regulation.

13. Operation and Maintenance Expenses

(1) The Operation and Maintenance (O&M) expenses for the Transmission Licensee shall be computed for three components *i.e* (i) Employee Expenses, (ii) Repair and Maintenance (R&M) Expenses, and (iii) Administrative and General Expenses.

(2) The Norms for each component of O&M Expenses shall be determined as per these Regulations. Thereafter O&M Expenses for each year of the Control Period shall be computed based on the formula shown below:

$$O\&M_n = EMP_n + R\&M_n + A\&G_n$$

Where:

O&M_n - O&M expenses for nth year

EMP_n - Employee expenses for nth year

R&M_n - R&M expenses for nth year

A&G_n - A&G expenses for nth year

(3) At the time of Truing-Up, gains or losses for each component of Operation and Maintenance Expenses shall be shared as per clause 7 of these Regulations.

(4) The impact of Pay Revision, change in Pension Scheme etc., shall be allowed by the Commission over and above normative Expenses of the respective component after prudence check. However, one-time expenses such as payment of Arears due to impact of pay revision, change in pension scheme etc., shall not be considered for the determination of norm of the respective component.

(5) In case data required for establishing the norms is not available, the Transmission Licensee shall propose O&M norms with justification. The Commission shall approve the norms for the Transmission Licensee after prudence check which shall be applicable for the remaining Control Period.

(6) Employee Cost

(a) The Employee Cost shall be derived on the basis of the average of the values in the Audited Accounts for the last five (5) financial years ending March 31, 2025 subject to prudence check by the Commission. However, if Audited Accounts are not available for FY 2024-25, Audited Accounts available for the last five (5) years will be considered and subsequently when the same are available the base year value (i.e. FY 2024-25) will be recomputed.

(b) The average of such Employee Cost shall be considered as Employee Cost for the middle year of the previous Control Period (01.04.2020 to 31.03.2025) and shall be escalated year on year with the escalation factor considering CPI of respective years, for subsequent years up to FY 2024-25:

Provided that impact of one time expenses such as Arears due to impact of pay revision, change in pension scheme etc. shall be removed from the base Employee Cost.

After arriving the figure of FY 2024-25, the normative employee expenses shall be computed as per formula below:

$$EMP_n = EMP_{n-1} \times (1 + \text{CPI inflation}) \times (1 + G_n)$$

Where:

EMP_n: Employee expense for the nth year;

EMP_{n-1}: Employee expense for the (n-1)th year;

For the purpose of ARR, CPI inflation is the average of Consumer Price Index (CPI) for Industrial Workers (All India) as per Labour Bureau, Government of India for the immediately preceding three Financial Years.

For the purpose of True-Up, CPI inflation is the actual point to point inflation for the concerned Financial Year.

G_n is a growth factor for the nth year and it may be greater than or less than zero based on the actual performance. Value of G_n shall be determined by the Commission in the Tariff Order for meeting the additional manpower requirement based on the Licensees' filing, benchmarking or any other factor that the Commission feels appropriate.

(7) Repairs and Maintenance Expense

The normative Repair and Maintenance expense for first year of Control period shall be allowed at the rate of 2% of the opening GFA of the year as approved by the Commission. The normative Repair and Maintenance expense for subsequent years of the control period, shall be allowed at 2% of the incremental GFA of the respective year in addition to the normative R&M value of previous year along with an annual escalation based on the Wholesale Price Index (WPI) inflation:

Provided that the normative R&M expense determined as per the above stipulation shall be inclusive of any impact of change in applicable taxes or duties.

For the purpose of ARR, WPI inflation is the average of Wholesale Price Index (WPI) for immediately preceding three Financial Years as per the Office of Economic Advisor of Government of India.

For the purpose of True-Up, WPI inflation is the actual point to point inflation for the concerned Financial Year.

(8) Administrative and General Expenses

(a) The normative A&G Expenses shall be derived on the basis of the average of the values in the Audited Accounts for the last five (5) financial years ending March 31, 2025 subject to prudence check by the Commission. However, if Audited Accounts are not available for FY 2024-25, Audited Accounts available for the last five (5) financial years of previous Control Period (01.04.2020 to 31.03.2025) will be considered and subsequently when the same are available the base year value (i.e. FY 2024-25) will be recomputed.

(b) The average of such A&G Expenses shall be considered as A&G Expenses for the middle year and shall be escalated year on year with the escalation factor considering WPI of respective years, for subsequent years up to FY 2024-25.

(c) A&G expense shall be computed as per the following formula escalated by wholesale price index (WPI) and adjusted by provisions for confirmed initiatives (IT etc. initiatives as proposed by the Transmission Licensee and validated by the Commission) or other expected one-time expenses:

After arriving the figure of FY 2024-25, the normative A&G expenses shall be computed as per formula below:

$$A\&G_n = A\&G_{n-1} (1 + \text{WPI inflation}) + \text{Provision}$$

Where:

$A\&G_n$: A&G expense for the n^{th} year;

$A\&G_{n-1}$: A&G expense for the $(n-1)^{\text{th}}$ year;

For the purpose of ARR, WPI inflation is the average of Wholesale Price Index (WPI) for immediately preceding three Financial Years as per the Office of Economic Advisor of Government of India:

For the purpose of True-Up, WPI inflation is the actual point to point inflation for the concerned Financial Year.

Provision: Cost for initiatives which entail conversion of Capex projects into Totex or Opex mode or are undertaken to ensure compliance of any directives of the Commission or any other Expense as may be allowed by the Commission on the proposal of Transmission Licensee.

14. Debt-Equity

(1) Closing balance of Equity as on 31.03.2025 approved by the Commission shall be taken as the opening Equity for Financial Year 2025-26.

(2) For a capital investment scheme declared under commercial operation on or after April 1, 2025, debt-equity ratio as on the date of commercial operation shall be 70:30 of the amount of capital cost approved by the Commission under clause 11 of these Regulations after making appropriate adjustment of Assets funded by Consumer Contribution/ Deposit Works/ Capital Subsidies/ Grant, subject to prudence check for determination of Tariff:

Provided that if the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in excess of 30% shall be treated as normative loan for the Transmission Licensee for determination of Tariff:

Provided further that the Transmission Licensee shall submit documentary evidence for the actual deployment of equity and explain the source of funds for the equity:

Provided also that where equity actually deployed is less than 30% of the capital cost of the capitalised asset, the actual equity shall be considered for determination of Tariff:

Provided also that the equity invested in foreign currency shall be designated in Indian Rupees on the date of each investment:

Provided that in case of retirement or replacement or de-capitalisation or deletion/adjustment of the assets, the equity capital approved as mentioned above, shall be reduced to the extent of 30% (or actual equity component based on documentary evidence, if it is lower than 30%) of the original cost of such assets:

Provided further that in case of retirement or replacement or deletion/ adjustment or de-capitalisation of the assets, the debt capital approved as mentioned above, shall be reduced to the extent of the outstanding debt component based on documentary evidence, or the normative loan component, as the case may be, of the original cost of such assets.

15. Depreciation

(1) The Transmission Licensee, shall be permitted to recover Depreciation on the value of fixed assets used in their respective businesses, computed in the following manner:

(a) The approved original cost of the fixed assets shall be the value base for the calculation of Depreciation:

Provided that the Depreciation shall be allowed on the entire capitalised amount of the new assets after reducing the approved original cost of the retired or replaced or de-capitalised assets.

(b) Depreciation shall be allowed annually based on the Straight- Line Method at the rates stipulated in the Annexure- A for existing Assets (capitalised on or before 31.03.2025) and at the rates stipulated in Annexure- B for Assets capitalised during the Control Period:

Provided that the Licensee shall ensure that once individual asset is depreciated to the extent of seventy percent, the remaining depreciable value as on 31st March of the year closing shall be spread over the balance Useful Life of the assets including the Extended Life, as per submission of the Licensee and approval by the Commission.

(c) The salvage value of the asset shall be considered at 10% of the allowable capital cost and Depreciation shall be allowed up to a maximum of 90% of the allowable capital cost of the asset:

Provided that land owned shall not be treated as a Depreciable asset and shall be excluded from the capital cost while computing Depreciation:

Provided further that Depreciation shall be chargeable from the first year of commercial operation:

Provided that the salvage value of the IT equipment, software and underground cable shall be considered as nil and value of such assets shall be considered 100% depreciable.

(d) Depreciation shall not be allowed on assets funded by Consumer Contributions or Subsidies/ Grants/ Deposit works.

(2) In case of existing assets, for the purpose of computation of depreciation, the opening value of GFA shall be taken as the closing value as on March 31, 2025 as approved by the Commission in its Tariff Order.

(3) In case of projected commercial operation of the assets for part of the year, depreciation shall be computed based on the average of opening and closing value of assets:

Provided that the depreciation shall be re-computed for assets capitalised at the time of Truing-Up, based on Accounting Statements and documentary evidence of assets capitalised by the Petitioner, subject to prudence check of the Commission.

16. Return on Equity

Return on equity shall be computed in ₹ terms on equity base at the rate of 14.5% post-tax per annum (hereinafter referred to as 'Base Rate') for the Transmission Licensee as determined in accordance with clause 14 of these Regulations:

Provided that assets funded by Consumer Contribution / Deposit works, Capital Subsidies / Grants and corresponding Depreciation shall not form part of the Capital Cost.

17. Interest on Long- Term Loan

(1) The long- term loans arrived at in the manner indicated in these Regulations on the assets put to use shall be considered as gross normative loan for calculation of interest on loan:

Provided that in case of retirement or replacement or de-capitalisation or deletion/adjustment of the assets in the balance sheet, the loan capital approved as mentioned above shall be reduced to the extent of outstanding loan component of the original cost of such assets based on documentary evidence.

(2) The closing normative long- term loan outstanding as on March 31, 2025, shall be taken as the opening normative long term loan outstanding for the financial year 2025-26.

(3) The repayment of long-term loans for each year shall be deemed to be equal to the depreciation allowed for that year.

(4) Notwithstanding any moratorium period availed, the repayment of loan shall be considered from the first year of commercial operation of the asset.

(5) The rate of interest for ensuing year shall be the weighted average rate of interest computed on the basis of the actual long- term loan portfolio of previous year:

Provided that if there is no actual long- term loan for a particular year but the normative loan is still outstanding, then the rate of interest for the purpose of allowing the interest on the normative long-term loan shall be the weighted average of SBI MCLR (1 year) prevailing during the previous year plus 100 basis points.

(6) At the time of Truing-Up, the weighted average rate of interest of the actual long- term loan portfolio during the concerned year shall be considered as the rate of interest:

Provided that if there is no actual long-term loan for a particular year but the normative loan is still outstanding, then the rate of interest for the purpose of allowing the interest on the normative long-term loan shall be the weighted average of SBI MCLR (1 year) prevailing during the concerned year plus 100 basis points.

(7) The interest on long- term loan shall be computed on the normative average long- term loan of the year by applying the weighted average rate of interest:

Provided that at the time of Truing-Up, the normative average loan of the concerned year shall be considered on the basis of the actual asset capitalisation approved by the Commission for the year.

18. Banking and Finance Charges

The Banking & Finance charges shall be allowed as per actuals in Truing-Up, subject to prudence check by the Commission:

Provided that the Banking and Finance charges shall be allowed in ARR as per the approval given by the Commission for the latest True-Up year.

19. Interest During Construction (IDC)/Incidental Expenditure During Construction (IEDC)

(1) Interest during construction (IDC) shall be computed considering the actual loan and normative loan after taking into account the prudent phasing of funds up to actual COD:

Provided also that IDC on a normative loan corresponding to excess equity over 30% of funds deployed shall be allowed only in cases where the actual infusion of equity on a pari-passu basis is more than 30% of total funds deployed and shall be computed on a quarterly basis:

Provided further that in case IDC on normative loan is to be allowed prior to infusion of actual loan, rate of interest for computing such IDC shall be equal to 1-year SBI MCLR as prevailing on 1st April of the respective year:

Provided further that IDC on normative loan, post infusion of actual loan shall be computed based on weighted average rate of interest (WAROI) for that respective quarter:

Provided further that the IDC on normative loan shall be allowed only when it can be demonstrated by the Licensee that the capital cost arrived after IDC on normative loan is to the benefit of consumers.

(2) Incidental expenditure during construction (IEDC) shall be computed from the zero date, taking into account pre-operative expenses up to actual COD:

Provided that any revenue earned during the construction period up to actual COD on account of interest on deposits or advances or any other receipts shall be taken into account for reduction in incidental expenditure during construction.

(3) In case of additional costs on account of IDC and IEDC due to delay in achieving the COD, the Transmission Licensee shall be required to furnish detailed justifications with supporting documents for such delay, including prudent phasing of funds in the case of IDC and details of IEDC during the period of delay and liquidated damages recovered or recoverable corresponding to the delay.

(4) If the delay in achieving the COD is not attributable to the Transmission Licensee, such additional IDC and IEDC may be allowed after prudence check, and the liquidated damages, if any, recovered from the contractor or supplier or agency shall be adjusted to the capital cost of the transmission system.

(5) If the delay in achieving the COD is attributable either in entirety or in part to the Transmission Licensee or its contractor or supplier or agency, in such cases, IDC and IEDC due to such delay may be disallowed after prudence check, either in entirety or on a pro-rata basis corresponding to the period of delay not condoned vis-à-vis total implementation period, and the liquidated damages, if any, recovered from the contractor or supplier or agency shall be retained by the Transmission Licensee, in the proportion of delay not condoned vis-à-vis total implementation period:

Provided that in cases where delay in achieving COD is beyond six months from SCOD on account of delay in obtaining approval of any of the following activities namely, (i) forest clearance, (ii) NHAI clearance, or (iii) Railways permission, a time overrun maximum up to 95% shall be allowed after prudence check.

(6) For the purpose of sub-clauses (4) and (5) of clause 19 of these Regulations, IDC on actual loan and normative loan shall be considered in accordance with the normative debt-equity ratio specified under sub-clause (2) of clause 14 of these Regulations.

20. Hedging Cost of Foreign Exchange Rate Variation (FERV)

(1) The Transmission Licensee may hedge foreign exchange exposure in respect of the interest on foreign currency loan and repayment of foreign loan acquired, in part or in full, at the discretion of the Transmission Licensee.

(2) The Transmission Licensee shall recover the cost of hedging and foreign exchange rate variation on a year-to-year basis as income or expense in the period in which it arises. However, the same shall be allowed subject to prudence check by the Commission at the time of True-Up.

21. Interest on Working Capital

(1) The working capital requirement of the Transmission Licensee shall cover:

- (a) Operation and Maintenance expenses for one month;
- (b) Maintenance spares at 40% of the R&M expenses for two months; and
- (c) One-and-a-half-month equivalent of the expected revenue from transmission charges at the prevailing Tariff;

minus

- (d) Amount held as security deposits, if any, from Transmission System Users:

Provided that if the working capital, determined based on the above formula, is positive, it shall be reduced by the amount of revenue surplus (if any) as of 31st March of the previous year so approved by the Commission:

Provided further that for the purpose of Truing- Up for any year, the working capital requirement shall be re-computed on the basis of the values of components of working capital approved by the Commission in the Truing- Up.

(2) Rate of interest on working capital for ensuing year shall be simple interest and shall be equal to the SBI MCLR (1-year) as on date on which Petition for determination of Tariff is filed plus 200 basis points:

Provided that for the purpose of Truing- Up for any year, simple interest on working capital shall be allowed at a rate equal to the weighted average SBI MCLR (1-year) prevailing during the concerned year plus 200 basis points.

22. Tax on Return on Equity

(1) The rate of return on equity as allowed by the Commission under clause 16 of these Regulations shall be grossed up with the effective tax rate (hereinafter referred to as 't') of the respective financial year. The effective tax rate shall be calculated at the beginning of every financial year based on the estimated profit and tax to be paid estimated in line with the provisions of the relevant Finance Act applicable for that financial year to the concerned Transmission Licensee by excluding the income of other business and the corresponding tax thereon:

Provided that tax on any income other than that through its Licensed Business shall not be pass through and it shall be payable by the Licensee itself:

Provided that in case a Transmission Licensee is paying Minimum Alternate Tax (MAT) under Section 115JB of the Income Tax Act, 1961, the effective tax rate shall be the MAT rate, including surcharge and cess:

Provided further that in case a Transmission Licensee has opted for Section 115BAA, the effective tax rate shall be the tax rate including surcharge and cess as specified under Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961.

(2) The rate of return on equity shall be rounded off to three decimal places and shall be computed as per the formula given below.

Rate of pre-tax return on equity = Base rate / (1-t)

(3) The Transmission Licensee shall true up the effective tax rate for every Financial Year based on the actual tax paid together with any additional tax demand, including interest thereon, duly adjusted for any refund of tax including interest received from the income tax authorities pertaining to the Tariff period covered under these Regulations on actual gross income of any Financial Year. Further, any penalty arising on account of delay in deposit or short deposit of tax amount shall not be considered while computing the actual tax paid by the Transmission Licensee:

Provided that in case a Transmission Licensee is paying Minimum Alternate Tax (MAT) under Section 115JB, the Transmission Licensee shall true up the grossed up rate of return on equity at the end of every Financial Year with the applicable MAT rate including surcharge and cess:

Provided that in case a Transmission Licensee is paying tax under Section 115BAA, the Transmission Licensee shall true up the grossed up rate of return on equity at the end of every Financial Year with the tax rate including surcharge and cess as specified under Section 115BAA:

Provided that any under-recovery or over recovery of grossed up rate on return on equity after truing-up, shall be recovered or refunded, on a year to year basis.

23. Non-Tariff Income

(1) The amount of Non-Tariff income relating to the Transmission Business as approved by the Commission shall be deducted from the ARR in determining the Annual Transmission Charges of the Transmission Licensee:

Provided that the Transmission Licensee shall submit full details of its forecast of Non-Tariff income to the Commission in such form as may be stipulated by the Commission.

(2) The Non-Tariff Income shall include:

- (a) Income from rent of land or buildings;
- (b) Income from sale of scrap;
- (c) Income from investments:

Provided that income arising from investment of shareholder's funds, if any, shall not be included in Non-Tariff Income subject to prudence check of requisite detailed information submitted by the Transmission Licensee before the Commission.

- (d) Interest income on advances to suppliers/contractors;
- (e) Interest income on loans / advances to employees;
- (f) Income from rental from staff quarters;
- (g) Income from rental from contractors;
- (h) Income from hire charges from contractors and others;
- (i) Income from Supervision Charge;
- (j) Income from advertisements;

- (k) Income from sale of tender documents;
- (l) Excess found on physical verification;
- (m) Income from Insurance Claim;
- (n) Prior Period Income;
- (o) Miscellaneous receipts; and
- (p) Any other Non-Tariff Incomes:

(3) The Non-Tariff income under item (j) above (income from advertisements) shall be shared between the Transmission Licensee and the consumers in the ratio of 30% and 70% respectively:

Provided that the Transmission Licensee shall undertake asset monetisation study within six months from the date of notification of these Regulations.

24. Income from Other Business

(1) Where the Transmission Licensee has engaged in any Other Business under Section 41 of the Act for optimum utilisation of its assets, the income from such business will be deducted from the ARR in calculating the revenue requirement of the Transmission Licensee in the manner and in proportion as may be stipulated by the Commission. The proportion of revenue from Other Business that shall be utilized in the Transmission business shall be as stipulated in UPERC (Treatment of Income of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2004 or any subsequent amendment thereof:

Provided that the Transmission Licensee shall follow a reasonable basis for allocation of all joint and common costs between the Transmission Business and the Other Business and shall submit the Allocation Statement, duly certified by the Board of Directors, to the Commission along with its Petition for determination of ARR:

Provided further that where the sum total of the direct and indirect costs of such Other Business exceeds the revenues from such Other Business, income from such other business shall be taken as zero.

25. Rebate, Incentive, Penalties and Miscellaneous

(1) All rebates or incentives earned by the Transmission Licensee shall be considered under its Non-Tariff Income, while all rebates or incentives given by the Transmission Licensee, as approved by the Commission, shall be allowed as an expense for the Transmission Licensee.

(2) The timeline and percentage rebate for payment of bills of transmission charges and late payment surcharge shall be as per the Tariff Order issued by the Commission from time to time.

(3) Penalties paid by the Transmission Licensee shall not be allowed as an expense for the Transmission Licensee:

Provided that penalties / compensation levied on the Transmission Licensee due to the reasons beyond its reasonable control, as corroborated by it with appropriate justification and supporting documents to satisfy the Commission, shall be allowed subject to prudence check.

(4) Carrying cost for the ARR gap of the Transmission Licensee will be provided by the Commission after prudence check at the interest rates as provided for working capital in these Regulations.

(5) The revenue surplus of the Transmission Licensee shall be first adjusted towards working capital requirement for the year and balance revenue surplus amount, if any, shall be eligible for carrying cost as per weighted average of bank rate published by RBI net of applicable tax rate for the relevant year:

Provided that the Transmission Licensee shall invest the revenue surplus amount in risk-free securities such as RBI bonds, Government Securities or fixed deposit receipts of scheduled banks only.

CHAPTER 4

OPERATIONAL PRINCIPLES

26. Components of Tariff

(1) The Transmission Charges for access to and use of the Intra- State Transmission System shall comprise any of the following components or a combination of the following components:-

- (a) Transmission System access charges;
- (b) Annual Transmission charges;

- (c) Per unit charges for energy transmitted;
- (d) Reactive energy charges:

Provided that the Reactive energy charges would be determined as per Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission Grid Code 2007 as amended from time to time or any Order issued by the Commission.

(2) Any person who is eligible to apply for access to the Intra- State Transmission System shall be entitled to obtain such access in accordance with the Regulations and Orders of the Commission governing Transmission Open Access and shall be liable to pay the charges for obtaining such access as stipulated in these Regulations and Orders.

(3) Where the access of the intending Transmission System User to the Intra-State Transmission System entails works of transmission lines or other transmission assets dedicated to such user, the Transmission Licensee shall be entitled to recover, through transmission system access charges, all expenses reasonably incurred on such works for providing access to such intending Transmission System User.

(4) Where the access of the intending Transmission System User entails other works, not covered under clause 26(3) of these Regulations relating to the Intra-State Transmission System, the Transmission Licensee shall recover the expenses relating to such works through annual transmission charges, in accordance with clause 26(10) under these Regulations.

(5) Where any works for obtaining access have been carried out by the intending Transmission System User, the Transmission Licensee shall be entitled to recover supervision charges at the rate of 15% of the cost of labour employed, cost of material, material handling and storage/inventory but excluding the establishment costs, for carrying out such works and shall not be entitled to recover any other expenses with regard to such works:

Provided that such supervision charges shall form part of the Non-Tariff Income of the respective Transmission Licensee and shall also be treated as O&M expense incurred by the intending Transmission System users, which shall be capitalised in the respective year of asset capitalisation.

(6) The works for providing access to the Intra-State Transmission System shall be maintained by the Transmission Licensee for the duration of the Bulk Power Transmission Agreement between the Transmission Licensee and the Transmission System User.

(7) Where the Transmission System User has paid for the works carried out to provide it access to the Intra-State Transmission System, the Transmission System User shall be entitled to the depreciated value (as per Companies Act 2013 and its amendments) of such works paid for by it upon termination of the Bulk Power Transmission Agreement:

Provided that where the Transmission System User has carried out the works to provide it access to the Intra-State Transmission System of the Transmission Licensee, the Transmission System User may be entitled to retain such works upon termination of the Bulk Power Transmission Agreement.

(8) The Transmission System access charges may be recovered by any one of the following methods, in accordance with the terms of the Bulk Power Transmission Agreement:-

- (a) As a one-time payment by the Transmission System User at the time of obtaining access; or
- (b) As a series of payments over the duration of the Bulk Power Transmission Agreement; or
- (c) As any combination of (a) and (b) above.

(9) Any dispute between the Transmission Licensee and the intending Transmission System User with regard to the works to be carried out to give access to the intending Transmission System User or with regard to the Transmission System access charges shall be referred to the Commission for adjudication or to such other forum as may be stipulated by the Commission.

(10) The ARR of the Transmission Licensee, shall comprise the following components:-

- (a) Operation and maintenance expenses;
- (b) Depreciation;
- (c) Interest on Loan Capital;

- (d) Interest on Working Capital;
- (e) Banking & Finance charges;
- (f) Return on Equity;
- (g) Tax on Return on Equity;

Minus:

- (h) Non-Tariff Income;
- (i) Income from other Business:

Provided that Depreciation, Interest on Loan Capital, Interest on Working Capital, Return on Equity, and Income Tax for Transmission Licensees shall be allowed in accordance with the provisions stipulated in Chapter 3 of these Regulations:

Provided further that the components of the ARR, corresponding to the transmission lines owned by the Transmission Licensee but conveying electricity to other States, being recovered in accordance with the Regulations and Orders of the Central Electricity Regulatory Commission, shall not be recovered from the Tariff determined under these Regulations:

Provided also that in case any such components have already been recovered through the Intra-State Transmission Tariff, then such excess recovery shall be deducted from the ARR of the Transmission Licensee for the future years, along with associated carrying cost, as applicable:

Provided also that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the time of Truing- Up based on audited accounts, on a case to case basis, if the income/expenses in that prior period have been allowed on actual basis, subject to prudence check:

Provided also that all penalties and compensation payable by the Transmission Licensee to any party for failure to meet any Standards of Performance or for damages, as a consequence of the Orders of the Commission-or Competent Courts, Authorities *etc.*, shall not be allowed to be recovered through the ARR:

Provided also that the Transmission Licensee shall maintain separate details of such penalties and compensation paid or payable by the Transmission Licensee, if any, and shall submit them to the Commission along with its Petition.

(11) The Annual Transmission Charges along with Intra State Transmission Tariff shall be determined by the Commission on the basis of a Petition for determination of Tariff as stipulated in these Regulations.

27. Capital Investment Plan

(1) The Transmission Licensee shall submit a detailed projected capital expenditure schemes being part of STU Transmission Plan, financing plan and physical targets for the ensuing year for strengthening and augmentation of the Intra-State Transmission System of the Transmission Licensee, meeting the requirement of load growth, improvement in quality of supply, reliability, metering, reduction in congestion, *etc.*, along with the Tariff Petition before the Commission.

(2) The Capital Investment Plan shall be a least cost plan for undertaking investments:

Provided that all capital expenditure projects of capital expenditure of value exceeding ₹ Twenty Crore must have prior approval of the Commission and shall be subject to prudence check:

Provided that the Capital Investment Schemes/Projects proposed by the Transmission licensee shall be for Intra- State transmission network including if any associated upstream/downstream works, and the Schemes/ Projects shall not be submitted in parts:

Provided further that any capital expenditure scheme/project based on the specific requirement of a Distribution Licensee shall be substantiated with necessary documentary evidence in the form of request for the same.

(3) The Transmission Licensee is required to undertake approval of all transmission schemes/projects with a capital expenditure of ₹ 20 Cr. and above. The Transmission Licensee is required to submit all such schemes qualifying the criteria through a separate petition on a quarterly basis for the prior approval of the Commission.

(4) The Capital Expenditure Scheme(s)/Project(s) submitted for prior approval of the Commission shall be accompanied by such information, particulars and documents as may be required including but not limited to the information such as number of bays, name, configuration and location of grid substations, substation capacity (MVA), transmission line length (circuit kilometres) showing the need for the proposed investments, alternatives considered, cost/benefit analysis and other aspects that may have a bearing on the transmission charges.

(5) The Transmission Licensee shall submit the list of capital expenditure schemes/Projects after the asset is put to use along with actual capital expenditure incurred, capitalisation and details of time overrun and cost overrun on a quarterly basis:

Provided that the Transmission Licensee shall submit the details of the scheme/project-wise asset capitalisation along with receipt of the Electrical Inspector certificate and other documents as may be prescribed by the Commission from time to time, at the end of each quarter.

(6) The Commission shall review actual capital expenditure incurred and capitalisation *vis-à-vis* the approved capital expenditure and capitalisation after the completion of scheme. The quarterly capitalization approved by the Commission shall form the basis for truing-up at the end of each year.

(7) The Transmission Licensee shall submit, along with the Petition for determination of ARR or along with the Petition for Annual Performance Review, as the case may be, details showing the progress of capital expenditure projects, together with such other information, particulars or documents as the Commission may require to assess such progress.

CHAPTER 5

NORMS OF OPERATION

28. Norms of Operation

(1) Target availability

(a) Normative Annual Transmission System Availability factor (NATSAF) shall be as under:

- (i) AC System : 98.00%
- (ii) HVDC bi-pole links and back-to-back Stations: 95.00%

(2) Auxiliary Energy Consumption in the Sub-station:

(a) AC System

The charges for auxiliary energy consumption in the AC Sub-station for the purpose of air-conditioning, lightning and consumption in other equipment shall be borne by the Transmission Licensee and are included in the normative operation and maintenance expenses.

(b) HVDC Sub-station

For auxiliary energy consumption in HVDC Sub-stations, the Central Government / State Government may allocate an appropriate share from one or more ISGS generating station. The charges for such power shall be borne by the Transmission Licensee and are included in the normative operation and maintenance expenses.

(3) The transmission charge payable for a calendar month for a Transmission System shall be:

$$\text{ARR} \times (\text{NDM/NDY}) \times (\text{TAFM/NATSAF})$$

Where,

ARR	= Aggregate Revenue Requirement specified for the year;
NATSAF	= Normative annual transmission availability factor, in per cent stipulated in these Regulations;
NDM	= Number of days in the month;
NDY	= Number of days in the Year; and
TAFM	= Transmission System Availability Factor for the month, in per cent, computed in accordance with Annexure- C to these Regulations;

Provided that the Transmission Licensee shall raise the bill for the transmission charge for a month based on its estimate of TAFM. Adjustments, if any, shall be made on the basis of the TAFM to be certified by the SLDC within 30 days from the last day of the relevant month.

CHAPTER 6

INTRA-STATE TRANSMISSION TARIFF AND SHARING OF TTSC

29. Determination of Intra-State Transmission Tariff

(1) The aggregate of the yearly revenue requirement for all Transmission Licensees shall form the "Total Transmission System Cost" (TTSC) of the Intra-State transmission system, to be recovered from the Transmission System Users (TSUs) for the respective year of the Control Period, in accordance with the following Formula:

$$TTSC = \sum_{i=1}^n ARR_i + \sum_{j=1}^m ATSC_j + \text{Adjustment for ATSC}$$

Where,

TTSC = Pooled Total Transmission System Cost of year of the Control Period;

n = Number of Transmission Licensee(s) with projects under Section 62 of the Act;

m = Number of Transmission Licensee(s) with projects under Section 63 of the Act;

ARR_i = Yearly revenue requirement approved by the Commission for i_{th} Transmission Licensee for the year of the Control Period as determined by the Commission under Section 62 of the Act;

$ATSC_j$ = Annual Transmission Service Charges (ATSC) of TBCB Projects adopted by the Commission under Section 63 of the Act;

Adjustment for ATSC (during True-Up) = (Actual ATSC paid by LTTC - ATSC as adopted by the Commission) or nil whichever is lower.

(2) The Commission shall approve yearly 'Base Transmission Capacity Rights' as average of "Yearly average of daily max InSTS drawal" and "Yearly max InSTS drawal" for Distribution Licensee(s) and Indian Railways as projected for the respective year of the Control Period, representing the 'Capacity Utilisation' of Intra-State transmission system and accordingly determine 'Intra State Transmission Tariff, in accordance with the following formula:

Base Transmission Capacity Rights

$$(\text{Base TCR}) \text{ for the respective year} = \sum_{u=1}^n ([X + Y]/2)$$

Where,

X = Yearly average of daily max InSTS drawal of respective year for each Distribution Licensee or Indian Railways (u) as the case may be;

Y = Yearly max InSTS drawal of respective year for each Distribution Licensee or Indian Railways (u) as the case may be;

Note: The X & Y shall reflect drawal of Distribution Licensee(s) (including drawal of power from Distribution Licensee by part Open Access Consumer) or Indian Railways, as the case may be, and same shall be exclusive of drawal of power by Open Access consumers.

(3) The Annual Transmission Charge payable by Distribution Licensees and Indian Railways shall be computed in accordance with the following formula:

$$ATC(u) = TTSC \times ([\text{Base TCR}(u)] / \sum_{u=1}^n [\text{Base TCR}(u)])$$

Where,

ATC(u) = Annual Transmission Charges to be shared by Distribution Licensees and Indian Railways (u) for the year:

Provided that the Base Transmission Capacity Rights for Distribution Licensees and Indian Railways for ensuing year shall be determined based on the projections of 'X' and 'Y' after taking into account available data of past years:

Provided further that projections of Base TCR for the ensuing year, shall be submitted by the Distribution Licensees and Indian Railways to the STU latest by last week of August of current year:

Provided that Open Access Customer other than the Distribution Licensee and Indian Railways shall be billed at ₹/kWh as provided in clause 29 (4) of this Regulation:

Provided further that in case of a Distribution Licensee(s) and Indian Railways whose monthly 'X' and 'Y' data is not available for prior 12 months at the time of determination of Base TCR, the monthly 'X' and 'Y' data if available for at least 4 months, or the quantum of Open Access applied by the Distribution Licensee and Indian Railways for the available period, shall be considered in *lieu* of the average monthly 'X' and 'Y' for calculating the Base Transmission Capacity Rights:

Provided further for True-up of respective year of the Control Period of these Regulations, the Base Transmission Capacity Rights shall be determined based on the actual data of 'X' and 'Y' of the Distribution Licensees and Indian Railways as per the data received by Distribution Licensee (s)/ Indian Railways from SLDC. The said data, after deduction of drawal of Open Access consumer (s), shall be forwarded by the Distribution Licensee(s) and Indian Railways to the State Transmission Utility (STU).

(4) The Open Access Customers other than Distribution Licensees and Indian Railways shall pay Intra State Transmission Tariff (in INR/kWh) in terms of actual energy consumed which will reduce the TTSC of the Intra-State transmission system:

Provided that the intra-State transmission tariff for Open Access Customers other than the Distribution Licensee(s) and Indian Railways during a particular year of Control Period shall not increase by more than 15% of the applicable transmission tariff determined by the Commission for the preceding year.

(5) Intra State Transmission Tariff for each Year shall be determined as ratio of approved TTSC for Intra-State transmission system and approved 'Base Transmission Capacity Rights' and shall be denominated in terms of "INR/MW/Year" (for Distribution Licensees) or in terms of "INR/kWh" (for Open Access Customers other than the Distribution Licensees and Indian Railways) in accordance with the following formula:

Intra State Transmission Tariff for Distribution Licensees and Indian Railways:

Intra State Transmission Tariff for Distribution Licensees and Indian Railways in INR/MW/Year
= TTSC / Base TCR

Intra State Transmission Tariff for Open Access Customers other than Distribution Licensees and Indian Railways:

Intra State Transmission Tariff for Open Access Customers other than Distribution Licensee and Indian Railways in INR/kWh

= TTSC / E (Total Energy input at State Periphery for the year)

Where,

TTSC = Pooled cost (in INR per Year) for InSTS for year of the Control Period:

Provided that the energy units transmitted within the State shall be based on the energy input requirement at State Periphery, as projected by each Distribution Licensee as part of its MYT Petition and as approved by the Commission for the ensuing year. Whereas for True- Up period, the energy units transmitted within the State shall be based on the actual energy handled at State Periphery.

(6) The State Transmission Utility shall file the Petition for determination of Intra-State Transmission Tariff along with True-Up and APR on the basis of Base Transmission Capacity Rights of Distribution Licensees and Indian Railways and the summation of the TTSC projected or actual as the case may be, by the Transmission Licensees/LTTCs in accordance with these Regulations.

(7) The Distribution Licensees and Indian Railways shall make monthly payment of Intra-State Transmission Tariff as per Base Transmission Capacity Rights approved by the Commission from time to time.

(8) The charges for Intra-State Transmission usage of excess/shortfall drawal of power shall be treated during true-up in the following manner:

(a) In case of excess drawal of power from the Base Transmission Capacity Rights approved by the Commission, the charges for excess power drawal shall be payable by Distribution Licensees and Indian Railways along with carrying cost at 1-year SBI MCLR, which shall be adjusted in Total Transmission System Cost of the year:

Provided that in case of drawal of power lower than the Base TCR, the transmission charges corresponding the projected Base TCR as approved by the Commission shall be considered.

(9) In case of any variation in projected & Trued-Up TTSC, such excess/shortfall shall be adjusted in the TTSC of subsequent year along with carrying cost at weighted average bank rate for the respective year.

CHAPTER 7

RECOVERY OF INTRA-STATE TRANSMISSION CHARGES

30. Billing and Payment of the InSTS Charges

(1) The STU shall be responsible for monthly billing and collection of Intra-State Transmission Charges from the Transmission System Users as per the Tariff Order issued by the Commission from time to time.

(2) The amount so collected by the STU on account Intra-State Transmission Charges shall be kept in a separate account maintained and operated by the STU.

(3) The amount collected on account of Intra-State Transmission Charges by the STU shall be exclusively allocated for the disbursement or adjustment of the Total Transmission System Cost (TTSC) and any remaining amount shall be considered by the Commission during the True-Up.

(4) The Monthly transmission charges of TBCB projects implemented under Section 63 of the Act, shall be adjusted/ credited by the STU to Distribution Licensee after taking into account the monthly invoice issued by TBCB Transmission Licensee to LTTCs and corresponding payment made by LTTCs within five working days from the date of furnishing such information by LTTCs.

(5) The Monthly transmission charges/cost of TBCB projects under Section 63 of the Act, shall be settled by LTTCs as per the terms and conditions of Transmission Service Agreement executed between them.

(6) The Monthly transmission charges of Transmission Licensee under Section 62 of the Act, shall be credited by the STU to such Transmission Licensee as per the Intra-State Transmission Charges determined by the Commission under relevant Tariff Order, within five working days from the date of collection.

(7) All TSU's shall ensure timely payment of Transmission Charges to STU so as to enable STU to make timely settlement of claims raised.

(8) The excess amount, if any, after disbursement of transmission charges, shall be kept by STU in the separate account, to which Commission shall allow the carrying cost at bank rate for the respective year.

(9) In case of any shortfall in collection of transmission charges, the STU shall make disbursement proportionately and such shortfall amount shall be considered in true up along with carrying cost at bank rate for the respective year.

(10) The STU shall make appropriate adjustments in transmission charges on account of short-term transmission charges if received from power exchange(s) by STU/UPPTCL.

(11) The STU shall prepare a procedure for recovery of Intra-State Transmission Charges under these Regulations, which shall be binding on all Transmission System Users and shall submit the same within three months for approval of the Commission.

31. Treatment of Rebate on intra-State Transmission Charges

(1) In accordance with the Uttar Pradesh Solar Energy Policy, 2022, and Data Centre Policy, 2021, the exemption or rebate applicable on Intra-State Transmission Charges shall be treated as specified in this Regulation.

(2) The quantum of energy (in kWh) applicable for rebate and procured shall be considered while computing the total cost of transmission charges attributable to such procurement.

(3) The transmission usage cost corresponding to the energy eligible for rebate shall be added to the Total Transmission System Cost (TTSC) of the Intra-State transmission system for the relevant year of the Control Period, as determined under clause 1 of Regulation 29 to arrive at the Adjusted TTSC.

(4) The Adjusted TTSC shall be allocated among Distribution Licensees and Indian Railways, in proportion to their approved Base Transmission Capacity Rights (Base TCR) for the relevant year:

Provided that Distribution Licensees and Indian Railways shall submit the projected breakup of their total energy (in kWh) for the ensuing year, segregated into solar and non-solar sources, as part of their submissions to the State Transmission Utility (STU).

(5) Based on the transmission tariff in ₹/kWh determined under 5 of Regulation 29, the applicable monthly rebate shall be computed in accordance with the respective policy. The rebate, calculated on the monthly quantum of energy (applicable for rebate) consumed corresponding to per-unit rebate rate (₹/kWh), shall be credited in the monthly transmission charge invoices raised on Distribution Licensee(s) and Indian Railways.

(6) In the event of any deviation between the projected and trued-up Adjusted TTSC, such excess or shortfall shall be reconciled in the Adjusted TTSC of the following year, along with carrying cost at the applicable weighted average bank rate for the respective year.

32. Transmission Pricing Framework

The Commission may, after conducting a detailed study and due regulatory process, change the existing transmission pricing framework to one considering factors such as voltage, distance, direction and quantum of flow based, etc., or the methodology specified by the Central Electricity Regulatory Commission, as the Commission may deem appropriate.

33. Transmission Losses

The energy losses in the Intra-State transmission system, as determined by the State Load Despatch Centre and approved by the Commission, shall be borne by the Transmission System Users in proportion to their usage of the Intra-State transmission system.

CHAPTER 8

GRANT OF SUBSIDIES BY STATE GOVERNMENT

34. Manner of grant of subsidy by State Government

If the State Government requires to grant subsidy to any consumer or class of consumers in the Tariff determined by the Commission, the same shall be provided as per Section 65 of the Act.

CHAPTER 9

MISCELLANEOUS

35. Saving of Inherent Powers of the Commission

(1) Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice.

(2) Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with provisions of the Act, a procedure which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if

the Commission, in view of the special circumstances of a matter or a class of matters, deems it just or expedient for deciding such matter or class of matters.

(3) Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters in a manner, as it considers just and appropriate.

36. Repeal and Saving

Save as otherwise provided in these regulations, Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Distribution and Transmission) Regulations, 2019 and its amendments shall hereby repealed except to the extent of carrying out true up and APR for the period mentioned in these Regulations.

37. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific Order, give directions, not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary or expedient for the purpose of removing difficulties.

38. Power to Amend

The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provision of these Regulations.

39. Power to Relax

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the necessary parties, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

By the Order of the Commission,
SUMEET KUMAR AGARWAL,
Secretary
Uttar Pradesh Electricity
Regulatory Commission.

Annexure-A
Depreciation Schedule for Existing Assets Capitalised on or before 31.03.2025

Description of Assets		Depreciation Rate
A.	Land owned under full title	0.00--
B.	Land held under lease	
(a)	for investment in the land	3.34%
(b)	for cost of clearing the site	3.34%
C.	Assets Purchased New:	
(a)	Building & civil engineering works of permanent character	
	(i) Offices & showrooms	3.34%
	(ii) Temporary erection such as wooden structures	100%
	(iii) Roads other than kutchra roads	3.34%
	(iv) Others	3.34%
(b)	Transformers, transformer (Kiosk) sub-Station equipment & other fixed apparatus (including plant foundations)	
	(i) Transformers (including foundations) having a rating of 100 kilo volt amperes and over	5.28%
	(ii) Others	5.28%
(c)	Switchgear including cable connections	5.28%
(d)	Lightning arrestors	
	(i) Station type	5.28%
	(ii) Pole type	5.28%
	(iii) Synchronous condenser	5.28%
(e)	Batteries	9.00%
	(i) Underground Cable including joint boxes and disconnected boxes	5.28%
	(ii) Cable duct system	5.28%
(f)	Overhead lines including supports:	
	(i) Lines on fabricated steel operating at nominal voltages higher than 66 kV	5.28%
	(ii) Lines on steel supports operating at nominal voltages higher than 13.2 kilovolts but not exceeding 66 kilovolts	5.28%
	(iii) Lines on steel or reinforced concrete supports	5.28%
	(iv) Lines on treated wood supports	5.28%
(g)	Meters	9.00%
(h)	Self propelled vehicles	9.00%
(i)	Air conditioning plants:	
	(i) Static	5.28%
	(ii) Portable	9.00%
(j)	Furniture and Fittings	
	(i) Office furniture and fittings	6.33%
	(ii) Office equipment	6.33%
	(iii) Internal wiring including fittings and apparatus	6.33%
	(iv) Street light fittings	5.28%
(k)	Apparatus let on hire	
	(i) Other than motors	9.00%
	(ii) Motors	6.33%
(l)	I.T. equipment including software	15.00%
(m)	Any other assets not covered above	5.28%

Note: Useful life of the assets shall be derived based on the depreciation rate provided in the above table.

Annexure-B
Depreciation Schedule for Existing Assets Capitalised After 31.03.2025

Description of Assets		Depreciation Rate
A.	Land owned under full title	0.00--
B.	Land held under lease	
(a)	for investment in the land	3.34%
(b)	for cost of clearing the site	3.34%
C.	Assets Purchased New:	
(a)	Building & civil engineering works of permanent character	
	(i) Offices & showrooms	3.34%
	(ii) Temporary erection such as wooden structures	100%
	(iii) Roads other than kutcha roads	3.34%
	(iv) Others	3.34%
(b)	Transformers, transformer (Kiosk) sub-Station equipment & other fixed apparatus (including plant foundations)	
	(i) Transformers (including foundations) having a rating of 100 kilo volt amperes and over	4.22%
	(ii) Others	4.22%
(c)	Switchgear including cable connections	4.22%
(d)	Lightning arrestors	
	(i) Station type	4.22%
	(ii) Pole type	4.22%
	(iii) Synchronous condenser	4.22%
(e)	Batteries	9.00%
	(i) Underground Cable including joint boxes and disconnected boxes	4.22%
	(ii) Cable duct system	4.22%
(f)	Overhead lines including supports:	4.22%
	(i) Lines on fabricated steel operating at nominal voltages higher than 66 kV	4.22%
	(ii) Lines on steel supports operating at nominal voltages higher than 13.2 kilovolts but not exceeding 66 kilovolts	4.22%
	(iii) Lines on steel or reinforced concrete supports	4.22%
	(iv) Lines on treated wood supports	4.22%
(g)	Meters	9.00%
(h)	Self propelled vehicles	9.00%
(i)	Air conditioning plants:	
	(i) Static	4.22%
	(ii) Portable	9.00%
(j)	Furniture and Fittings	
	(i) Office furniture and fittings	6.33%
	(ii) Office equipment	6.33%
	(iii) Internal wiring including fittings and apparatus	6.33%
	(iv) Street light fittings	4.22%
(k)	Apparatus let on hire	
	(i) Other than motors	9.00%
	(ii) Motors	6.33%
(l)	Communication Equipment	
	(i) Radio and High- Frequency Carrier System	15.00%
	(ii) Telephone lines and telephones	15.00%
	(iii) Fibre Optic/OPGW	6.33%
(l)	I.T. equipment including software	15.00%
(m)	Any other assets not covered above	4.22%

Note: Useful life of the assets shall be derived based on the depreciation rate provided in the above table.

Annexure-C**Procedure for calculation of Transmission System Availability Factor for a Month**

- (1) Transmission System Availability Factor for a Calendar Month (TAFM) shall be calculated by the respective Transmission Licensee, got verified and certified by the SLDC and separately for each A.C. Transmission System and grouped according to sharing of transmission charges.
- (2) TAFM, in percent, shall be equal to $(100 - 100 \times \text{NAFM})$, where NAFM is the non-availability factor in per unit for the month, for the Transmission System / sub-system.
- (3) NAFM for A.C. systems / sub-systems shall be equal to:
- $$= \frac{[\sum_{l=1}^L (OH_l \times Cktkm_l \times NSC_l) + \sum_{t=1}^T (OH_t \times MVA_t \times 2.5) + \sum_{r=1}^R (OH_r \times MVAR_r \times 4)]}{THM \times [\sum_{l=1}^L (Cktkm_l \times NSC_l) + \sum_{t=1}^T (MVA_t \times 2.5) + \sum_{r=1}^R (MVAR_r \times 4)]}$$

Where,

I = identifies a transmission line circuit;

t = identifies a transformer / Inter connecting transformer (ICT);

r = identifies a bus reactor, switchable line reactor or Static VAR Compensation (SVC);

L = total number of line circuits;

T = total number of bus reactors, switchable line reactors and SVCs;

R = total number of bus reactors, switchable line reactors and SVCs;

OH = Outage hours or hours of non-availability in the month, excluding the duration of outages not attributable to the Transmission Licensee,

Ckt km = Length of a transmission line circuit in km;

NSC = Number of sub-conductors per phase;

MVA = MVA rating of a transformer / ICT;

MVAR = MVAR rating of a bus reactor switchable line reactor or an SVC (in which case it would be the sum of inductive and capacitive capabilities);

THM = Total hours in the month.

- (4) The transmission elements under outage due to following reasons shall be deemed to be available:

(a) Shutdown availed for maintenance of another transmission scheme or construction of new element or renovation/upgradation/additional capitalization in an existing system approved by the Commission. If the other transmission scheme belongs to Transmission Licensee, the SLDC may restrict the deemed availability period to that considered reasonably by him for the work involved.

(b) Switching off of a transmission line to restrict over voltage and manual tripping of switched reactors as per the directions of SLDC.

(c) Deemed availability may be provided by SLDC in case of Shutdown of a transmission line due to the Project(s) of National Highways Authority of India, Railways and Border Road Organization, including for shifting or modification of such transmission line or any other infrastructure project approved by Ministry of Power or any critical infrastructure project(s) of the State Government as backed by the recommendation of the State Government (Energy Department) highlighting that the infrastructure project is critical one and only the duration of shutdown as approved by the State Power Committee (SPC). SLDC may restrict the deemed availability period to that considered reasonable by it for the work involved:

Provided that apart from the deemed availability, any other costs involved in the process of such shutdown of transmission line shall not be borne by the users of the intra-State transmission system:

Provided further that such deemed availability shall be considered only for the period for which users of the intra-State transmission system are not affected by the shutdown of such transmission line:

Provided also that SPC shall contemplate the shutdown period required for such shifting or modification works on case to case basis in line with the guidelines issued by CEA, if any, so that deemed availability period is not utilised for other than intended purposes.

- (5) Outage time of transmission elements for the following contingencies shall be excluded from the total time of the element under period of consideration:

(a) Outage of elements due to force majeure events such as war, strike riot, floods, earthquake etc. beyond the control of the Transmission Licensee.

(b) However, onus of satisfying the SLDC that element outage was due to aforesaid events and not due to design failure shall rest with the Transmission Licensee. A reasonable restoration time for the element shall be considered by SLDC and any additional time taken by the Transmission Licensee for restoration of the element beyond the reasonable time shall be treated as outage time attributable to the Transmission Licensee. SLDC may consult the Transmission

Licensee or any expert for estimation of reasonable time. Circuits restored through ERS (Emergency Restoration System) shall be considered as available.

(6) Outage caused by grid incident / disturbance not attributable to the Transmission Licensee, e.g. faults in substation or bays owned by other agency causing outage of the Transmission Licensee's elements and tripping of lines, ICTs, etc due to grid disturbance. However, if the element is not restored on receipt of direction from SLDC while normalizing the system following grid incident / disturbance within reasonable time, the element will be considered not available for the period of outage after issuance of SLDC's direction for restoration.

(7) The outage period which can be excluded for the purpose of clause (5) and (6) of this Annexure-C shall be declared as under:

(a) Maximum up to one month by Member Secretary, SPC;

(b) Beyond one month and up to three months after the decision at SPC;

(c) Beyond three months by the Commission for which the transmission licensee shall approach the Commission along with reasons and steps taken to mitigate the outage and restoration timeline.

(8) In case of inconsistency, these regulations shall override any other regulation or code or order thereof issued / passed by the Commission with regard to the deemed availability in respect of Intra-State transmission system.